हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

10 मार्च, 2011

खण्ड-1, अंक-5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 10 मार्च, 2011

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5) 22
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 27
दूसरी बैठक से संबंधित मामला	(5) 30
मुकुन्द लाल नैशनल कालेज, यमुनानगर के अध्यापकों तथा छात्रों का अभिनंदन	(5) 39
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	(5) 39
राज्य में महिलाओं तथा बच्चों के खराब स्वास्थ्य सम्बन्धी	(5) 39
वक्तव्य-	(5) 40
स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	
गैर सरकारी संकल्प-	(5) 46
अन्तर्भौम जल के दोहन को रोकने/नियमित करने सम्बन्धी	
विधायकों को सुविधाएं देने सम्बन्धी मामला	(5) 72

बैठक का समय बढ़ाना (5) 84

विधायकों को सुविधाएं देने सम्बन्धी मामला (पुनरारम्भण) (5) 84

बैठक का समय बढ़ाना (5) 87

गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भण) (5) 87

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 10 मार्च, 2011

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the questions hour.

Utilization of Vacant Land

***90. Smt. Sumita Singh :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government for proper utilization of the commercially precious land vacated due to the shifting of the Court Complex, Session's Court Complex and Jail from old G.T. road in Karnal which is lying without any use at present ?

Revenue Minister (Sh. Satpal Sangwan) : Yes Sir, it has been decided to transfer 4 Acre 7 Kanal 5 Marla land of D.C. Office and Civil Court Karnal of Khasra No. 4971 to HUDA for developing the land. As regards utilization of land of old Jail and Session's Court the matter is under consideration.

The land in Karnal has been allocated by 3 departments. One by Jails and 2 others by Session's Court and other Court also in which the land nearly 4 acre, 7 kanal and 5 marla that of Civil Court has already been transfered to HUDA free of cost. As regards Jail Department's land and Session's Court, there is no proposal from any side that by which department the land will be given. But still, I would like to tell my friend through you, Speaker Sir, that a total area of land which has become vacant on account of shifting of Court Complex is 5 acre and 12 marla. In that Court Complex also there is some part of land which has not been vacated by some departments. So, 4 acres of land has already been given to HUDA. The Session's Court Complex is having 11 Bigha and 19 Biswa land and this Jail department land is having 9 acre, 6 kanal and 12 marla land nearly. Some part of the Jail department's land which was belonging to Municipal Corporation has been transferred to Urban Development Department for construction of Kalpana Chawla Medical College.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, she wants to know whether there is any scheme under consideration of the Government for proper utilization of the commercially precious land which was vacated due to the shifting of the Court Complex ? Do you have a plan with you ?

Shri Satpal Sangwan : Yes Sir, that land has been allotted to HUDA which is developing that area.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। मंत्री जी यह बताएं कि यह जमीन कौन से डिपार्टमैंट की थी, क्या वह जमीन म्युनिस्पिल काउंसिल की थी ? अगर वह जमीन हुडा को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है तो फिर म्युनिस्पिल काउंसिल का शेयर उसमें क्यों नहीं रखा गया ? इतने सालों से वह जमीन खाली पड़ी है। उस जमीन को अब से पहले यूटीलाईज क्यों नहीं किया गया ? हुडा ने उस जमीन का यूटीलाईजेशन करने के लिए क्या प्लान बनाई है ?

Mr. Speaker : Hon'ble Member, once a land has been transferred to HUDA, it is for HUDA to answer as to what they want to do with that land next.

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, अगर म्युनिसिपल काउंसिल की जमीन ट्रांसफर की गई है तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उसमें से कुछ जमीन नगर निगम की भी है जो ट्रांसफर नहीं की गई है ?

Shri Satpal Sangwan : Sir, the land which was of Municipal Corporation, that was a Police Line first, which has been given to Municipal Corporation for the construction of Kalpana Chawla Medical College.

श्रीमती सुमिता सिंह : सर, यह जमीन म्युनिस्पिल कॉरपोरेशन को नहीं दी गई है बल्कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने वह जमीन स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर की है।

Shri Satpal Sangwan : Yes Sir, that has been transfered to Health Department. Firstly, Police line was there.

Water Harvesting and Management of Rain Water

***392. Shri Aftab Ahmed :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) the measures being undertaken for rain water Harvesting/ Management in the State; and

(b) whether there is any proposal to develop such projects at the foothills of Aravali in South Haryana to preserve rain water through such schemes ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Sir, the Government has taken variety of measures for rain water harvesting and its management which are as follows :–

(i) Construction of humps at on various drains.

(ii) Deepening of Lakes and ponds.

(iii) Construction of recharge channels.

(iv) Construction of cross regulators.

(v) Construction of small check dams, earthen dams and other water harvesting structures.

(vi) Construction of precolation embankments, silt detention dams and gully plugging etc.

(vii) Imposition of condition of construction of rainwater harvesting system in licenced residential plotted colonies, group housing colonies, commercial colonies, industrial colonies and cyber cities.

(viii) Making it mandatory to have rain water harvesting system for buildings with a roof top area of more than 100 Sqmtr.

(b) Yes, Sir.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जवाब में जो उपाय बताए हैं, ये ग्राउंड लैवल पर इम्पलीमैंट भी हो रहे हैं या फिर ये बातें केवल पेपर्स में ही हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैंने हम्पस की बात की है। इनके एरिया में उजीना ड्रेन और नूंह ड्रेन हैं। आर.डी. नं0 70200-डाईमैंशन ड्रेन नं0 8, आर.डी. नं0 6500 और 47500 आफ नूंह ड्रेन, आर. डी. नं0 101683 उजीना ड्रेन पर हमने हम्पस क्रिएट किए हैं। इसके इलावा आर.डी. 36000 उजीना ड्रेन जो है उसकी डीपनिंग के बारे हम कार्यवाही करेंगे। इसके इलावा ड्रेनस की डीपनिंग करने की भी हमारी एक प्रपोजल है ताकि बरसात के दिनों में इनमें पानी रुक सके। दूसरा हम इनके क्षेत्र में वाटर बोडीज भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कोटला झील का कल भी मैंने जिक्र किया था कि यह 116 करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो मेवात के लिए लाइफ लाइन का काम करेगी, उसको बनाने का प्रस्ताव हमने बना रखा है। बीबीपुर लेक कुरुक्षेत्र में और ओटू झील सिरसा के अंदर है जिनकी हम डीपनिंग करेंगे तो it will work as a recharging channel. एक मसानी बैराज है जिसको जे.एल.एन. कैनाल से जोड़ दिया गया है। अरावली में शिवालिक फुट हिल्स के अंदर रेन वाटर हारवैस्टिंग के लिए फोरैस्ट डिपार्टमैंट ने 31 करोड़ रुपये की एक परियोजना बनाई है। इस योजना के तहत छोटे-छोटे चैक डैम बनाए जाएंगे जो रिचार्जिंग का काम तो करेंगे ही साथ ही इरीगेशन का भी काम करेंगे। 50 करोड़ रुपये की एक और योजना महेन्द्रगढ़, भिवानी, रिवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात 6 जिलों के लिए है। इसके लिये कुछ पैसा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट और कुछ पैसा फोरैस्ट डिपार्टमैंट लगाएगा यानि दोनों डिपार्टमैंटस मिलकर यह परियोजना बना रहे हैं। जिसके तहत हम वाटर हारवैस्टिंग का काम भी करेंगे, छोटे-छोटे चैक डैम बनाने के साथ-साथ पॉन्ड्स को भी रिहैबलीटेट किया जायेगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने 418 रेन वाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए हैं। 40 रेन वाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर का टारगैट 2010-11 के लिए है। इसके इलावा हुडा ने साइबर पार्कस, कमर्शियल कालोनियों और इंडस्ट्रियल कालोनियों के लिए

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

टोप रेन वाटर हारवैस्टिंग मंडेटरी किया है। छतों पर जो पानी आएगा उसकी हारवैस्टिंग के लिए प्लाट होल्डर्स वह पानी पाइप द्वारा ग्राउंड वाटर में डालने का काम करेंगे। इसी तरीके से हमारी और भी बहुत सी कोशिशें हैं। यह साल हम वाटर कंजर्वेशन के तौर पर मना रहे हैं। हमारा पूरा स्ट्रैस होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजर्वेशन करें।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, the Hon'ble Member wanted to know what is the reality on ground ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको बता दिया है कि इनके क्षेत्र में नूंह ड्रेन और उजीना ड्रेन हैं जिन पर हम हम्पस बना रहे हैं। इसके इलावा मैंने यह भी कहा है कि मेवात की कुछ ड्रेनों की हम डीपनिंग भी कर रहे हैं।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर लो लाइंग एरियाज में बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। क्या मंत्री महोदय जी बताएंगे कि वहां पर ये रेन वाटर हारवैस्टिंग की कोई योजना लागू करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया है कि इस बारे में म्यूनिसिपल कारपोरेशन और कमेटियों को निर्देश दे दिए गए हैं और वे वाटर हारवैस्टिंग का कार्य कर रहे हैं। जहां तक शहरों का मामला है कि जहां पानी भर जाता है वहां पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट पानी निकासी का काम करवाता है। वैसे तो यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी जहां-जहां रिक्वायरमैंट है हम वहां-वहां ड्रेनें भी बनवाते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही हम करते रहते हैं।

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सिरसा की ओटू झील का जिक्र किया है। उस झील की पहले भी खुदाई करवाई गई है और अब पुन: बजट में इसके लिए पैसे का प्रावधान रखा है। ओटू झील की ओरिजनल योजना वहां से जो मिट्टी निकलेगी उससे झील के बांध पुख्ता करने की है और वहां सड़क बनाकर उसे टूरिस्ट स्पोट के तौर पर डिवैल्प करने की है। क्या सरकार ओटू झील की इस ओरिजनल योजना को क्रियान्वित करने पर विचार करेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि इसको चार फिट डीपन करेंगे और जहां तक इसको टूरिस्ट स्पोट बनाने बारे माननीय साथी ने अपने विचार रखे हैं तो इस पर हम विचार कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में उजीना ड्रेन पर आर.डी. नम्बर 30 पर हम्पस बनाने के लिए प्रपोजल बनाई गई थी । माननीय मंत्री जी ने भी उजीना ड्रेन का जिक्र किया है इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वहां हम्पस बनाने पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां तो वहां हम्पस कब तक बना दिये जायेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री यह है कि मंत्री जी ने कोटला झील का भी जिक्र किया है वहां पानी इकट्ठा करने का काम किया है। इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आप 100 एकड़ जमीन एक्वायर करके 116 करोड़ रुपये की लागत की स्कीम बना रहे हो लेकिन वहां के

इलाके के लोगों की मांग कुछ और है विशेषकर नगीना ब्लॉक के लोगों की, नगीना ब्लॉक गुड़गांव जिले में है और पहले भाई आफताब जी के हल्के में पड़ता था। वह मांग यह है कि यह झील 100 एकड़ की बजाय 500 एकड़ में बनाई जाए। क्या सरकार 100 एकड़ की बजाय 500 एकड़ जमीन एक्वायर करके कोटला झील में पानी संरक्षण करने का काम करेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में बताया है कि हम उजीना ड्रेन में आर.डी. 36000 पर डीपनिंग भी करेंगे और हम्पस भी बनवायेंगे। जहां तक माननीय साथी ने 100 एकड़ से ज्यादा जमीन एक्वायर करने की बात कही है तो इस बारे में बताना चाहूँगा कि हम पहले 100 एकड़ जमीन में जल संरक्षण का काम करेंगे और यदि हम इसमें कामयाब हुए तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उजीना और गोच्छी ड्रेन मेरे हल्के से होकर गुजरती हैं। इन ड्रेनों में पानी बहुत कम मात्रा में चलता है। हमारे यहां बुलवाना गांव से पहले घड़ी गांव पड़ता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि बुलवाना गांव में बांध बना दिया जाये तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के सौंद, बंचारी, डाडका और बौराखा आदि गांवों की सिंचाई व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister just note down the suggestion but no need to give reply.

डॉ. विशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पिछली बार बजट सत्र में इन्होंने कहा था कि दादूपुर नलवी नहर का पहला चरण पूरा कर लिया गया है और दूसरा चरण भी इसी साल पूरा कर लिया जायेगा। अब की बार भी इन्होंने यही बात कही है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ जो एक साल का अरसा था उसमें इन्होंने इस नहर के दूसरे चरण के बारे में क्या कुछ किया है ?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister just note down the suggestion but no need to give reply.

Irrigation Water Supply

***481. Shri Mamu Ram :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that there is no provision for getting water for irrigation purposes from Sirsa canal and SYL canal for the villages of Nilokheri constituency; If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to make provision for providing any outlets in the above stated canals for providing irrigation water to the villages of the Nilokheri constituency; and

(b) if so, the time by which the above stated outlets are likely to be provided ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हां, श्रीमान जी। इस विषय में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

श्री मामूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नीलोखेड़ी हल्के से एस.वाई.एल. नहर और सिरसा ब्रांच निकलती हैं उनसे वहां के किसानों को लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि वहां कोई मौगा नहीं है। क्या सिरसा ब्रांच में मौगे लगाकर मेरे हल्के के किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जायेगा ? वहां बरसालू, बैरसल, मणक माजरा और रायपुर आदि कई गांव हैं जिनके किसानों को सिंचाई के लिए कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा। क्या इन गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाने के लिए सरकार विचार करेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इनको सिरसा ब्रांच द्वारा आऊटलेट दिए जायें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र में चौटांग फीडर सिस्टम है जो कि बिलकुल सिरसा ब्रांच के पैरलल चलता है। उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी तकरीबन 476 क्यूसिक है जिसमें तकरीबन 14 चैनल हैं, यदि माननीय सदस्य कहें तो मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। माननीय सदस्य के इलाके में बाहनी और चौटांग जैसे 14 माईनर हैं जिनके अन्दर हम जीरी के सीजन के समय पानी देते हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने एन.बी. की कैनाल को क्रॉस किया था। जब यह कैनाल बनाई गई थी तब से ये पेरेनियल एरिया बन गये हैं। इनका यह कहना है कि इनके बाकी के एरिया को भी हम पेरेनियल बना दें तो यह पॉसीबल नहीं है क्योंकि यह कैरिज चैनल है। दूसरी बात यह है कि वहां आलरेडी स्वीट वाटर अवेलेबल है और पानी की कोई कमी भी नहीं है। इसके साथ-साथ हम ट्यूबवैल्ज़ पर भी बहुत ज्यादा सबसिडी देते हैं और वहां पर अण्डर ग्राऊंड वाटर टेबल भी ज्यादा नीचे नहीं गया है। इसलिए इन सब बातों के मद्देनज़र मैं समझता हूँ कि वहां पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जीरी का समय होता है उस समय हम इस ओर विशेष ध्यान देते हैं और किसी भी प्रकार से पानी की कमी नहीं छोड़ते।

श्री मामूराम : स्पीकर सर, मैं पुन: माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो गांव इसके साथ लगते हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जीरी के समय में पानी न मिलने की वजह से वहां के किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब एन.बी. कैनाल बनाई गई थी तो जो धोपुर माईनर है, साम्भी माईनर है, साम्भली माईनर है, सागा माईनर है, कगीथ माईनर है, चिराव माईनर है और जुण्डला डिस्ट्रीब्यूट्री है ये इतने माईनर्ज़ और डिस्ट्रीब्यूटीज माननीय सदस्य के क्षेत्र में हैं जो पेरेनियल चल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूँगा कि जब चौटांग फीडर से इरीगेशन हो रही है तो फिर दो तरफ से पानी देने का कोई औचित्य नहीं बनता।

Installation of Tube-wells in Ferozpur Jhirka City

***468. Shri Naseem Ahmed :** Will the Publich Health Engineering Minister be pleased to state the number of Tube-wells installed for water supply in Ferozpur Jhirka city during the years 2009 to 2010 togetherwith the names of the places where the aforesaid Tube-wells have been installed alongwith the number of such tube-wells which are presently functioning ?

Excise and Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : 12 Nos. tubewells have been drilled during the year 2009 to 2010 at Doodh Ghati (8 Nos.), Jhir Road Nursery (East and West) (2 Nos.) and Athkuti (2 Nos.). Out of 12 Nos. tubewells, 10 Nos. tubewells are functionig and 2 Nos. tubewells at Doodh Ghati are not functioning.

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूँ कि फिरोजपुर झिरका शहर में पीने के पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। खासकर वार्ड नम्बर 1, 2 और 3 में पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत है। क्या मंत्री महोदय इन वार्डों में पीने के पानी की समस्या का कोई समाधान करेंगी और अलग से ट्यूबवैल लगवाने की व्यवस्था करवायेंगी?

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, I would like the Hon'ble Members to know that already drinking water supply to the town is being supplied from No. 22 Tubewell and there are three boosting stations located at Athkuti, Bandhrod and Sumshudin Park. Approximately 75 per cent area of the town is covered with the water supply system and 25 per cent by sewerage. About Rs. 305 lacs has been approved during the year July 2007 and 80 per cent of this work has already been completed. Six numbers of tube-wells have been commissioned and another estimate costing around Rs. 43.50 lacs has been approved during the year 2010. By 2011, this entire thing will be done.

Mr. Speaker : Naseem Ji, have you understood ?

Shri Naseem Ahmed : Yes Sir.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, you may please continue.

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, Hon'ble Member has not asked but I would like to tell him that these two tube-wells which are not functioning that were due to theft of cable wire. I would also inform the House that out of two, one tube-well has already started functioning and I have also requested the Hon'ble Minister in this regard so that another one will start functioning today itself.

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने कहा है कि ट्यूबवैल नम्बर 2 और 24 सही ढंग से काम कर रहे हैं। यह बात इनकी ठीक है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि वार्ड नम्बर 1, 2 और 3 के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए क्या सरकार की कोई योजना है क्योंकि वहां पर आज यह हालत है कि महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए दूसरे वार्डों में जाना पड़ता है।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मेरी आपसे एक जनरल रिक्वैस्ट है कि अगर किसी माननीय सदस्य द्वारा सप्लीमैंट्री क्वैश्चन अंग्रेजी भाषा में पूछा जाये तो उसका जवाब भी अंग्रेजी भाषा में दिया जाये और अगर किसी माननीय सदस्य द्वारा सवाल हिन्दी में पूछा जाता है तो उसका जवाब भी हिन्दी में ही आना चाहिए।

Smt. Kiran Chaudhary : Hon'ble Speaker Sir, I would like to assure the Hon'ble Member that even while these two tube-wells were not functioning extra care was being taken so that the extra water is being supplied by the other tube-wells. As he is putting it on record and requesting for it start functioning, I will see to it that these two tube-wells will start functioning immediately so that adequate water may be given to the people of the area because our Government is committed to give potable and good water to the residents of Haryana. For what concurrently, we have made this kind of allocation in Budget. In comparison to the year 1999-2005, our budget allocation is ten-fold.

Mr. Speaker : The request is noted please. Hon'ble Members, I have all the respect for my mother language that is Hindi and all of us I am sure have that respect for this language. However, in the world of globalization English is an international means of communication. The questions those have been put before me are all in English. So, we cannot really restrict ourselves to a certain language. Of course, my emphasis would be that all of us try to speak more in Hindi than English.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पलवल के लोहागढ़ गांव में जो बूस्टर बना है उसकी सप्लाई कृष्णा कालोनी से है लेकिन वहां 15-20 साल से पानी नहीं आ रहा है। अधिकारियों के ध्यान में भी यह बात कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से लाई गई है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या मंत्री जी इस बारे में बतायेंगी कि कृष्णा कालोनी में कब तक यह पानी आ जायेगा ताकि बूस्टर में पानी पहुंचे ?

Mr. Speaker : Subhash Ji, your request has been noted down. Since it is a separate question, so, you may send it in writing, The Minister concerned will entertain your request.

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, I assure the Hon'ble Member that whatever his problem is, will be taken care of.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे जिले में रेनीवेल परियोजना के माध्यम से 258 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह हमारी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। रेनीवेल योजना के अलावा जिन गांवों में ट्यूबवेल सैगमैंट स्कीम के तहत पानी दिया जाना है वहां पर भी काफी दिक्कत आ रही है। क्या मंत्री जी इस बारे में बतायेंगी ?

Mr. Speaker : Your request has already been noted.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पंचकुला जिले में बरवाला ब्लॉक के 30-32 गांव हैं वहां पर पिछले काफी समय से

7-8 ट्यूबवैल ही काम कर रहे हैं बाकी 20-22 गांवों के ट्यूबवैल काम नहीं कर रहे हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगी कि ये कब तक ठीक हो पायेंगे और अगर ये ठीक नहीं हो पाते तो क्या नए ट्यूबवैल लगाये जायेंगे ?

Mr. Speaker : Mr. Bansal, you may give in writing about the tube-wells which are not functioning. As it is a separate question, so give it in writing. Minsiter will see that the tube-wells do function. (Interruption) On one question there have been eight supplementaries. If you will ask as many supplementaries, you will lose other questions. My request is that do not ask more than three supplementaries on one question because most of the question which the Hon'ble Members want to ask remain unanswered.

Does this House have a consensus that more than three supplementaries normally should not be asked ? Will everybody agree ?

Voices : Yes. (Interruption)

Mr. Speaker : I said "normally". If it is a very important question, I would allow but if I allow ten supplementaries on one question then you will lose because the last questions will remain unanswered. So, the consensus of the House is which may be noted that more than three supplementaries would not be asked. (interruption)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, महत्वपूर्ण प्रश्न तो लगते ही लास्ट में हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा सप्लीमैंट्री पूछे जाने की वजह से बाद के प्रश्न रह जाते हैं। केवल 7-8 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है चाहे आप 20-20 सप्लीमैंट्री पूछें लेकिन सिर्फ दो क्वेश्चन आंसर होंगे। हाउस की कंसैंस यह है कि एक प्रश्न पर केवल 3 से ज्यादा सप्लीमैंट्री न हों। Will everybody agree to this ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : O.K. Only three supplementaries are allowed. If the Speaker thinks that there are very important supplementaries, apart from the third, that will be allowed.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसको 3 स्पलीमैंट्रीज तक ही सीमित मत करो। जरूरत हो तो ज्यादा भी पूछी जा सकती हैं।

Mr. Speaker : You leave something to my judgement also. O.K. If it is a very important supplementary, I will allow it but normally restrict yourself even two-three supplementaries. O.K. That is a rule also but in order to entertain lot of members I allow it but you can see that how the questions are lost. Questions are the property of the House and they should not be lost.

Construction of Dam

***558. Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that a dam is proposed to be constructed in village Chhamla of Morni Block to supply the water for which the Public Health Department has deposited Rs. 5 lac with the Forest Department; if so, the time by which the construction work of the aforesaid dam is likely to be completed ?

आबकारी एवं कराधान मन्त्री (श्रीमती किरण चौधरी) : नहीं श्रीमान। (लेकिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वन विभाग के पास 5.50 लाख रुपये बाहरी सतह/उप सतह जल संग्रहण ढांचों के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान हेतू केवल फिजीबिलिटी स्टडी करवाने के लिए जमा करवाए हैं। जल संचयन संरचनाओं का निर्माण प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट की सफलता पर निर्भर है)।

नहीं सर, साढ़े पांच लाख रुपये फॉरेस्ट डिपार्टमैंट को चैक डैम बनाने की सूटेबल साईटस को आईडैंटीफाईड करने के लिए, फिजिबिलिटी स्टडी के लिए और वाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए हैं जिससे चैक डैम वगैरह बनाये जा सकते हैं।

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया से मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही जाती है लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वह आज बहुत से मामलों में 18वीं सदी में ही है। पीने के पानी की यदि मैं बात करूं तो हमारे एरिया में पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। छामला डैम लगने की लोगों को बहुत आस थी क्योंकि प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा इस बारे में बहुत प्रचार प्रसार किया गया था और कहा गया था कि यह डैम लगेगा। इस डैम से मोरनी ब्लॉक के 90 प्रतिशत गांवों के लोगों को पानी मिलने की उम्मीद है। टिपरा जो की बहुत ऊंचाई पर है वहां पर भी इससे पानी जाना था इसलिए मैं मंत्री महोदया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि छामला डैम को लगाया जाए और इस पर विचार किया जाए। इसी तरह भोज, राजपूरा और बालदवाला पंचायत में लोग और महिलाएं गर्मियों के दिनों में ऐसी जगह जाकर पानी पीते हैं जहां पर जंगली जानवर पानी पीते हैं। वे लोग इस तरह का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से इस बारे में भी गुजारिश करना चाहता था कि यहां पर भी एक आधुनिक डैम लगाया जाए लेकिन इन्होंने तो छामला में भी डैम लगाने से मना कर दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जल को जीवन कहा जाता है इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और वहां पर यह डैम जरूर लगाया जाए।

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है कि पानी की वहां किल्लत है इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगी कि इनके गांव छामला में हम लोग ड्रिंकिंग वाटर धग्गर रीवर से थ्रू प्रोपर ट्रीटमैंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके यहां पर वाटर सप्लाई का जो स्टेट्स है वह 55 लीटर पर कैपिटा पर डे है। लेकिन जहां तक इन्होंने डैम बनाने की बात कही है तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि डैम बनाने के लिए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से फंड्ज आते हैं। इसकी फिजिबिलिटी देखने के लिए हमने फोरैस्ट डिपार्टमैंट के पास फण्ड जमा करवाए हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग जाएगा कि वहां चैक डैम या बांध बन सकते हैं या नहीं। जैसे इरीगेशन मिनिस्टर साहब ने बताया है कि जो इन्होंने करना है वह करेंगे। लेकिन स्पीकर सर, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह जो पैसा है इससे कोई डैम बनाने का कोई भी आश्वासन

नहीं है क्योंकि these are only funds which we received from the Government of India to conduct a feasibility report. यहां पर इरीगेशन मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वैस्ट करूंगी कि जैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारे पास आए तो इसके बाद वे इस पर आगे की कार्यवाही करने की बात करें। But Speaker Sir, I want to make it very clear कि यह डैम नहीं बन सकता। These can only be check dams or some features where water sustainability can be made.

Mr. Speaker : Mr. Pardeep Chaudhary, whether you wants to ask one more question ?

श्री प्रदीप चौधरी : जी हां सर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहता हूँ कि 'प्रगति का नया इतिहास समृद्धि के चार साल' में लिखा है कि सरकार ने मानसून सत्र के दौरान हरियाणा में पानी के व्यर्थ बहाव को रोकने तथा बाढ़ से जान माल की सुरक्षा के लिए घग्गर व इसकी सहायक नदियों पर कम ऊंचाई के जो बांध लगाने की योजना स्वीकृत की है वे हैं - कौशल्या डैम, डगराना डैम, दिवानवाला डैम और छामला डैम जिनकी अनुमानित लागत करोड़ों रुपये में है और जिसकी केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति एवं निपटान हेतु प्रस्तुति की हुई है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने भी यही कहा है।

श्री प्रदीप चौधरी : सर, आप मेरी बात आगे तो सुनो। इस बारे में जो भारत सरकार का जवाब आया है वह मैं आपको बता रहा हूँ। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उसमें लिखा है कि हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला जिले के कालका क्षेत्र में तीन बांध दिवानवाला, डगराना और छामला के निर्माण के संबंध में कोई आवेदन केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह उनका लैटर है।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। हमने केस भेजा हुआ है। (विघ्न)

11.00 बजे **श्री प्रदीप चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह लैटर 2 जुलाई, 2010 का है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, घग्गर स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है। छामला का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डगराना और धीमाना वाले डैम के निर्माण बारे पंजाब सरकार विरोध कर रही है। वे नहीं चाहते कि डैम बने। कौशल्या डैम का कोई विरोध नहीं हुआ इसलिये यह डैम 200 करोड़ रुपये की लागत से बना है। यह बात मै ऑन रिकार्ड कह रहा हूँ। माननीय सदस्य पता नहीं कौन सी चिट्ठी पढ़ रहे हैं। (विघ्न) घग्गर स्टैंडिंग कमेटी के पास यह केस विचाराधीन है, जैसे ही वहां से क्लीयरैंस मिल जाएगी उसके बाद ही हम केस भेज सकते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का जवाब पहले ही इरीगेशन मिनिस्टर साहब दे चुके हैं और बता चुके हैं कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। यह जो पैसा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के पास आया है this is a part of the funds which Govt. of India is giving for sustainability of water.

[श्रीमती किरण चौधरी]

इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब आएगी, तभी कार्यवाही होगी। दूसरी बात यह है कि डैम तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। These are small structures जैसे चैक डैम हैं इस बारे में पहले भी किसी माननीय सदस्य द्वारा इस सदन में प्रश्न किया गया था और उसके बारे में इरीगेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है तो इरीगेशन डिपार्टमैंट के साथ मिलकर चैक डैम या बंध बनाने की योजना हम बना सकते हैं।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि हमने केस भेज दिया है और वे कहते हैं कि हमारे पास कोई केस आया ही नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, यह केस घग्गर स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगी हम काम शुरु करेंगे। माननीय सदस्य बात को ठीक से समझने का प्रयास करें। यह दो स्टेट का मामला है और यदि इसमें एक भी स्टेट ऑब्जैक्शन कर देती है तो काम रुक जाता है। कौशल्या डैम के मामले में कोई ऑब्जैक्शन ही नहीं थी, इसलिए उसका काम पूरा हो गया। इस डैम के बारे में पंजाब सरकार ऑब्जैक्शन कर रही है, जब क्लीयरैंस मिल जाएगी तो हम आगे केस भेजेंगे।

Mr. Speaker : Mr. Pardeep Chaudhary you may pass on the letter to Hon'ble Minister and he will check it.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय प्रदीप चौधरी जी को बताना चाहूँगा कि जो पूरा हमारा इलाका पंचकूला से सिरसा तक का है, उसमें घग्गर डैम बनाने का प्रपोजल था। घग्गर डैम के बारे में पिछली सरकार के समय में भी काम हुआ था और उसकी डिटेल कैप्टन साहब के पास है। वह डिटेल वे किसी समय दे देंगे। मैं माननीय साथी श्री प्रदीप चौधरी जी को बताना चाहूँगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी और उन्होंने इस प्रौजैक्ट को ही कैंसिल कर दिया था। चौधरी बंसी लाल जी ने घग्गर डैम बनाने के लिए कॉलौनाइजर का एक कालोनी का लाइसैंस भी कैंसिल कर दिया था, बाद में चौटाला जी की सरकार आई, इन्होंने मीटिंग की और कालोनी को लाइसैंस दे दिया। इसके अलावा चौधरी बंसी लाल जी ने जो कॉलोनी को कैंसिल करने का नोटिस दिया था, वह केस भी इन्होंने हाईकोर्ट से विदड्रा कर लिया। इन्होंने यह कह कर विदड्रा किया कि घग्गर डैम सिरसा, कैथल और फतेहाबाद इत्यादि को पानी देगा। माननीय सदस्य प्रदीप चौधरी जी को यह जानकारी भी होनी चाहिए।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये हर बार इस तरह की बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या आपने इनको यहां इस तरह की बात करने का लाइसैंस दिया हुआ है ?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, is it relevant ?

श्रीमती किरण चौधरी : सर, जो रैलेवेंट क्वैश्चन था उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन जो मंत्री जी बता रहे हैं वह केवल इसलिए है कि उस डैम का प्रावधान किया गया होगा जो इन्होंने नहीं बनने दिया था।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो नदियों और नालों के लाईसैंस दिये हैं। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय सुरजेवाला साहब यह बता रहे हैं कि इन्होंने डैम का प्रोविजन किया लेकिन चौटाला साहब ने कैंसिल कर दिया।

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सोनीपत शहर में पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। गर्मियों की बात तो छोड़ें वहां हालात यह हैं कि सर्दियों के मौसम में भी लोग सड़कों पर जाम लगाते हैं। पिछले वर्ष भी मुझे इस बारे में मंत्री जी और विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि सोनीपत शहर में पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए यमुना के किनारे रेनी वैल बनाए जाएंगे। यह भी कहा गया था कि कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम में जितना एम.एल.डी. पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी मात्रा बढ़ाई जायेगी या ट्यूबवैल लगाए जायेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस दिशा में कोई प्रोग्रेस है? मैं इस बारे में एक सजैशन भी देना चाहूंगी कि जो मैंने सिंचाई मंत्री से क्वैश्चन किया था अगर वे इस दिशा में सोचें कि रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम लगाया जाए तो वह पानी स्टोर करके उससे पीने के पानी की जो कमी है, उसको दूर किया जा सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर साहब, वैसे तो ये रैलेवेंट क्वैश्चन नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्या को एश्योर करना चाहूँगी कि . . .

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, she was very vociferous on this issue even on Motion of Thanks. So, her concerns should be well noted.

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, being a lady and a first-timer, she is doing well and I must congratulate on the way she is taking up the causes. I would like to put it on record also. If any kind of assurance has been given before I took over, we will certainly look into and have it done.

Construction/Repair of Roads

***505. Shri Ashok Kashyap :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct/repair the 2 km stretch on State Highway from Chogama to Garhi Birbal which was badly damaged due to floods;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads :—

(i) Indri to Ladwa;

(ii) Darad to Karnal; and

(c) if the reply to the part (a) and (b) above is in affirmative the time by which the above said roads are likely to be reconstructed/repaired ?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : (a) & (b) Yes, Sir.

(c) (i) The work of repair of 2 km stretch on Chogama to Garhi Birbal is expected to be completed by 30-11-2011. It will cost Rs. 67.69 lacs.

(ii) The work of repair of road from Indri to Ladwa and Darad to Karnal is expected to be completed by 30-12-2011 & 30-04-2011 respectively, at a cost of Rs. 2713 lacs and Rs. 3014 lacs, total Rs. 5794 lacs. Hon'ble Chief Minister had visited the area. These schemes have been approved and I assure the Member that we will try to complete these roads within the scheduled time.

श्री अशोक कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के इन्द्री की 90 फीसदी सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन सड़कों की मरम्मत कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर नोटिस दें we will get it examined.

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जब से बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधि बना हूँ मैंने पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर महोदय को पत्र लिखकर मांग की है कि मेरे हल्के की चांगरोड से डाढ़ी छिल्लर, लाड से नान्दा, मोड़ी से खेड़ी सन्सनवाल, बलकरा से डाढ़ी छिल्लर, लाड से ढाणी नान्दा, ढाणी ढौला, मेहंडी पराणु से जेवली, बिन्दरावन से पिचोपा कलां, हड़ौदा से उमरवास, हड़ौदी से मेहंदी हरिया, मेहंदी हरिया से पिचोपा खुर्द और पिचोपा कलां और नौरंगा बास राजपुताना से ढाणी गुजराण पिपलवास, हुई से जेवली, गोपी से कैरा रूपा और कल्याणा से पीरबाबा कल्याण की सडकें बनाई जाए। स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को पत्र लिखकर मांग की कि इन सड़कों को बनाया जाए। उन्होंने मुझे कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पत्र लिखो। तब मैंने उनके पास पत्र लिखा। इस बारे में पिछले सत्र मे एक क्वैश्चन भी लगाया था।

Mr. Speaker : Now, what is your question ?

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे उस प्रश्न का जवाब question doesn't arise मिला था। उसके बाद मैंने इस सत्र में अपना प्रश्न इन सड़कों के बारे में दिया तो मुझे लिखित में यह जवाब मिला कि आपको पहले ही जवाब दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या रोड बनाने के लिए हरियाणा के मानचित्र से बाढ़ड़ा हल्के का नाम निकाल दिया गया है।

Mr. Speaker : This is not the question.

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी इन सड़कों में से कोई रोड बनायेंगे ?

Mr. Speaker : Yes, this is the question.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि आदरणीय कर्नल रघबीर सिंह जी ने मुझे पत्र भी लिखा था और मैंने इनके पत्र का जवाब भी दिया था और इन्होंने दूरभाष

पर भी मुझ से बात की थी। जिन सड़कों के नाम इन्होंने बताये हैं वे सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. की नहीं हैं। मैंने इनको यह सुझाव दिया था कि आप इन सड़कों के बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पत्र लिखो और इनका पत्र हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को भेज दिया है। ये हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकतर कच्चे रास्ते थे। जो खेतों के कन्सोलिडेशन पाथ होते हैं, ये वो रास्ते थे तो मैंने इनको यह भी कहा था कि जब नये कन्सोलिडेशन पाथ लेंगे तब इन सड़कों को कंसीडर कर लेंगे। इस बारे में आप कृषि मंत्री से भी बात करें।

राव बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर पूरे जिले की बात करूं तो महेन्द्रगढ़ जिले में एक भी रोड गाड़ी की तो छोड़ो, ऊंट गाड़ी के भी चलने के लायक नहीं है। आपने जो दादरी से कोटपुतली रोड फोर लेनिंग करने का काम किया है उस रोड को छोड़कर कोई रोड ठीक नहीं है। आप चाहे कनीना से अटेली रोड या कोई भी और रोड देखें, वहां सारी सड़कों की हालत बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे एक बार डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ के रोड देखने के लिए वहां विजिट जरूर करें क्योंकि वहां पर एक भी रोड ठीक नहीं है।

Mr. Speaker : No need to reply as this is a request. Hon'ble Minister may accept his invitation.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I accept his invitation.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन के दौरान सिरसा ऐलनाबाद रोड को बनवाने का जिक्र किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने और मंत्री महोदय दोनों ने आश्वासन दिया था कि आप लिखकर दे देंगे तो हम इस सड़क को बना देंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या आपने लिख कर दिया था ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे उप चुनाव के दौरान इन्होंने उस सड़क पर एक बार नहीं बल्कि 10-10 बार आने जाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आप भी वहां गये थे। आपने भी देखा होगा कि उस सड़क की कितनी बुरी हालत है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, 6 सालों तक आप भी वहां रहे हैं फिर इस सड़क की यह हालत क्यों है ? Hon'ble Member please ask the question.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे टाइम में वह सड़क ठीक थी। बारिश आएगी तो सड़कें टूटेंगी। सड़कें बनाने का काम तो सरकार का है। पिछले सैशन के दौरान मुझे आश्वासन दिया गया था कि एक साल में इस सड़क को बना देंगे। अब साल तो दूर उससे भी ज्यादा समय हो गया है लेकिन अभी तक वह सड़क नहीं बनी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस सड़क को बनवाएंगे और यदि बनवाएंगे तो कब तक बनवाएंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले सदन में इस बारे प्रश्न पूछा था इनकी यह बात ठीक है और हमने इस बारे उनको आश्वासन दिया था। अध्यक्ष महोदय, पिछले मार्च, 2010 से माइनिंग एक्टीविटीज पूरे स्टेट के अंदर it has come to a standstill. अब हमने इस सड़क के एस्टीमेट्स एप्रूव कर दिये हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना

चाहता हूँ कि हमने इस सड़क के टैण्डर्ज काल किए हुए हैं और जल्दी ही इस सड़क का निर्माण करवा देंगे। पिछले हफ्ते ही माननीय उच्च न्यायालय ने शायद अगर मुझे सही याद है तो जुलाई 30 तक माइनिंग एक्टीविटीज खोल दी हैं by way of an interim order. पंजाब एण्ड हरियाणा दोनों स्टेट्स में पहले माइनिंग बन्द थी। अब दोनों स्टेट्स में खोल दी गई है जिससे कंस्ट्रक्शन मैटीरियल की कॉस्ट कम हो गई है। हमने इस सड़क के टैण्डर्स काल कर लिए हैं, ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल भी दे दी है और बहुत जल्दी इस सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा।

Mr. Speaker : Mr. Minister, Shri Abhey Singh Chautala ji is smiling at your answer. So, it means that he is satisfied with the answer.

सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 8 तारीख को लगा था लेकिन मुझे समय नहीं मिला। कालांवाली रोड़ जो कि 4 किलोमीटर है। एक साल से यह सड़क उखाड़ी हुई है। अब भी मंत्री जी कह रहे हैं कि 31 दिसम्बर तक उसको बनाएंगे। एक साल पहले हो गया है और एक साल अब ले लिया है। हालांकि यह सड़क 4 किलोमीटर की है और इस पर लागत केवल 14 लाख रुपये आनी है। पहले जब मंडी में फसल आई तो उस समय 4 तो बैल मर गए और दो ट्रैक्टर्स उलट गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि यह 4 किलोमीटर की सड़क है मैंने इस बारे ठेकेदार से बात की थी तो ठेकेदार कहने लगा कि इस पर 60 परसैंट मैटीरियल पुराना ही लग जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप ठेकेदार से नहीं मंत्री जी से बात करो।

सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे इस सड़क को बनवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपका सजैशन नोट कर लिया गया है और इस पर रिप्लाई की जरूरत नहीं है।

Construction of R.O.B.

***611 Shri Pirthi Singh :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state —

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a ROB on the railway crossing of Jind-Rohtak railway line on National Highway No. 65 passing through Narwana city and

(b) If so, the time by which the aforesaid ROB is likely to be constructed ?

Public Works (B&R)Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No Sir, there is no proposal under consideration of the Government to construct a ROB on the railway crossing of Jind-Rohtak railway line on National Highway No. 65 passing through Narwana city.

(b) Question does not arise.

श्री पृथी सिंह नम्बरदार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि दिल्ली-भटिंडा रेलवे लाइन डबल लाईन हो जाने के कारण जींद-रोहतक लाईन पर रेल गाड़ियों का बहुत आना-जाना रहता है जिसके कारण वहां फाटक पर घंटों जाम लगा रहता है। यहां पर उपरि पुल बनाने के लोगों की बहुत पुरानी मांग है इसलिए कृपा करके यह पुल बनवाया जाये ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो जाये।

Mr. Speaker : This is a suggestion, no need to answer.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार हरियाणा नम्बर एक होने की बात करती है लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्र की बहुत सी सड़कें कच्ची हैं जिनकी दूरी लगभग 8-8 और 10-10 कि.मी. की है। मैं इनका नाम भी बताना चाहूंगा कि बाड़ाके से भावना (विघ्न)

Mr. Speaker : Chaudhary Sahib, you may give it in writing because this is not a question pertaining to this question. आप लिखकर दे दीजिए, हम उसको इंटरटेन करवा देंगे।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष जी, आप तो हमारी बात सुन लें दूसरा कोई तो सुनता नहीं है। अगर पलवल को हरियाणा के नक्शे से निकालना है तो बात अलग है (विघ्न)। सरकार कहती है कि हरियाणा नम्बर एक है लेकिन आज भी पलवल के अंदर बहुत सी सड़कें कच्ची हैं। हरियाणा नम्बर एक उस दिन बनेगा जब सभी कच्ची सड़कों को पक्का कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सुभाष जी, आप लिखित में दे देना।

श्री सुभाष चौधरी : ठीक है, सर। (विघ्न)

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सारा विधान सभा क्षेत्र 6 रेलवे फाटकों से घिरा हुआ है। वहां से कोई बीमार आदमी हस्पताल भी टाईम पर नहीं पहुंचता। वहां लम्बी-लम्बी कतारें लग जाती हैं। मैंने पिछले सैशन में क्वैश्चन देकर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि मेरे यहां हसनपुर रेलवे रोड पर फाटक है वहां पुल बनवाया जाये। मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि 11 नवम्बर तक पुल चालू हो जायेगा लेकिन वहां पर आज तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि गोड़दा रेलवे लाईन पर अंडर पास और हसनपुर रोड पर उपरि पुल बनाया जाये ताकि मेरे हल्के के लोगों की समस्या दूर हो सके।

Mr. Speaker : No need to answer, it is just a request.

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पलवल में एक रेलवे लाईन है जिसके कारण वहां घंटों जाम लगा रहता है इसलिए वहां ओवर ब्रिज बनाया जाये यह लोगों की बहुत पुरानी मांग है। यह मांग मैं भी मुख्यमंत्री जी से करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी सुभाष चौधरी जी ने सड़कों की बात उठाई। इनका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र पलवल और पृथला दोनों साथ-साथ हैं तथा मोहना-झायसा रोड दोनों हल्कों के लिए आम रास्ता है। वहां 100 के करीब गांव पड़ते हैं। यमुना के ऊपर जो पुल है उसको भी यही सड़क जोड़ती है इसलिए वहां ओवर ब्रिज अवश्य बनवाया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पलवल और अलावलपुर सड़क पर रेलवे लाईन है जिसकी चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर की है। इस पर ओवर ब्रिज बनाने की हमने मंजूरी दे दी है और इस पर 3500 लाख रुपये खर्च होंगे जिसको 2011-12 में बना दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ पलवल-मथुरा रेलवे लाईन के बारे में कल सदन में चर्चा हुई थी उस समय मेरे पास पूरी जानकारी नहीं थी मैं आज यह जानकारी लेकर आया हूँ। मथुरा रेलवे लाईन पर भी 3500 लाख रुपये की लागत से वर्ष 2011-12 में ओवर ब्रिज बना दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आर.ओ.बी. हसनपुर को भी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी गई है उसका भी जल्दी ही निर्माण किया जायेगा।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि समालखा शहर एन.एच.-1 के दोनों तरफ पड़ता है। वहां एक तरफ इण्डस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ रिहायशी एरिया है। सरफेस एण्ड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कमलनाथ जी से हम और आप वहां अंडर पास बनवाने के लिए मिले थे। क्या वहां कोई अंडर पास बनाने का प्रावधान सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह कहना चाहूंगा कि ये मुझे इस बारे में लिखकर भिजवा दें। मैं इनको भी साथ लेकर इस मामले को पर्सनली परस्यू कर लूंगा।

Mr. Speaker : I may inform the House and share this information with the House that a delegation headed by two Members of Parliament Shri Depender Hooda and Shri Jitender Malik alongwith five MLAs have met the Hon'ble Minister for Surface Transport Shri Kamal Nath Ji. He agreed to re-design for making a provision for under-pass in Samalkha. Thank you. Now, next question please.

Teaching of Science Subject

***531 Shri Rameshwar Dayal Rajoria :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start science classes in Govt. College, Bawal; if so, the time by which Science Classes are likely to be started in the aforesaid college ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir.

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : स्पीकर सर, गवर्नमैंट कालेज, बावल (रिवाड़ी) को बने हुए आज 35 साल हो गये हैं और काफी बड़े एरिया में दूर-दूर तक कोई कालेज नहीं है। इस कालेज में साईंस स्ट्रीम नहीं है, जिससे हमारे साईंस के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पिछले सैशन में भी मैंने यह मांग की थी जिस पर मंत्री महोदया ने यह कहा था कि हम इसके बारे में विचार करेंगे लेकिन आज तक भी इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदया से अपील है कि गवर्नमैंट कालेज, बावल में साईंस की क्लासिज़ चलाई जायें।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस समय हरियाणा प्रदेश में 79 गवर्नमैंट कालेजिज चल रहे हैं। इनमें से 31 कालेजिज में हम एरिया और डिमाण्ड के हिसाब से साईंस स्ट्रीम शुरू करते हैं। रेवाड़ी में चार कालेज हैं जहां पर साईंस स्ट्रीम चलाई जा रही है, जिनमें से एक का नाम गवर्नमैंट कालेज, कंवाली है जिसमें बी.एस.सी., फर्स्ट ईयर में 80 स्टूडैंट्स हैं, सैकण्ड ईयर में 58 और थर्ड ईयर में 9 स्टूडैंट्स के साथ इस कालेज में साईंस स्ट्रीम चल रही है। इसके अलावा गवर्नमैंट कालेज फॉर विमैन, रेवाड़ी में भी साईंस स्ट्रीम चल रही है, के.एल.पी. कालेज, रेवाड़ी में भी साईंस स्ट्रीम चल रही है और अहीर कालेज, रेवाड़ी में भी साईंस स्ट्रीम चल रही है। बावल रेवाड़ी से 20 किलोमीटर दूर है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है जहां पर चार कालेजिज में साईंस स्ट्रीम चल रही है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी कि उनकी यह बात सही है कि इस कालेज को सरकार द्वारा 1980 में टेक-ओवर किया गया था और आर्ट्स और कॉमर्स की क्लासिज़ इस कालेज में चल रही हैं। इस कालेज में आर्ट्स स्ट्रीम में 1002 स्टूडैंट्स हैं और कॉमर्स स्ट्रीम में केवल 147 स्टूडैंट्स हैं। इसके साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों में भी बहुत से ऐसे कालेजिज हैं जिनमें साईंस स्ट्रीम चल रही है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि गवर्नमैंट कालेज, बावल में आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम में स्टूडैंट्स की कम संख्या को देखते हुए और नियरबाई एरिया में काफी कालेजिज में साईंस स्ट्रीम की व्यवस्था होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वहां पर साईंस स्ट्रीम चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता।

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : स्पीकर सर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से पिछले सैशन के दौरान भी मांग की थी लेकिन वर्तमान एकेडमिक सैशन की समाप्ति का समय पास आ रहा है अभी तक भी इस कालेज में लैक्चरर्ज़ की पोस्टें नहीं भरी गई हैं। इस कालेज में लैक्चरर्ज़ की 25 सैंक्शंड पोस्टों में से केवल 12 लैक्चरर्ज़ ही पोस्टिड हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा करने के पीछे कहीं सरकार की इस कालेज को बंद करने की मंशा तो नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदया जी से यह जानना चाहता हूँ कि गवर्नमैंट कालेज, बावल में लैक्चरर्ज़ की खाली पोस्टों को क्यों नहीं भरा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह आपकी डिमाण्ड है ?

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : जी सर ।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि इस समय गवर्नमैंट कालेज, बावल में 23 लैक्चरर्ज़ की पोस्टें सैंक्शंड हैं जिनमें से 12 लैक्चरर्ज़ रेगुलर लगे हुए हैं, 5 गैस्ट टीचर्ज़ हैं और सिर्फ लैक्चरर्ज़ की 6 पोस्टें ही वेकैंट हैं। पूरे प्रदेश में लैक्चरर्ज़ की वेकैंट पोस्टों को भरने के लिए उचित उम्मीदवारों का चयन करने के लिए हमने एच.पी.एस.सी. को रिक्वीजिशन भेज रखी है और जैसे ही वहां से उम्मीदवार उपलब्ध होंगे हम लैक्चरर्ज़ की सभी खाली पोस्टों को भर देंगे।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो दो से ज्यादा सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत न दी जाए। जिसने प्रश्न पूछा है वह अपनी सप्लीमैंट्री पूछे तथा उसके अलावा एक-आध सप्लीमैंट्री और हो जाए। इसके कारण जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वे रह जाते हैं। जो प्रश्न रैलीवैंट नहीं होते वे सप्लीमैंट्री में आ जाते हैं। अगर किसी को ज्यादा प्रश्न पूछने हैं तो वे अपने प्रश्न लिख कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले यह बात हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : The Hon'ble Leader of the House is speaking please.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल जवाब का सम्बन्ध है तो एक प्रश्न पर 2 सप्लीमैंट्री पूछने का अधिकार है। उसके अलावा अगर सप्लीमैंट्री देनी है तो वह अध्यक्ष का निर्णय है, यह उनको देखना है। दूसरी बात जहां तक हमारे साथी रामेश्वर दयाल ने बावल के बारे में सवाल पूछा है तो मुझे इस बात का अहसास है कि बावल का कॉलेज बहुत पुराना है और वहां साइंस की क्लासिज होनी चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूँगा कि वहां पर आप साइंस की क्लासिज शुरू करवा दें । (इस समय मेजें थपथपाई गईं)

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितने सरकारी कॉलेज हैं और कितने सरकारी एडिड कॉलेज हैं और उनमें से कितनों के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, कितनी लैक्चरर्स की पोस्टें खाली हैं और वे कब तक भर दी जायेंगी ?

Mr. Speaker : It is a separate question.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सप्लीमैंट्री है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, बहुत प्रश्न बचे हैं। आपको बोलना है तो ठीक है लेकिन प्रश्न बहुत बचे हुए हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 514

(इस समय माननीय सदस्य श्री आनन्द कौशिक सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया।)

Construction of Road

***577. Dr. Hari Chand Middha :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that Government has accorded approval for construction/ repair of various roads in Jind City, if so, the time by which the work of construction/repair of the said roads is likely to be started ?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. All the approved works are likely to be started by 01-06-2011.

Sir, I will also like to tell my learned friend that one of the construction works we are undertaking on Jind-Rohtak-Jhajjar road of N.H. 71 इसमें जीन्द का पोर्शन 263 से 302 किलोमीटर तक है। इसी प्रकार से गोहाना-जीन्द रोड से नॉर्दन बाई पास

तक साईड ड्रेन, असन्ध-जीन्द रोड 54.60 से 82.84 किलोमीटर तक तथा इसी प्रकार जीन्द-सफीदों रोड से पानीपत-असन्ध रोड तक जो पोर्शन अलग-अलग किलोमीटर्ज में है, इन सबके हमने टैंडर्ज दे दिये हैं और मुझे उम्मीद है कि इन सब का निर्माण हम 1 जून, 2011 तक करवा देंगे। इसके अलावा भी हमारे काबिल दोस्त जो सुझाव देंगे वह लिखवा कर भिजवा दें यानि और भी कोई सड़क होगी तो हम उस पर काम करवा देंगे।

डॉ. हरिचन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ये सभी बातें पिछले सैशन में भी कही गईं, दूसरे सैशन में भी कही गई और अब यह तीसरा सैशन भी आ गया मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ हो पायेगा। मंत्री जी एक बार जीन्द में जाकर तो देखें, जीन्द चारों तरफ से बुरी तरह से डूबा पड़ा है तथा लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। एक बार जो उस रास्ते से आ जाए वह दोबारा उस रास्ते से आता नहीं। परसों बहुत सुन्दर शब्दों में परम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने एक कविता कही, कल आपने भी कही और आज मैं कहता हूँ कि -

गरीब को न सता, गरीब रो देगा,

ऊपर वाले की नजर पड़ी तो दुनिया जहां में खो देगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि गरीबों की सुनो क्योंकि मेरे यहां 80 परसैंट लोग गरीब हैं। मेरे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कहा है कि -

पहले काम लो प्यार से, नहीं होता है तो करो इंतजार से।

इंतजार से नहीं होता तो करो हथियार से।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम हथियार से काम नहीं करेंगे क्योंकि हथियार से काम करना तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का काम है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कई सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य मेरी परमीशन के बिना बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

डॉ. हरिचन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मै आपको बताना चाहता हूँ कि -

हरी पगड़ी वाले तेरी शान है निराली,

जन्म जन्म में तेरी ही सरकार है आने वाली।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश जी हथियार से काम करते हैं। यह बात तो रिकार्ड पर आ गई है। ये बात इन्होंने कही है और ये खुद इस बात को मान रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये हथियार इस्तेमाल करने का पाठ पढ़ाते हैं। यहां तो इनके सदस्य ने बताया है हमने नहीं बताया है। यह इस तरह की शिक्षा देते हैं। (शोर एवं व्यवधान) यहां पर महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है इसलिए कम से कम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी और मिड्ढा साहब उसकी तरफ भी देखें। माननीय सदस्य कहते हैं कि वे कहते हैं कि हथियार इस्तेमाल करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : यह बोलने के हथियार की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. हरिचन्द मिड्ढा : * * *

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Damage to Crops by Neel Gai and Monkeys

***523. Shri Rajbir Singh :** Will the Forest Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the crops of farmers in Mulana Constituency are being damaged by the Neel Gai and Monkeys; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to protect the crops of the farmers from these animals ?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अजय यादव) :

(क) हां, श्रीमान। यह सत्य है कि मुलाना विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसलों को सिर्फ नील गायों द्वारा ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है परन्तु बन्दरों द्वारा नहीं।

(ख) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों अनुसार वन्य जीवों के शिकार पर पाबन्दी लगा दी गई है। परन्तु यदि वन्य प्राणी मानव जीवन या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो गया हो तो अधिनियम की धारा-11(1) (ख) के अन्तर्गत मुख्य वन्य प्राणी वार्डन उसे मारने की अनुमति प्रदान कर सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5138 दिनांक 7-1-1996 द्वारा दिशा निर्देश दिये हैं कि वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) सम्बन्धित पंचायत से नील गाय मारने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन्हें मारने का परमिट जारी कर सकता है।

जहां तक बन्दरों की समस्या का सम्बन्ध है, बन्दरों को समस्या वाले क्षेत्र से पकड़वाकर जंगल में छोड़ा जा रहा है। वन तथा वन्य प्राणी विभाग इनकी संख्या नियंत्रित करने तथा बन्दरों की नसबन्दी करने हेतु विचार कर रहा है।

Welfare Fund of Police Department

***582. Sh. Dharam Singh Chhoker :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the present amount of Police Welfare Fund ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, हां।

Funds Realized for ATMA, RKVY and NFSM

***338. Shri Ram Pal Majra :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether the Agricultural Technology Management Agency (ATMA),

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

National Agricultural Development Scheme (RKVY) and National Food Security Mission (NFSM) Schemes have been started in the state; if so, the funds realized to each scheme/agency separately during the years 2009-2010 and 2010-11 ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) : जी हाँ, श्रीमान जी, राज्य में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था (आत्मा) वर्ष 2005-06 से चल रही है जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) स्कीमें वर्ष 2007-08 से राज्य में क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान इन स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपयों में)

स्कीम	2009-10	2010-11
आत्मा	737.64	647.30
आर.के.वी.वाई.	11,356.00	20554.77
एन.एफ.एस.एम.	3,360.89	2,781.28

Shortage of Doctors in Mahendergarh

***535 Rao Bahadur Singh :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the shortage of doctors in Govt. Hospitals in District Mahendergarh is likely to be met out ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान जी, मई 2011 में चिकित्सकों के चालू भर्ती दौर पूर्ण होने के उपरान्त जिला महेन्द्रगढ़ के सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों को लगा दिया जायेगा।

Sanctioned Posts of Coaches

***369 Shri Sampat Singh :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be plesed to state :

(a) the number of sanctioned posts of Coaches in the Sports Department Haryana togetherwith the number of Coaches working as on today and when the last recruitment of Coaches was made;

(b) the total number of Coaces and their Trainees in Haryana who were awarded with cash prizes by the Haryana Government and total amount thereof in the financial year 2010-2011;

(c) the number of Coaches out of 'B' above belongs to Haryana Sports Deptt; and

(d) whether all the awardee players have been given jobs; if not, the time by which these players are likely to be given jobs ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) :

(क) खेल विभाग, हरियाणा में प्रशिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 353 है। वर्तमान में प्रशिक्षकों की संख्या 273 है। सितम्बर, 2010 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 4 कनिष्ठ प्रशिक्षकों की भर्ती की गई थी।

(ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 में 54 खेल प्रशिक्षकों तथा 170 खिलाड़ियों को कुल 13.23 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिये गये।

(ग) पुरस्कृत 54 प्रशिक्षकों में से 9 प्रशिक्षक खेल विभाग हरियाणा में कार्यरत हैं।

(घ) आज तक 12 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियों के लिए पुलिस में उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ी जब भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, उनकी उपलब्धियों के स्तर को ध्यान में रखकर उन पर विचार किया जाता है।

Shortage of Machinery and Staff

***444. Shri Jagdish Nayar :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the Community Health Centres of Hodel and Hasanpur of Hodel Assembly Constituency there are neither X-Ray Machine nor any other machines in the operation theaters, and also, sufficient staff is not available in the aforesaid Community Health Centres; if so, the time by which the shortage of doctors and staff is likely to be met out and the aforesaid machines are likely to be provided ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होडल में आपरेशन थियेटर नव निर्मित है और अभी संचालित किया जाना है। हसनपुर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक्स-रे मशीन स्वीकृत नहीं है। यहां पर अमले की कमी है। जैसे ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होंगी, आवश्यक अमला लगा दिया जाएगा।

Grant-in-aid to Schools

***477. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Education Minister be pleased to state:—

(a) the percentage of grant-in-aid provided for payment of salaries and other like expenditure to the staff of schools in receipt of grant in aid from the government;

(b) the number of Societies/Schools in receipt of grant in aid from Government who were unable to pay their part of contributions for payment of salaries and other like expenditure to their staff during the financial year 2009-10 and financial year 2010-2011; and

(c) the action taken against the Societies/Schools in receipt of grant in aid from Government who were unable to pay their part of

contributions for payment of salaries and other like expenditure to their staff during the financial year 2009-2010 and financial year 2010-2011 ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) श्रीमान जी, हरियाणा राज्य में निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अमले को वेतन का भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा 75 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

(ख) 20 निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अपने हिस्से का अंशदान उनके अमले का वेतन देने हेतु नहीं दिया जा रहा है।

(ग) विभाग द्वारा 20 विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है 17 विद्यालयों के प्रबन्धन को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं कि क्यों न उनके प्रबन्धन को सरकार के अधीन कर लिया जाये। 3 सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन, नामत: वैदिक पुत्री पाठशाला, अम्बाला छावनी, वैश्य प्राथमिक विद्यालय, मन्डी बहादुरगढ़ (झज्जर), हिन्दू कन्या पाठशाला, सढौरा (यमुनानगर) को पहले ही निलम्बित किया जा चुका है तथा इन विद्यालयों की देखभाल के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

N.O.C. for Sale & Purchase of Property

***376. Smt. Kavita Jain :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state :—

(a) whether it is mandatory to obtain NOC for the sale and purchase of property within the limits of all the Municipal Councils and the Municipal Committees; and

(b) If so, the number of NOCs issued separately by all the Municipal Councils and Municipal Committees of the State after the implementation of this provision ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं श्रीमान जी, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 7-क के तहत अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में एक हैक्येटर से कम खाली भूमि के हस्तांतरण के अलावा नगर समितियों एवं नगरपालिकाओं की सीमा में सम्पति के क्रय-विक्रय के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य नहीं है।

(ख) वर्तमान में, फरवरी 2004 के बाद से, नगरसमितियों एवं नगरपालिकाओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं क्योंकि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 7-क के अधीन यह प्रमाण-पत्र जिला नगर योजनाकारों, जिन्हें अधिनियम के तहत निदेशक की शक्तियां प्रत्यायोजित हैं, द्वारा जारी किये जाते हैं।

Construction of Govt. College in Ellenabad

***442. Shri Abhay Singh Chautala :** Will the Education Minister be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start the construction of a Govt. College at Ellenabad during the current year; and

(b) if not, the time by which the construciton work of the aforesaid college is likely to be started together with the time by which the same is likely to be completed ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी, ऐलनाबाद में राजकीय महाविद्यालय पहले से ही चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Incidents of Buffalo Theft

***541. Master Dharam Pal Obra :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the steps are not being taken by the Govt. and the local administration in regard to theft of buffalos of the farmers particularly in the area of Loharu-Bahal of Distt. Bhiwani;

(b) whether it is also a fact that Sh. Surender Singh Inspector/SHO Bahal Police Station and Sh. Ashok Kumar, Inspector/SHO, Loharu have released the buffalo thieves by taking bribe from them who were caught on the spot by the villagers; and

(c) if the reply to the part (a) and (b) above be in affirmative the steps being taken by the Govt. in this regard ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) नहीं, स्थानीय प्रशासन व पुलिस द्वारा भैंस चोरी को नियन्त्रण करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) यह तथ्य नहीं है कि, श्री सुरेन्द्र सिंह, निरीक्षक थाना प्रबन्धक, बहल और श्री अशोक कुमार, निरीक्षक, थाना प्रबन्धक, लोहारू ने भैंस चोरों को जो मौके पर पकड़े गए थे, उनसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया।

(ग) इस अपराध को नियन्त्रण में रखने हेतू गांवों में लगातार दिन व रात को गश्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त, थाना/चौकियों में प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर तत्काल कानूनी कार्यवाही की जा रही है। कोई भी सूचना जो पशुओं को वाहनों

में ढील बारे प्राप्त होती है उस पर जिला में तुरन्त कार्यवाही करते हुए उस वाहन को रोक कर जांच की जाती है। लोहारू, बहल और बाढड़ा क्षेत्र में विशेषतौर पर ठीकरी पहरा लगाकर पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई। पशु चोरी रोकने हेतू सी.आई.ए. दादरी के संरक्षण में एक विशेष दल गठित किया गया है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Cases Registered under Motor Vehicle Act

87. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise and year-wise number of cases registered under Motor Vehicle Act in the State during last 5 years.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, जिला-वार और वर्ष-वार पुलिस विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये चालानों का विवरण निम्नानुसार है :-

जिला का नाम	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (upto 28.2.011)
अम्बाला	8541	34024	31368	15629	51903	14990
कुरूक्षेत्र	7063	19081	24950	9369	15603	4595
पंचकूला	19235	36453	58641	37921	52439	3610
यमुनानगर	286	12064	21242	17230	18620	7016
कैथल	5565	6447	21128	10673	17792	5534
करनाल	5412	11619	32567	22453	24099	14032
पानीपत	9204	5631	21944	32007	58586	19736
सोनीपत	4878	16572	46758	36851	41476	12898
रोहतक	3099	1707	19046	22042	25483	11306
झज्जर	4574	12024	30771	4908	9730	8776
हिसार	13171	12096	18896	18132	17514	8107
सिरसा	3162	11386	19813	14541	19556	1628

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

फतेहाबाद	1570	4967	7115	6161	3591	2024
जीन्द	1713	3694	7459	9635	3642	827
भिवानी	2731	3172	17519	16085	17079	3628
मेवात	1781	1987	2573	1448	5079	1488
पलवल	1804	12279	12538	7789	3749	1352
नारनौल	2852	7716	8116	4741	3794	3005
रेवाड़ी	2529	3265	3568	3966	4400	2696
गुड़गांव	26040	39646	55791	84937	161257	34471
फरीदाबाद	35734	67584	188320	49951	81639	29951
योग	160944	323414	650123	426469	637031	191670
राज्य का कुल योग	23,89,651					

Details of Loss/Profit to Sugar Mills

88. Sh. Anil Vij : Will the Co-operation Minister be pleased to state the Mill-wise and year wise details of the loss suffered or profit earned by the Sugar Mills of the Cooperative Sector in the State from April, 2005 till date ?

सहकारिता मंत्री (स० हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर है।

विवरण

अप्रैल 2005 से 31-3-2010 तक राज्य की सहकारी चीनी मिलों द्वारा अर्जित लाभ तथा हुई हानि का मिल अनुसार तथा वर्ष अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :-

(रुपये लाखों में)

मिल	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
पानीपत	-807.72	-1834.24	-971.70	+229.08	+478.57
रोहतक	-1023.77	-1584.51	-1175.14	-462.45	-2279.98
करनाल	+549.64	-860.66	-1037.73	+341.71	+419.74
सोनीपत	-949.14	-1419.62	-822.70	-84.76	-251.63
शाहाबाद	+2488.89	+998.85	-318.62	+1932.87	+1024.66

जींद	-902.32	-1093.28	-150.89	-362.97	-837.99
पलवल	+1.79	-1125.32	-454.53	-214.39	-381.37
महम	-486.19	-1268.40	-908.92	-138.42	-821.35
कैथल	-1813.78	-971.20	-1332.83	-173.33	-573.78
गोहाना	-741.24	-1151.69	-177.75	+374.24	-223.80
असंध	--	--	--	-736.19	-1238.86
कुल	-3683.84	-10310.07	-7350.81	+705.39	-4685.79

Loss/Profit to Haryana Roadways

89. Shri Anil Vij : Will the Transport Minister be pleased to state the depotwise and year-wise details of the loss suffered or profit earned by Haryana Roadways in the State from April, 2005 till date ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : श्रीमान जी, हरियाणा परिवहन द्वारा वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010-11 (जनवरी, 2011 तक) तक उठाई गई अनुमानित हानि/अर्जित लाभ की डिपो-वार तथा वर्ष वार ब्यौरा की विवरणी अनुबन्ध 'क' पर रखी है।

अनुबन्ध 'क'

हरियाणा परिवहन को हानि/लाभ

हरियाणा परिवहन को वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010-11 (जनवरी, 2011 तक) के दौरान अनुमानित हानि/लाभ इस प्रकार रही है--

अनुमानित

(अन-रीकंसाईल्ड)

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	डिपो का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (जनवरी 2011 तक)
टाटा							
1	अम्बाला	-571.84	-620.45	-531.86	-1086.50	-1255.33	-971.32
2	चण्डीगढ़	-214.44	-34.06	-456.34	-921.90	-1047.81	-407.58
3	करनाल	-739.85	-739.63	-562.78	-1022.56	-1407.42	-1231.30
4	जींद	-735.77	-871.58	-506.54	-1209.31	-1531.87	-1563.30

[श्री ओम प्रकाश जैन]

5	कैथल	-558.71	-619.13	-353.83	-800.69	-749.66	-1057.90
6	सोनीपत	-697.88	-761.56	-716.72	-1423.59	-1802.73	-1521.40
7	यमुनानगर	-607.64	-551.57	-352.95	-708.72	-983.63	-1155.02
8	दिल्ली	-80.15	-82.39	-200.42	-624.89	-1007.12	-832.73
9	कुरुक्षेत्र	-719.79	-678.61	-401.18	-883.81	-1009.30	-1009.44
10	पानीपत	-268.20	-420.24	-315.20	-559.84	-776.98	-909.03
कुल (क)		**-5094.28**	**-5379.22**	**-4397.82**	**-9241.81**	**-11571.85**	**-10659.02**
लेलेंड							
11	गुड़गांवा	-423.87	-614.47	-517.05	-717.63	-1053.95	-672.91
12	रोहतक	-836.59	-825.54	-576.01	-908.96	-1294.96	-1371.59
13	हिसार	-972.42	-1020.98	-671.53	-1477.22	-1707.39	-1620.01
14	रिवाड़ी	-507.91	-663.54	-537.45	-1024.10	-986.75	-996.47
15	भिवानी	-1312.25	-1259.09	-852.18	-1562.41	-1895.21	-1596.19
16	सिरसा	-676.37	-675.30	-395.42	-918.95	-994.39	-1043.08
17	फरीदाबाद	-495.97	-591.74	-405.19	-1094.82	-1528.36	-1152.55
18	फतेहाबाद	-725.45	-762.26	-616.85	-1089.88	-1373.60	-1201.16
19	झज्जर	-552.44	-585.39	-409.20	-751.12	-1037.91	-1194.59
20	नारनौल	-404.02	-495.89	-345.78	-629.90	-771.10	-765.83
कुल (ख)		**-6907.30**	**-7494.20**	**-5326.66**	**-10174.99**	**-12643.62**	**-11680.89**
कुल योग (क+ख)		**-12001.58**	**-12873.42**	**-9724.48**	**-19416.81**	**-24215.47**	**-22339.91**

दूसरी बैठक से संबंधित मामला

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the Parliamentary Affairs Minister will make a statement.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, पहले आप मुझे अपनी एक बात कह लेने दें।

Mr. Speaker : If it is so good, I will allow but I have already requested the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister to make a statement.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मेरा जीरो ऑवर में ही एक सुजैशन है।

Mr. Speaker : Next you will speak, but let the Hon'ble Minister to make a statement first please.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, उसके बाद तो मुझे अपनी बात कहने का समय ही नहीं मिलेगा। फिर तो प्रोसीजरल ही आप मुझे बोलने का समय नहीं देंगे।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सर, बजट के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों का ही यह मानना है कि एक सिटिंग आज और हो जाए क्योंकि आज नॉन ऑफिशिएल डे है। सर, आपकी भी और माननीय सदस्यों की यह फरमाइश थी कि नॉन ऑफिशिएल डे को ऑफिशिएल डे में कन्वर्ट न किया जाए और सारे सदस्यों को बजट पर बोलने का समय दिया जाए। सर, अब मैजोरिटी सदस्यों की यह रिक्वैस्ट है कि आज एक और सिटिंग दोपहर के बाद कर लें। सब सदस्यों के लंच का इंतजाम यहीं पर हो जाएगा ताकि आज, कल और सोमवार तीनों दिन बजट के ऊपर लम्बी चर्चा हो जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर सैकिण्ड सिटिंग ही करनी थी तो आपको कल एनाउंस करना चाहिए था। मैम्बर्ज ने उस हिसाब से अपनी तैयारी नहीं कर रखी होगी इसलिए वे बजट पर कैसे बोलेंगे ? सेकिण्ड सिटिंग का कायदा यही है। आप तो जिम्मेवार आदमी हैं। ये तो बगैर जिम्मेवारी की बात कर सकते हैं लेकिन आपको तो सोचना था। अगर सेकिण्ड सिटिंग करनी थी तो आप कल एनाउंस कर देते हमें कोई ऐतराज नहीं था। सेकिण्ड सिटिंग पहले भी होती रही है इसलिए हमें कोई ऑब्जैक्शन नहीं है। अगर आप पहले एनाउंस कर देते तो मैम्बर्ज अपनी तैयारी कर लेते। अब तो मैम्बर्ज निश्चिन्त हो गए क्योंकि आज तो नॉन ऑफिशिएल डे था और उसी रैजोल्यूशन पर उन्होंने बात करनी थी। उसी पर वे तैयारी करके आए हैं। अब यह कैसे संभव होगा ? कल ये सेकिण्ड सिटिंग कर लें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, एक कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहुत से सदस्यों से रिक्वैस्ट आयी है। इसमें क्या ऐतराज है? मैजोरिटी सदस्यों से रिक्वैस्ट आयी है। हम तो खुले दिल से टाईम देने लग रहे हैं लेकिन इसमें भी चौटाला साहब को ऐतराज है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर साहब, आप कल सेकिण्ड सिटिंग कर लें हम तैयार हैं लेकिन इनको एक दिन पहले इस बारे में बताना तो चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये इस पर भी ऐतराज कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा नेता विपक्ष ने कहा है कि इन्होंने तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं। आज हम सैकिण्ड सिटिंग कर लेते हैं हमारी साईड से बोलने वाले आज बोल लेंगे और इनके सदस्यों को कल बोलने का समय दे देंगे। ये कल तैयारी करके आ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार तो आपका है कि कौन बोलेगा। ये तो वैसे ही दखल दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कल सैकिण्ड सिटिंग कर लें। 14 और 15 को भी सैकेण्ड सिटिंग कर लें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहें तो सैशन और ज्यादा लम्बा बुला लें। क्या दिक्कत है। ये इजरायल चले जाएं इसमें क्या दिक्कत है सैशन तो इनके पीछे भी चलता रहेगा।

Mr. Speaker : Alright, I have heard both sides. As per Rules of Procedures & conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, the Speaker can take the sense of the House with regard to fixing of time. Hon'ble Members, is it the pleasure of the House that the House shall meet for second sitting today at 3.50 P.M. ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस पर हमें ऐतराज है। आप कल डबल सिटिंग कर लें। यह जो प्रोग्राम है यह आपने बी.ए.सी. की रिपोर्ट में तय किया है। (शोर एवं व्यवधान) हम तो कहते हैं कि आप कल डबल सिटिंग कर लो, हो सके तो शनिवार और रविवार को भी कर लो। 11 तारीख को दो सिटिंग कर लो, 14 को दो सिटिंग कर लो, 15 तारीख को दो सिटिंग कर लो। कल आपने कहा था कि कल नॉन ऑफिशियल डे है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको दूसरे सदस्यों के बोलने पर भी ऐतराज है। बी.जे.पी. के साथी बोल लेंगे। (शोर एवं व्यवधान) चौटाला जी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते थे तो बजट पेश होने के तुरंत बाद ही चर्चा शुरु हो जाती थी। (शोर एवं व्यवधान) Is it correct? (शोर एवं व्यवधान) आप तो एक सिटिंग में डिस्कशन करवा कर बजट पास करवा दिया करते थे। हम तो फिर भी चार-चार सिटिंग कर रहे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप रिकार्ड निकलवा कर दिखायें इस बारे में। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है पहले हाउस को सूचित किया जाता है। मान लीजिए उसी दिन शुरु हुआ होगा लेकिन ऐजेंडा में तो था। आप इस बारे में कल ही अनाउंस कर देते। सर, आप 11 मार्च को डबल सिटिंग करो, 14 को करो, पूरा सैशन चलाओ। लेकिन यह बात गलत है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय चौटाला साहब ने एक सिटिंग मार्च, 2000 में कराई है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उस समय नयी सरकार बनी थी और दो महीने के लिए लेखानुदान लिया था। बजट नहीं हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फरवरी, 2004 में भी दो सिटिंग की हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लेकिन उसके लिए ऐजेंडा में तो प्रावधान होता है। ऐजेंडा में जिक्र तक नहीं है and at the eleventh hour यह चेंज किया गया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बी.ए.सी. की मीटिंग होनी चाहिए थी, वह किस लिए बना रखी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : सर, इस तरह से तो नये सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिल ही नहीं सकेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : नये सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाएगा। आप मंडे को दो सिटिंग कर लो। चाहें तो सैटरडे को भी सिटिंग रख लें।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, जब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने बजट पेश किया है इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, सही मायने में तो सरकार विपक्ष का मुकाबला कर पाने में सक्षम ही नहीं है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। विपक्ष ने तैयारी नहीं की इसलिए ये आज ही बजट पर चर्चा कराना चाहते हैं और हरियाणा की जनता को धोखा देना चाहते हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो कल ये डबल सिटिंग करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सत्तापक्ष चर्चा करवाना चाहता है और विपक्ष भागना चाहता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : किस बात के लिए भाग रहे हैं। जितने दिन मर्जी सैशन चलाओ। यदि डबल सिटिंग करनी थी तो हमें कम से कम कल तो कह देते, ताकि हम तैयारी करके आते। हमें तो यह था कि कल नॉन ओफिशियल डे है। कल कह देते कि कल बजट पर चर्चा होगी तो हम तैयारी के साथ आते। बी.ए.सी. की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें आज का दिन नॉन-ओफिशियल डे डिक्लेयर किया गया है और बजट पर चर्चा करने के लिए 11 तारीख का दिन आपने मुकर्रर किया। उसी बात को हम कह रहे हैं कि 11 तारीख को आप बजट पर चर्चा शुरू करें और जितने दिन मर्जी चला लीजिए हम तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप एजैण्डा के अगैंस्ट निर्णय कैसे लेंगे। इन्होंने कल यह बात नहीं कही। आप कल सैकिण्ड सिटिंग कर लें या सोमवार को कर लें। आखिर एजैण्डा को इस प्रकार रोज कैसे बदल पायेंगे। आपके होते हुए हम यह उम्मीद नहीं रखते कि एजैण्डा के अगैंस्ट कोई निर्णय लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, it is not the change of agenda. We have not converted it. We only requested to you, Sir. (Interruptions) आदरणीय चौटाला साहब ने भी कहा था कि नॉन ओफिशियल डे कन्वर्ट मत कीजिए। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार के समय में नॉन ओफिशियल डे कभी नहीं किया। हमने कहा नॉन ओफिशियल डे में कोई दिक्कत नहीं आप कीजिए। हमने तो यह कहा है कि आज एक और सिटिंग हो जाए और बजट पर बहस हो जाएगी इसमें इनको क्या दिक्कत है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत ब्यानबाजी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अरोड़ा साहब, आप बिजनैस एडवाईजरी कमेटी के सदस्य ही नहीं हैं, जो बी.ए.सी. के सदस्य हैं वे तो ये बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब सदन में बी. ए.सी. की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसमें विधान सभा की तरफ से जो प्रोग्राम गया हुआ है उसमें स्पष्ट है कि 11 तारीख को बजट पर चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक दिन बजट पर चर्चा और हो जाएगी तो क्या है। अगर विपक्ष के साथी नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिये इसमें क्या दिक्कत है।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि एक दिन बढ़ाओ हम कहते हैं कि दो दिन सदन का समय बढ़ाया जाए। आपकी सुनने की हिम्मत चाहिए। आप तो सुन नहीं सकते आप तो एक मिनट में खड़े हो जाते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप 11 तारीख को बजट पर बहस शुरू करके जितना मर्जी चलायें हम इसके लिए तैयार हैं।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक सिटिंग बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि दो या चार सिटिंग बढाओ, आप में सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि शनिवार को भी सैशन बुलाओ।

Mr. Speaker : Saturday is my wedding anniversary.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको बधाई हो। कार्यवाही भी चलेगी, रात को आप डिनर भी खिलाओगे।

Mr. Speaker : Hon'ble Members are you ready to listen me ? (Interruptions).

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, बजट में पूरे साल का प्रदेश का लेखा-जोखा होता है और उसमें बड़े लेखे-जोखे मिलाने होते हैं। किसी पर नुक्ता-चीनी करने से पहले उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। आज का दिन नॉन ओफिशियल डे अनाउंस हुआ था।

Mr. Speaker : But you have promised me that you will not speak on Budget if I let you speak on Governor's Address.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि सरकार के घोटाले और घपले हम तभी बता सकेंगे जब उन लेखे-जोखों को हम देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : रामपाल जी, आप मुझे यह बताईये कि क्या आज बजट पर डिस्कशन शुरू होना है।

श्री रामपाल माजरा : नहीं होना सर। अभी तक तो है नहीं। पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी बताया है। हम तो कल के लिए सोच रहे थे।

श्री अध्यक्ष : किसी भी हाउस में अगर अपोजीशन एक डिसकशन को करटेल करना चाहती हो तो क्या यह अच्छा सिगनल है ?

श्री रामपाल माजरा : नहीं सर। ये डिस्कशन करवाने में जल्दबाजी कर रहे हैं ताकि हम से कुछ बातें छूट जायें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It will entirely send a wrong signal about you. (Interruptions). Don't send this signal.

श्री रामपाल माजरा : हम तो कल के लिए भी और परसों के लिए भी चाहे तो सण्डे के लिए भी बजट पर डिस्कशन के लिए तैयार हैं।

Mr. Speaker : Majra Ji, you are a good parliamentarian. If the Members of the House want to discuss continuously for two days, you should welcome it. (Interruptions).

श्री रामपाल माजरा : सर, आपको इस बारे में कल बता देना चाहिए था और कल ही आज के नॉन ओफिशियल डे को ओफिशियल डे में बदल देते। नॉन ओफिशियल डे कोई जरूरी नहीं था।

Mr. Speaker : Since you have more experience than I.

श्री रामपाल माजरा : सर, ये जान बूझ कर षडयन्त्र के तहत ऐसा कर रहे हैं। यह बात ये अब बता रहे हैं जब 12 बजने वाले हैं और इनको पता है कि सैशन डेढ़ बजे खत्म होना है।

Mr. Speaker : I have to suggest you that it will send a wrong signal against you.

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रोंग सिगनल नहीं जा रहा है। आपको एक दुविधा है।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई दुविधा नहीं है।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : आप लीगली तो मानकर चलते हो कि एजैण्डा जो अलॉऊ कर दिया गया है उसके अगेन्स्ट कोई फैसला नहीं हो सकता। आप इस बात को समझते हो लेकिन आप इधर देख रहे हो और डर रहे हो आपको कोई चिन्ता हो रही है। आपको दुविधा में नहीं रहना चाहिए। आपका फैसला इस कुर्सी के मुताबिक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह चेयर पर और चेयर की गरिमा के खिलाफ ऐस्पर्शन है। अध्यक्ष महोदय किसी से नहीं डरते। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी को कहें कि ये अपने लफ्ज वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ये अपने शब्द वापिस लें।

Mr. Speaker : He will take his words back.

Shri Bhupender Singh Hooda : He can't say like this to the Chair. Everybody should have the respect to the Chair.

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मैं किससे डरता हूँ ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप पण्डित चिरंजीलाल शर्मा जी से डरते हो।

श्री अध्यक्ष : आपने यह कहा कि मैं डरता हूँ, आप यह शब्द वापिस लें। (विघ्न) आप इस दुविधा जैसे शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं ? आप डरने वाले शब्द को वापिस लेते हैं या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको एक दुविधा है .....

श्री अध्यक्ष : आप पहले डर वाले शब्द को क्लीयर कर दो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप किसी से डरते हो क्या ?

श्री अध्यक्ष : आपने कहा है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, लगता तो ऐसा है।

श्री अध्यक्ष : आपको लग रहा है ? चौटाला साहब, आप अपने शब्द वापिस लेते हैं या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं तो अपने शब्द वापिस ले लूंगा।

Mr. Speaker : These words may be taken back.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपको दुविधा में नहीं रहना चाहिए। आज एजैंडे के मुताबिक यदि सदन की कार्यवाही चलती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी कि आप उसमें चेंज करते लेकिन आप कल अनाउंस कर सकते थे। दिक्कत तो यह है कि एजैंडे में क्लीयर तो यह किया गया था कि 11 तारीख को बजट पर बहस होगी। 10 तारीख को यानि आज बजट पर बहस होती है तो क्या यह इलीगल नहीं है ? वैसे तो आपको पावर है और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हाउस के कस्टोडियन हो लेकिन आपको अपना फैसला बदलने में संकोच होगा या नहीं। मैं तो अपने लफ्ज वापिस ले लूंगा परन्तु लोग क्या कहेंगे। आपको यह भी तो सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : *"बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।'*

लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे।
यह भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशां क्यों हो।
उंगुलियां उठेंगी इन सूखे हुए गालों की तरफ।
और कई तनजे कसे जायेंगे इन बालों की तरफ।
उनकी बातों का जरा सा भी सबब मत लेना।
लोग जालिम हैं खुद ही समझ जाएंगे।"

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आपकी पोजीशन को सेफ करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसी दुविधा आपके सामने न आ जाए। हम आपकी पोजीशन को खराब नहीं करना चाहते हैं।

Mr. Speaker : Chautala ji, I am the Speaker of this House and I am very safe on my seat.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहूँगा और कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिस पर विपक्षी साथियों को एतराज हो। बिजनैस एजवाइजरी कमेटी का एजैंडा, जिसमें चौटाला जी भी सदस्य हैं, उसमें निर्धारित हो गया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उस पर भी मेरी सहमति नहीं थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अब मैंने क्या एतराज वाली बात कह दी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे बी.ए.सी. की मीटिंग पर भी सहमति नहीं थी। मैं उस मीटिंग में से वॉक आउट करके आया था। सदन में जो बी.ए.सी. की रिपोर्ट रखी गई थी, उसमें 11 तारीख को बजट पर बहस का निर्णय लिया गया था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात ठीक है कि कल भी बजट पर चर्चा है और सोमवार को भी बजट पर चर्चा है। बहुत से सम्मानित सदस्य मुख्यमंत्री महोदय को मिले थे और उन्होंने कहा कि बजट पर दो दिन चर्चा है एक दिन और हो जाए परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि वीरवार को प्राइवेट मैम्बर्ज डे है। अब तो माजरा जी ने कह दिया कि मेरे रैजोल्यूशन को खत्म करके कंवर्ट कर लो। ये तो हमेशा ऐसा करते रहे हैं लेकिन हमारी मंशा उनके रैजोल्यूशन को खत्म करने की नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो क्योंकि यह एक गम्भीर विषय है। Speaker Sir, the House has approved by majority the agenda of the Business Advisory Committee for holding discussion on Budget for two days. We are saying that let us have two days discussion. That is all, Sir. (Interruption). Why are they running away ? Why are they shying away for more discussion ? Why are they shying away ? why are they afraid for more discussion, when more Members will get a chance to speak, Sir ? (Interruption). Speaker Sir, with the sense of the House, any decision of Business Advisory Committee can further be ordered. (interruption).

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये बार बार घुमा फिरा कर वही बात कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि बजट पर 4 दिन डिस्कशन हो, 8 दिन डिस्कशन हो परंतु आज की बजाय कल सैकिंड सिटिंग कर लो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हाउस ने बी.ए.सी. की रिपोर्ट को मान लिया था लेकिन उसमें तो यह था कि बजट पर बहस 11 तारीख को होगी। उसमें यह तो नहीं है कि बजट पर बहस 10 तारीख को होगी। अध्यक्ष महोदय, आप अपने किए हुए फैसले को देख लें। मैं बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में से भी वॉक आउट करके आया था लेकिन जब हाउस ने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया है तो क्या हाउस ने कहा है कि बजट पर 10 तारीख को बहस होगी। बजट पर बहस 11 तारीख को होने बारे इसमें लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप सदन की कार्यवाही के मुताबिक निर्णय लें।

Shri Randeep Singh Surjewala : Alright Sir, we will carry on with the same agenda. Let us have shorter discussion on the Budget. (interruption). We will not have the second sitting, Sir. (Interruption) Sir, I bow. Sir I have made an offer on behalf of the treasury benches. I bow. We will continue with the same agenda. (Interruption). इन्होंने कहा और हमने मान लिया। हम एजैंडे पर ही चलेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हम फालतू विवाद में नहीं पड़ेंगे। ये बड़े हैं, ये तजुर्बेकार हैं और हम इनकी बात पर चलते हैं और इन्होंने एजैंडा मान लिया है इसलिए उस पर चलिए और सैकिंड सिटिंग मत करिए।

Mr. Speaker : O.K., we agree with you. (interruption) मैं 15 साल पहले सिगरेट पीता था। मेरी पत्नी आ गई, मैंने सिगरेट फैंक दी। मेरे साथ खड़े मेरे साथी ने कहा, क्या आप अपनी पत्नी से डरते हो। मैंने कहा नहीं, मैं उनकी रिस्पैक्ट करता हूँ इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। मैं सबकी रिस्पैक्ट करता हूँ और मेरी रिस्पैक्ट को डर नहीं मानना चाहिए। मेरे लिए सत्तापक्ष किसी भी सदन का एक महत्वपूर्ण कम्पोनैंट है लेकिन उससे ज्यादा मेरा लोकतंत्र में विश्वास है और मैं विपक्ष को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। (इस समय मेजें थप-थपाई गई।)

लेकिन आज - मयकदे में अजब हादसा हुआ,

जाहिद मेरे हिसाब में पीकर चला गया।

यहां लोग डिस्कशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते (विघ्न) सिर्फ व्यवस्था का प्रश्न है। श्री अशोक अरोड़ा जी let me complete. श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्वयं कहा कि विधान सभा के अध्यक्ष समय फिक्स कर सकते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसा कहा। मेरी फीलिंग यह है और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि सदन जितना ज्यादा समय चले उतना ठीक है लेकिन हमें माहौल को खराब नहीं करना है। अगर आज विपक्ष को डबल सिटिंग पर आब्जैक्शन है तो पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर का बहुत सुंदर सजैशन आया है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष नहीं चाहता है तो डिस्कशन न हो और जो रैगुलर एजैंडा फिक्स है उसी पर सदन चले।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि सदन की सिटिंग बढ़ाई जाए लेकिन आज नहीं कल की डबल सिटिंग कर लें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब हम कहते हैं कि सैशन बढ़ा दीजिए तो आदरणीय चौटाला जी कहते हैं कि मत बढ़ाईये। जब मैं कहता हूँ कि मत बढ़ाईये तो कहते हैं कि बढ़ा दीजिए। इनकी कौन सी बात मानें।

श्री अध्यक्ष : मुझे लगता है कि जो आप कहेंगे वह नहीं मानेंगे। यदि आप न कहते तो शायद ये बढ़वा देते।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, शायद ये बात दुरुस्त है। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सदन में बहुत से नये मैंबर्ज हैं उनको भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले इसलिए कल की डबल सिटिंग कर ली जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सभासदो, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और इस मुद्दे पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत कुण्ठाओं से ऊपर उठकर डिस्कशन होनी चाहिए। बजट किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक सरकार का नहीं बल्कि समूचे स्टेट का होता है इसलिए बजट पर महत्वपूर्ण और हैल्दी डिबेट होनी चाहिए। जैसा एटमोसफेयर आपने सदन का बनाया इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने अच्छा एटमोसफेयर बनाया है उसको कन्टीन्यू करते हुए जहां सरकार की कोई कमी है उसको लेकर आना विपक्ष का काम है लेकिन व्यक्तिगत कुण्ठा, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप न इधर से हों और न उधर से हों ताकि बजट जैसे

महत्वपूर्ण विषय पर अच्छी बहस हो। आप सभी इससे सहमत हैं कि व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगेंगे।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : थैंक्यू।

मुकुन्द लाल नैशनल कॉलेज, यमुनानगर के अध्यापकों तथा छात्रों का अभिनंदन

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मुकन्द लाल नैशनल कालेज, यमुनानगर के छात्र और अध्यापकगण दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। यह सदन जहां इस देश की अगली पीढ़ी के नौजवान युवक और युवतियों को अपनी शुभ कामनाएं देता है तथा वहीं उनके अच्छे भविष्य की कामना भी करता है।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, you have come out with very good information. The youth of this country from the colleges have come to watch to this august House Proceedings. That's a very healthy trend and they will learn a lot. I welcome them on behalf all of you as Speaker of the House.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

राज्य में महिलाओं तथा बच्चों के खराब स्वास्थ्य सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, I have received a Calling Attention Motion notice from Dr. Ajay Singh Chautala, Hon'ble Member and four other MLAs regarding poor health of women and children in the State. I have admitted it. Shri Rameshwer Dayal, Shri Ragubir Singh Badra, Shri Ashok Kumar Arora and Shri Krishan Lal Panwar are co-signatory of this Calling Attention Motion. Dr. Ajay Singh Chautala, MLA may read his notice.

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं (श्री रामेश्वर दयाल, श्री रघबीर सिंह, श्री अशोक कुमार अरोड़ा तथा श्री कृष्ण लाल पंवार, एम०एल०एज०) इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि राज्य के लोगों में भारी रोष तथा असंतोष है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के खराब कार्य तथा अपर्याप्त सेवाओं के कारण महिलाओं तथा बच्चों के खराब स्वास्थ्य के बहुत से उदाहरण हैं। महिलाओं के दयनीय स्वास्थ्य तथा बच्चों में रक्त की कमी के मामले बढ़े हैं। इस समस्या के कारण, बच्चे तथा महिलाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। वास्तव में दिनांक 27.2.2011 के पंजाब केसरी में प्रकाशित योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य के निवासियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पीछे रह गया है। यह स्पष्टतय: सरकार की लापरवाही तथा घटिया कार्यप्रणाली को दर्शाता है। इस गम्भीर समस्या के दृष्टिगत सरकार को सदन के पटल पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

वक्तव्य-

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर,

1. पिछले 5-6 वर्षों के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए वहन योग्य दरों पर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु अनेकों कदम उठाए गए हैं तथा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। यद्यपि सरकार द्वारा लिए गए नीति निर्णयों तथा कार्यवाहियों के पूर्ण रूप से फलीभूत होने में समय लगता है, फिर भी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अति सकारात्मक परिणाम आने आरम्भ हो चुके हैं। भारत सरकार के एस०आर०एस० आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 2000 में 67 प्रति हजार थीं, वह वर्ष 2009 में घटकर 51 प्रति हजार हो गई। इसी प्रकार बच्चों में पूर्ण प्रतिरक्षण दर जो 1998-99 में 63% तथा 2004-05 में 65% थीं, वह वर्ष 2009 में बढ़कर 71.7% हो गई।

2. सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुरक्षित मातृत्व की सुविधाओं को पिछले पांच वर्षों में उच्च वरीयता दी गई है। चौबीसों घंटे प्रसूति सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से मास सितम्बर, 2005 से 406 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को 24x7 प्रसूति गृहों में परिवर्तित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 297 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 111 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी उपमण्डलीय तथा जिला स्तरीय अस्पताल गर्भवती महिलाओं को 24x7 प्रसूति एवं रैफरल सेवायें प्रदान कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप संस्थागत प्रसूतियों की संख्या जो वर्ष 1998-99 में 22% थीं तथा वर्ष 2005-06 में 39% प्रतिशत थीं, वह वर्ष 2010 में बढ़कर 74% प्रतिशत हो गई हैं।

3. सरकार केवल नवजात शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर के बारे में ही चिंतित नहीं है बल्कि 0-18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे भी पूर्ण ध्यान दे रही है। इस वर्ग के आंगनवाड़ी तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य निरीक्षण हेतु मास जनवरी, 2010 से एक नई व अनूठी इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना लागू की गई। इस योजना के तहत पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 29 लाख बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इन बच्चों को आवश्यकतानुसार उपचार भी प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति को जानने के लिए तथा आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु जांच भी की जाएगी।

4. गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं, जटिल प्रसूति मामलों तथा अन्य आपातकालीन मरीजों को अस्पतालों में पहुँचाने हेतु मास नवम्बर, 2009 से हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा संख्या 102 नाम की रैफरल परिवहन सेवा योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत 361 एम्बुलैंस चलाये जा रहे हैं। मास नवम्बर, 2009 से मास फरवरी, 2011 के बीच लगभग 2.79 लाख व्यक्ति इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं जिनमें से 1.16 लाख गर्भवती महिलायें थीं। यह सुविधा गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों की प्रसवोपरांत जटिलताओं के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध है।

5. नवजात शिशुओं के जन्म के 72 घंटों के पश्चात तक का समय उनकी जीवन रक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बीमार नवजात शिशुओं को सामयिक एवं उचित चिकित्सा सहायता

प्रदान करने हेतु सभी जिला अस्पतालों में बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाईयां (SNCU) स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इन इकाइयों में फोटो थैरेपी यूनिटें, इन्क्यूबेटर, रेडिएशन वार्मर इत्यादि उपकरण उपलब्ध होंगे। इन इकाइयों में चौबीसों घंटे डाक्टर तथा नर्सें उपलब्ध करवाने हेतु भी कदम उठाए जा रहे हैं।

6. शायद केवल हरियाणा ही ऐसा राज्य है जहां सभी वर्गों के बहिरंग रोगियों को पूर्ण नि:शुल्क दवाइयां दी जाती हैं। जहां बी०पी०एल० परिवारों से सम्बन्धित सभी रोगियों तथा सभी प्रसूति केसों को बहिरंग के अलावा अन्तरंग मरीजों को भी निशुल्क दवाइयां प्रदान की जाती हैं। सभी अस्पतालों में अति सस्ती दर पर सर्जरी पैकेज उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। सभी वर्गों के रोगियों के लिए नि:शुल्क सिजेरियन सर्जरी का प्रावधान है। ये योजनाएं पिछले दो वर्षों से जारी हैं। इन योजनाओं पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ से अधिक राशि खर्च होती है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों में ओ०पी०डी० रोगियों की संख्या वर्ष 2010 में बढ़कर 1.60 करोड़ हो गई जो वर्ष 2009 की तुलना में 20% अधिक है।

7. काफी अधिक संख्या में लोगों ने अब शहरी क्षेत्रों में निवास करना आरम्भ कर दिया है। शहरी स्लम्स तथा शहरी क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्ष 2009-10 में हरियाणा के विभिन्न जिलों में शहरी आर०सी०एच० केन्द्र खोले जा रहे हैं। मास जनवरी, 2011 तक कुल 86 स्वीकृत आर०सी०एच० केन्द्रों में से 65 आर०सी०एच० केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो चुके हैं, शेष बचे 21 केन्द्र चालू होने की अग्रिम स्थिति में हैं।

8. राज्य में सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु अनेकों अन्य निर्णय भी लिए गए हैं, जिससे महिलाओं एवं बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होगा। इन निर्णयों में डाक्टरों की लगातार भर्ती, तीन नए मैडीकल कालेज खोलना, पी०जी०आई० रोहतक में स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करना, जिला अस्पतालों को अपग्रेड करना, ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों के नये भवनों का निर्माण करना, चिकित्सकों तथा अन्य अमले के कौशल को अपग्रेड करने हेतु उन्हें नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना इत्यादि शामिल हैं।

9. हरियाणा सरकार, राज्य के लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कृत संकल्प है। सरकार द्वारा इस दिशा में अनेकों कदम उठाए गए हैं तथा अनेकों नीतिगत निर्णय लिए गए हैं तथा भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

12.00 बजे **डॉ० अजय सिंह चौटाला (डबवाली)** : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त स्वास्थ्य मंत्री राव नरेन्द्र सिंह जी ने बड़े विस्तार से आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। दूसरी बात ये नौजवान हैं एनर्जैटिक भी हैं और मंत्री बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे होस्पिटल्स में गये भी हैं। मैंने निरन्तर इनकी खबरें अखबारों में भी पढ़ी हैं और देखी भी हैं। मैं यह कामना करता हूं कि ये इसी तरीके से प्रयासरत रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जिन होस्पिटल्स में ये गये हैं उनके कार्य से और उनके रख-रखाव से ये स्वयं संतुष्ट हैं। क्या हरियाणा प्रदेश के सभी होस्पिटल्स में महिलाओं के लिए प्रसूति के लिए उचित व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सुधार की हमेशा जरूरत रहती है। मैं जिन-जिन अस्पतालों में व्यक्तिगत रूप से गया हूं और वहां मैंने जो कमियां महसूस की हैं उनको दूर करने के लिए हमने आदेश दिए हैं। डाक्टर्ज की जहां तक कमी का सवाल है यह समस्या हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज के इस युग के अंदर जहां हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है, हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने आपको स्वस्थ रखा जाए, अपने आपको मेनटेन रखा जाए इसलिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में डाक्टर्ज की ज्यादा जरूरत रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि डाक्टर्ज की कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं मैं समझता हूं कि इससे पहले की सरकार ने कभी नहीं किए होंगे। पिछले दो वर्षों से लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है और डाक्टर्ज की रैगुलर भर्ती जारी है। पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे से इनकी भर्ती प्रक्रिया को इसलिए ही बाहर निकाला गया है ताकि यह लम्बी न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही सोच है इसलिए इस प्रक्रिया को उससे बाहर निकालकर डिपार्टमैंट की कमेटी बनाकर डाक्टर्ज की भर्ती प्रक्रिया को हमने जारी रखा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में 1800 डाक्टर्ज भर्ती किए गए लेकिन इनमें से लगभग 800 डॉक्टर्ज ही ज्वाइन कर सके हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्या आप स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पर कुछ कमियां पायी गयी हैं उनके लिए मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को लिखा है और व्यक्तिगत रूप से भी डाक्टर्ज, सी०एम०ओज०, एस०एम०ओज० को आदेश दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अस्पताल में साफ-सफाई की बात है आप जानते हैं कि आपकी सरकार ने यह फैसला किया है कि सभी अस्पतालों के आउट सोर्स के आधार पर ठेके के आधार पर जो सफाई कर्मचारी हैं या दूसरे कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती की जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा कैथल का अस्पताल बनने जा रहा है उसको हम मॉडल अस्पताल बनाना चाहते हैं क्योंकि उसी पैटर्न पर दूसरे अस्पतालों की भी देखरेख की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 200 से 250 करोड़ रुपये की लागत से दस अस्पतालों का भी अपग्रेडेशन किया है। इसके अलावा हमने उनकी बिल्डिंग्ज को भी ठीक किया है, इक्विपमैंट्स भी वहां पर दिए गए हैं और स्टाफ के सिस्टम को भी हमने ठीक किया है। जहां पहले 29-30 का स्टाफ होता था वहां अब हमने 42 का स्टाफ किया है तथा बड़े अस्पतालों जैसे पंचकूला, गुड़गांव में यह संख्या 55 रखी गयी है। इसी तरह से वर्ष 2011-12 में हम तीन नये अस्पताल रिवाड़ी, दादरी और पानीपत में टेकअप करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कहने का अर्थ यह है कि सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी स्वयं चाहते हैं कि हरियाणा के गरीब लोगों और हरियाणा के रहने वाले निवासियों को स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं मिलें। जैसा मैंने बताया कि हरियाणा देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पर अस्पतालों में मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां दी जाती हैं। यदि कोई भी मरीज अस्पताल में जाता है चाहे वह किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उसको नि:शुल्क दवाइयां दी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसी शुरुआत हमारे राज्य ने की है वैसी कहीं पर नहीं की गयी है। 102 रैफरल सेवा का दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। इसकी 24 घंटे सर्विस है। जो एक्सीडैन्टल केसिज हैं, बी०पी०एल० के केसिज हैं या जो डिलीवरी के केसिज हैं, उन सबको इसमें फ्री रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, इन सबके अच्छे परिणाम आए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि ओ०पी०डी० के अंदर मरीजों की संख्या इंक्रीज हो रही है। माननीय सदस्य का चिंतित होना वाजिब है लेकिन

हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके रिजल्ट और अच्छे आएंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि मैं खुद अस्पतालों की तरफ ध्यान दे रहा हूं तो मेरा खुद का प्रयास है कि मैं जहां पर भी जाता हूं, व्यक्तिगत रूप से अस्पताल चैक करता हूं और कमियों के बारे में डाक्टर्ज को सख्त हिदायत भी देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आगे भी हमारे यह प्रयास जारी रहेंगे। मैं माननीय सदस्य को और सदन को कहना चाहूंगा कि इसके अलावा भी यदि उनके पास और कोई सुझाव हैं तो वह दे दें क्योंकि यह जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष या हैल्थ मिनिस्टर ही जिम्मेवार हो, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इस बारे में सुधार लाएं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से आगे आए और आगे आकर स्वास्थ्य सेवाओं में पूरा ध्यान दे।

Mr. Speaker : You want the Hon'ble Members to visit the hospitals for themselves.

राव नरेन्द्र सिंह : जी हाँ सर, अगर कोई मैम्बर मेरे साथ जाना चाहे तो मैं उसको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा।

Mr. Speaker : Can they go on their own to check the hospitals?

राव नरेन्द्र सिंह : जी हाँ सर, चुने हुए प्रतिनिधि का यह हक बनता है। अध्यक्ष महोदय, हमने तो खुद लम्बे समय तक विपक्ष में रहकर राजनीति की है। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे सरकार को सुझाव दें। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस बात के पक्षधर हैं।

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जो बात जानना चाहता था वह उन्होंने नहीं बतायी। मैंने आपके माध्यम से इनसे पूछा था कि जो डिलीवरी हट्स हरियाणा प्रदेश में बनाई हुई हैं उनमें सब जगहों पर लेडीज डाक्टर्ज और उपकरण की उचित व्यवस्था है या नहीं और अगर नहीं है तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या इसके बारे में मंत्री जी संतुष्ट हैं ? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि वे संतुष्ट नहीं है चलो अच्छी बात है कि वह इस संबंध में प्रयास करेंगे। मेरा भी उनको सहयोग रहेगा, मैं उनको सुझाव भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि इन-इन जगहों पर यहां यह व्यवस्था करवाएं। जो डिलीवरी हट्स बनायी गयी हैं खास तौर पर से ग्रामीण आंचलों में वहां लेडी डाक्टर्ज की कमी है। शहरों के अस्पतालों में और प्राईवेट अस्पतालों में तो इसकी पूरी व्यवस्था होती है। परन्तु ग्रामीण आंचल में जो हमारी पी०एच०सीज० हैं, वहां पर लेडी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं इसकी वजह से ग्रामीण महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने प्रसूति के मामले में जिक्र किया तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो-जो हमारे प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स और सी.एच.सीज. हैं उनके अंदर जो भी नॉमिनल स्टाफ जैसे ए.एन.एम्स. हैं, डॉक्टर्स हैं जितने होने चाहिए उतने हैं। हालांकि डॉक्टर्स की कमी को मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ सभी को इस बात का ज्ञान है फिर भी हम प्रसूति जारी रख रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आपने देखे होंगे कि इन इंस्टीच्यूशंज में 1998-99 में डिलीवरी की संख्या 22 प्रतिशत थी, आज वह बढ़कर 74 परसैंट पर चली गई है। हमारी तरफ से पूरे प्रयास जारी हैं। फिर भी आप ये समझते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है तो डॉक्टर्स की कमी को तो डॉक्टर्स ही पूर्ण करेंगे और कोई वह कमी पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए हम

[राव नरेन्द्र सिंह]

निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जहां तक होस्पिटल्स का जिक्र किया गया तो मैं स्वयं ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. में जाकर पेशेंट्स से मिला हूं, माताओं-बहनों से मिला और कहा कि आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ तो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट किया कि हमें कोई तकलीफ नहीं है और हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the concern shown by the Hon'ble Members of the House is regarding the poor health of women and children particularly their H.B. level that is very poor. It is my personal observation that it may be because of malnutrition and it may be because of any other reasons. As we go for a blood donation camp, you will find that nearly 15 per cent of girls registered for blood donation, their blood is not taken because their H.B. level is very poor. So, my suggestion to the Hon'ble Health Minister is that there should be a random checking of H.B. and blood related tests. You may instruct your officers in this regard because it is very important that the girl child should have a good health.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, आपने बहुत ही अच्छी बात की है और मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि हमने इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की और उसमें 29 लाख बच्चों के चैकअप किए गए। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश में थैलेसीमिया की बीमारी बच्चों में तेजी से बढ़ रही है। आप यह भी देखें कि पिछले वर्ष कितने बच्चे थैलेसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित पाए गए और उन बच्चों में से किसी को महीने में दो बार और किसी को महीने में एक बार और किसी को 20 दिन में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है तो क्या उसके लिए आपने सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की है या नहीं ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है और आप भी अभी ध्यान दिला रहे थे। पहले लोग घरों में गाय भैंस रखा करते थे और उसका यूज यही होता था कि अपने पीने के लिए दूध मिल जाया करता था। आज के इस माहौल में लोग घरों में गाय भैंस नहीं रखते हैं और जिनके पास गाय, भैंस हैं इकोनोमिक सिस्टम ऐसा आ गया है कि वे ये सोचते हैं कि थोड़ा सा दूध यदि बेच दें तो आमदनी हो जाएगी। इसके चलते जो डाइट महिलाओं और बच्चों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से माताओं, बहनों और बच्चों में खून की कमी है। जहां तक मैं समझता हूँ, हमने जो 29 लाख बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की है उनमें लगभग 37 प्रतिशत बच्चे ऐसे पाए गए जिनमें खून की कमी पाई गई। हमने इसके लिए उनको आयरन की टैबलेट्स दी। आंगनवाड़ी के जरिए बच्चों को मिड-डे मील और पोषक आहार वगैरह देने का काम भी चल रहा है। जहां तक थैलेसीमिया की बात है तो ऐसे बच्चों को हम फ्री ब्लड देते हैं इस तरह की व्यवस्था हमने कर रखी है।

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया (बावल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को जो आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं क्या वे टेबलेट्स वास्तव में दी जाती हैं या कागजों में ही दी जाती हैं। जो टैबलेट्स दी जाती हैं क्या वे ओरीजिनल टेबलेट्स होती हैं या नहीं क्योंकि उनका कोई असर नहीं होता है।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से वाकिफ हूँ और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो टैबलेट्स दी जाती हैं वे ओरीजिनल टेबलेट्स दी जाती हैं। सरकार द्वारा कोई भी डुप्लीकेट टेबलेट्स नहीं खरीदी जाती हैं। इसके लिए बाकायदा मापदण्ड बनाये गये हैं और उनके मुताबिक ही इन टेबलेट्स को खरीदा जाता है। सभी मरीजों को ये टेबलेट्स दी जाती हैं इसमें कोई कागजी कार्यवाही नहीं होती। इनके रिजल्ट जल्दी ही सामने आयेंगे। स्पीकर सर, मैंने निजी तौर पर अपने महेन्द्रगढ़ जिले में वहां के डी.सी. को बोल कर एक प्रौसैस स्टार्ट करवाया है कि वे विलेजिज में हैल्थ कैम्प लगवाएं और कैम्प लगाकर खास तौर से महिलाओं का होम्योग्लोबिन (एच.बी.) चैक किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपकी तरह यह मानना है कि महिलाओं का होम्योग्लोबिन कम पाया जाता है इसलिए उनको आयरन की टेबलेट्स दी जाएं। हमने यह प्रक्रिया अपने जिले में स्टार्ट की है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि दवाइयां ओरीजिनल ही हैं इसलिए वे इस बारे में चिन्ता न करें। उन दवाइयों को लेने से बहुत फर्क पड़ेगा। जैसा डाक्टर गाईड करते हैं उस हिसाब से ये दवाइयां ली जाएं तो पूरी तरह फर्क पड़ेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार (इसराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2005 से 2006 तक 406 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में जो प्रसूति गृह खोले हैं क्या उन प्रसूति गृहों में बिजली का, पानी का, टॉयलट्स का और डाक्टर्ज के उपकरणों का पूरा प्रबन्ध किया गया है ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है इन्होंने कुछ 406 प्रसूति गृहों की बात की है। निश्चित रूप से उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं सातों दिन किसी भी समय कोई भी महिला प्रसूति के लिए आती है तो सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए हमने कान्टीन्यूअस स्टाफ की व्यवस्था भी की हुई है।

कर्नल रघबीर सिंह (बाढड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हमने महसूस किया है और देखा भी है कि सभी अस्पतालों में दवाईयों की बहुत कमी है और मरीजों को दवाईयां नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में डॉक्टरों और स्टाफ नर्सिज की बहुत कमी है। मेवात के अन्दर जैसे मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेवात जिले के अन्दर कितने डॉक्टर्ज पोस्टिड हैं, कितनी नर्सिज पोस्टिड हैं और कितनी दवाइयों का वहां बन्दोबस्त किया जा रहा है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर डॉक्टर्ज और नर्सिज की कितनी पोस्ट्स सैक्शंड हैं और कितने-कितने डॉक्टर्ज और नर्सिज अभी पोस्टिड हैं और कितनों की कमी है ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता और हाउस को पता चल सके कि सरकार स्वास्थ्य के बारे में कितनी सचेत है ?

Mr. Speaker : These figures have already come, although Mr. Minister, you may please reply.

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, हमारे माननीय साथी ने मेवात के बारे में पूछा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेवात में 87 पोस्ट्स सैंक्शंड हैं जिनमें से 49 पोस्ट्स भरी हुई हैं और जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ भविष्य में बाकी जो बची हुई पोस्ट्स हैं उनको भी जल्दी ही भर देंगे।

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि पूरे प्रदेश के अन्दर कितने डॉक्टर्ज हैं, कितनी स्टाफ नर्सिज हैं, कितने पोस्टिड हैं और कितनी पोस्ट्स खाली हैं ताकि हाउस को यह पता चले कि सरकार कितनी सचेत है।

Mr. Speaker : I think the Hon'ble Members should visit hospitals and point out the problems. Your visits will help to improve the functioning of the hospitals and I think you should spare time for it. It is a good suggestion that has come from the House. More you will go more the working condition of the hospitals will improve. (Interruption) Hon'ble Members you may please resume your seats. Let me complete first.

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से वाकिफ हूँ और इनका प्रश्न बहुत बढ़िया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में एस.एम.ओज. की 412 सैंक्शंड पोस्ट्स हैं जिनमें से 376 भरी हुई हैं और 36 पोस्ट्स खाली हैं। जहां तक एम.ओज. की पोस्टों का सवाल है तो 2206 सैंक्शंड पोस्ट्स हैं जिनमें से 1833 भरी हुई हैं और 373 खाली हैं। कर्नल साहब आप तो फौजी अफसर रहे हैं आपके जो भी अच्छे सुझाव हों वे दिया करें, हम उन पर पूरी तरह से अमल करेंगे।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the Calling Attention Motion No. 3 given by Sarvshri Ajay Singh Chautala, Rameshwar Dayal, Raghbir Singh Badhra, Ashok Kumar Arora and Krishan Lal Panwar have been allowed by me to ask supplementaries on this matter. This House also expresses its deep concern over this issue mentioned in the Calling Attention Motion and the Hon'ble Minister for Health Services has assured this House that everyday they will try to improve the service because health is a very important aspect. Thank you.

गैर-सरकारी संकल्प-

अन्तर्भौम जल के दोहन को रोकने/नियमित करने सम्बन्धी

Mr. Speaker : I am embarking upon next agenda, the non-official resolution No. 1. Hon'ble Members, now Shri Ram Pal Majra will move his resolution.

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि अन्तर्भौम जल नियंत्रण तथा विनियम विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उचित पग उठायें ताकि अन्तर्भौम जल के दोहन को रोक/नियमित किया जा सके।

Mr. Speaker : Motion moved —

> This House recommends to the State Government to take appropriate steps to introduce Underground Water Control and Regulation Bill so that exploitation of underground water can be stopped/regulated.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार जल संरक्षण दिवस मना रही है। बहुत सी जगह लिखा भी मिलता है कि जल ही जीवन है। जहां प्राणियों के जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है वहीं फसलों, पेड़-पौधों के लिए भी जल की जरूरत है। कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है,कहीं पर जल स्तर ऊंचा है, कहीं नीचा है और कहीं सीपेज है, कहीं पानी खारा है और कहीं मीठा है, कहीं लवणीय है और कहीं बीमारियों से भरा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते

हुए इसके प्रबंधन की जरूरत है। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, इसकी उपयोगिता को समझने की जरूरत है इसलिए इस पर कोई नीति बनाई जानी चाहिए। प्रदेश की सरकार हर बार नाबार्ड से कुछ स्कीमें ड्रेनेज की, कुछ स्कीमें डिस्ट्रीब्यूट्रीज की और कुछ स्कीमें माइनर्स की एप्रूव कराती है और लोन लेती है। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिनके तहत माइनर्स के ऊपर 75 या 85 परसैंट पैसा खर्च हो जाता है। उनके ऊपर या तो कोर्ट का स्टे हो जाता है या मिस मनैजमैंट की वजह से वे रूकी पड़ी रह जाती हैं और लोगों को उनका फायदा नहीं हो पाता। इसी प्रकार से बहुत सी माइनर्स शहरों में चली गई हैं। वहां कालोनियां बस गई और उनमें से बहुत सी माइनर्स की टेलें करटेल हो गई और बहुत सी माइनर्स बन्द भी हो गई। उनकी जमीनें या तो फोरैस्ट डिपार्टमैंट को या फिर पी०डब्ल्यू०डी० को दे दी गई और उन्होंने इन जमीनों पर कुछ नहीं किया। लोगों ने उन जमीनों पर नाजायज कब्जे कर लिए। मैं विशेष कर कैथल जिले की बात करना चाहूँगा। वहां क्योड़क माइनर है वह बन्द हो गई थी इसलिए उसकी जमीन जिला परिषद को दी गई। इसी प्रकार पबनावा ढांड माइनर बन्द हो गई थी और उसकी जमीन को वन विभाग को दे दिया गया लेकिन वन विभाग ने उस पर कुछ नहीं किया और लोगों ने उस पर कब्जे कर लिए। जींद में जैड ई. 7 को पी०डब्ल्यू०डी० (बी.एण्ड आर.) को दिया गया लेकिन उस जमीन पर भी लोगों ने कब्जे कर लिए। पी०डब्ल्यू०डी० (बी.एण्ड आर.) ने केवल एक सड़क बनाई और बाकी की जमीन को छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो रजबाहे, डिस्ट्रीब्यूट्रीज, माइनर्स बन्द हो गए और उनकी जमीनें इरीगेशन डिपार्टमैंट की हैं, आज उन जमीनों का कोई यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उस जमीन और उस इलाके के पीछे चले गए पानी को यूज करने की कोई नीति बनाई जानी चाहिए। उपाध्यक्ष, महोदय, कई रजबाहे और माइनर्स बीच में ही छोड़े हुए हैं। मैंने विशेष तौर पर देखा है 4 अगस्त, 2007 को कैथल जिले में नैणा माईनर का माननीय सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने उद्घाटन किया था और नवीन जिंदल जी तथा दिनेश कौशिक जी भी उनके साथ थे। वहां पर 80 प्रतिशत पैसा लगाकर बुर्जी-16 तक तो बना दिया गया और 7 बुर्जी के लिए बीच में ही छोड़ दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर करोड़ों रुपये सरकार ने खर्च कर दिए लेकिन 2007 से लेकर आज तक उसमें पानी नहीं आया। इसी तरह उसी दिन सुदकन-जाखौली माइनर का भी उद्घाटन किया गया लेकिन बैड लैवल दोषपूर्ण होने के कारण वहां टेल तक किसानों को पानी नहीं मिला। इसी तरह से प्रदेश में बहुत सी परियोजनाएं हैं जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं लेकिन किसानों को उनका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अम्बाला जिले में मनसूर माईनर है जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हो गए लेकिन वह बीच-बीच में अधूरा पड़ा है। हरियाणा सरकार की ऐसी बहुत सी स्कीम्ज हैं जिन पर 80 प्रतिशत पैसा खर्च हो गया और किसानों को लाभ नहीं पहुंचा तथा उन पर जो धन राशि खर्च की गई वह बेकार में ही खर्च हुई। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में इंजीनियर्ज की वजह से टेल शोर्ट हैं। हमारे प्रदेश में 1200 टेल बनाई गई थी जिनमें से 225 टेल शोर्ट हैं। इसका मेन कारण आगे से बैड लैवल ऊंचा होना है, इनका स्लोप नहीं बना जिसके कारण एक भी टेल पर पानी नहीं पहुंचता और किसानों को हानि हो रही है। लगभग 226 कैनाल्ज, माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूट्रीज की टेल पर पानी न पहुंचने का कारण उनका बैड लैवल दोषपूर्ण होना है। यदि मैं इन सबका नाम बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं इनमें से कुछ का नाम बताना चाहूंगा कि न्यू सरसाना माईनर, न्यौली माईनर, बासड़ा नं.1 और 2 माईनर, न्यू सीधानी फीडर, पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूट्री, खानक माईनर, क्वारी माईनर,

[श्री रामपाल माजरा]

नलोई सब माईनर आदि ऐसी डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं जिनसे प्रदेश के लाखों किसानों को पानी मिलना चाहिए था लेकिन टेक्नीकल फिजीबिलिटी ठीक न होने की वजह से वह पानी नहीं मिल पाया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नहरों की सफाई की बात है इस बारे में कल भी सदन में चर्चा हुई थी। इस बारे में मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि साल में दो बार बिजाई से पहले आषाढ़ी और सावणी में नहरों की सफाई होनी चाहिए। कई बार बिजाई के समय इन्जीनियर्ज कहते हैं कि नहर में पानी बंद करो क्योंकि सफाई करनी है, इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। अगर बिजाई से पहले आषाढ़ी और सावणी में नहरों की सफाई की जायेगी तो मैं समझता हूँ कि किसानों को बहुत फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम भी और आप भी देखते हैं कि अगर नहरों और ड्रेनों की टाईमली सफाई नहीं करते हैं तो उनमें झाड़ बड़े-बड़े हो जाते हैं और गाद भी बहुत जम जाती है जिसके कारण उनमें पानी निर्धारित कैपेसिटी से कम चलता है। सरकार ने अबकी बार बाढ़ से निपटने के लिए बराबर तैयारी नहीं की थी। अगर बाढ़ को ध्यान में रखकर पहले ही ड्रेनों की सफाई की जाती तो हम नुकसान से बच सकते थे। बाढ़ आने के आद ड्रेनों की सफाई शुरू की गई और ड्रेनों ने पानी लेने से जवाब दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, समय रहते बाढ़ को रोकने के लिए ड्रेनों की सफाई करनी चाहिए और नहरों की भी सफाई करनी चाहिए तथा जो तटबंध हैं उनको भी समय पर मजबूत करना चाहिए। हमारी जो मुख्य नहरें हैं उनमें आज भी पानी निर्धारित कैपेसिटी से 30-40 प्रतिशत कम चल रहा है। भाखड़ा मेन लाइन, बी.एम.एल. बरवाला लिंक चैनल, बरवाला ब्रांच कैनाल, बालसमंद सब ब्रांच, रतिया ब्रांच, रोड़ी ब्रांच, हांसी ब्रांच, पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूट्री, सिवानी कैनाल, बुटाना ब्रांच तथा महेन्द्रगढ़ कैनाल आदि ऐसी मुख्य कैनाल हैं जिनमें बहुत लम्बे समय से अपनी निर्धारित कैपेसिटी से पानी कम चल रहा है। इसी प्रकार से बी.एम.एल. हरियाणा का सम्पर्क स्थल है वहां पर इसकी कैपेसिटी 6772 क्यूसिक है जबकि इसके अन्दर पानी महज़ 4000 क्यूसिक से 4200 क्यूसिक से ज्यादा नहीं होता जिसकी वजह से किसानों को बड़ा भारी लॉस होता है। इसकी टोटल कैपेसिटी भी 40 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक प्रयोग के बिना ही रह जाती है। बी.एम.एल. टेल टोहाना का भी यही हाल है और खनौरी हैड से निकलने वाली नरवाना जाखल सिरसा ब्रांच में गिरने वाली बी.एम.एल. की कुल कैपेसिटी 1700 क्यूसिक है जबकि इसमें केवल 1200-1300 क्यूसिक पानी ही चलता है इसलिए इसमें निर्धारित कैपेसिटी से 30 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक कम पानी रहता है। बरवाला ब्रांच भी अपनी निर्धारित कैपेसिटी से 20 से 30 प्रतिशत तक कम चलती है। इसकी क्षमता 1498 क्यूसिक है और इसी प्रकार से हिसार-भिवानी को जलापूर्ति करने वाली बालसमंद सब-ब्रांच की क्षमता 754 क्यूसिक है इसमें भी उतार-चढ़ाव होता रहता है। इसी प्रकार से देखा जा सकता है कि एक निर्धारित इंडेंट के मुताबिक ही पानी की सप्लाई होती है लेकिन ज्यादा निर्धारित इंडेंट के मुताबिक पानी नहीं मिलता। फतेहाबाद जिले की प्रमुख ब्रांच है रतिया ब्रांच जिसकी कैपेसिटी 600 क्यूसिक है उसका भी यही हाल है। रोड़ी ब्रांच कैनाल सिरसा जिला की मुख्य ब्रांच है इसकी कैपेसिटी 775 क्यूसिक है लेकिन इसमें भी अपनी निर्धारित कैपेसिटी से कम पानी चलता है। इसके साथ-साथ जिला जीन्द, हिसार और भिवानी में जलापूर्ति करने वाली हांसी ब्रांच है जिसकी कैपेसिटी 8000 क्यूसिक है इसमें भी निर्धारित कैपेसिटी से कम पानी रहता है। 5000 से 6000 क्यूसिक तक इसमें पानी चलता है। इसी प्रकार से पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी में भी बहुत कम पानी आता है और विशेष तौर पर पेटवाड़ टेल तक पानी मिलने तक पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी को एकदम

काट दिया जाता है। न्यु सिवानी फीडर भी काफी समय से अपनी निर्धारित कैपेसिटी से काफी नीचे चल रहा है। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जो मैन नहरें हैं वे अपनी निर्धारित कैपेसिटी से बहुत कम पानी दे पाती हैं और आज जो बजट पेश किया गया है उसमें पैरा नम्बर 39 पर यह लिखा है कि वर्ष 2011-12 में राज्य में 36 मिलीयन एकड़ फुट पानी की जरूरत है जबकि 14 मिलीयन एकड़ फुट की उपलब्धता है और 22 मिलीयन एकड़ फुट पानी की और आवश्यकता है इसलिए अगर हम इसका प्रबंधन ठीक ढंग से करेंगे तो निश्चित तौर से इसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमैंट होगा। सिंचाई विभाग द्वारा एक सर्वे किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में 336 लाख एकड़ पानी की जरूरत है और तमाम संसाधनों से 168.40 लाख एकड़ पानी उपलब्ध है। इस प्रकार से 168.60 लाख एकड़ पानी की सख्त जरूरत है। डिप्टी स्पीकर सर, इसके लिए हम उपलब्ध पानी का या तो सुप्रबंधन करें या फिर एस०वाई०एल० को लेकर आयें। एस०वाई०एल० प्रदेश के किसानों की जीवन रेखा है और इसके ऊपर 04 जून, 2004 को हरियाणा प्रदेश के हक में फैसला हुआ था। (विघ्न)

Cooperation Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Deputy Speaker Sir, the question is only for underground water because this House recommends to the State Government to take appropriate steps to introduce Underground Water Control and Regulation Bill so that exploitation of underground water can be stopped/regulated. Where is the question of canal कि ये कैनाल कम चल रही है और ये ज्यादा चल रही है ? This question is only about the underground water.

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : डिप्टी स्पीकर सर, विपक्ष के साथियों से आप कहो कि ये प्रॉपर तैयारी करके आयें। ये अच्छी तरह पढ़कर नहीं आते और जो यहां पर बोलना चाहिए वह न बोलकर कुछ और ही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे इन्होंने यहां पर रेजोल्यूशन तो किसी और टॉपिक के बारे में दिया हुआ है और बात ये किसी और ही टॉपिक पर कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने समय में वाटर रिचार्जिंग पर 1.52 करोड़ रुपये लगाये थे और हमने 457 करोड़ रुपये वाटर रिचार्जिंग पर लगाये हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां) : उपाध्यक्ष महोदय, चड्ढा जी ने दूसरे तरीके से इस बात को कहा है। सवाल इस बात का है कि जब तक वाटर रिचार्ज नहीं होगा तब तक पानी आयेगा कहां से ? वाटर रिचार्ज नहरों के माध्यम से ही होगा। हांसी बुटाना नहर को ही ले लीजिए। यह 18 फुट गहरी है। उसके किनारे और बेड दोनों ही पक्की हैं तो उसमें वाटर रिचार्ज कैसे होगा ? 11 किलोमीटर तक 10-10 फुट के बांध बना दिये और 9 किलोमीटर तक 7-7 फुट के बना दिये 5 फुट से आगे पानी जायेगा नहीं। उस पानी ने फ्लड में बैक मार कर 40 किलोमीटर तक बहुत नुकसान किया है। दादूपुर नलवी नहर है वह 6 साल से बेकार पड़ी है। कभी नहरें भी पार्ट से चलती हैं क्या, नहरें तो एकमुश्त चलती हैं ? इसकी वजह से जो फायदा होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। जो बरसाती नदियाँ हैं जैसे घग्गर है, कल भी इसके बारे में बताया गया था कि उसकी खुदाई की जा रही है। अब उसकी रेत निकाल कर बेच देंगे और बाद में फिर पानी आयेगा तो रेत तो फिर से भर जाएगी। उसका परिणाम यह रहा है कि आज समूचे विश्व के स्तर पर पानी की बहुत आवश्यकता है। बंगलादेश की आबादी विश्व की कुल आबादी का 1.56 परसैंट है लेकिन उसके पास दुनिया का 6 परसैंट पानी है। भारत की आबादी दुनिया की आबादी का 14.91 परसैंट है और भारत के पास 6 परसैंट पानी है। यह समूचे विश्व में एक

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

समस्या बनने जा रही है और भारतवर्ष इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। सवाल यह है कि पानी की रिचार्जिंग की व्यवस्था तो होनी चाहिए अन्यथा आपके पास पीने का पानी भी नहीं होगा। दुनिया में तो लड़ाई लड़ी जा रही है पेट्रोल के लिए और हमारे सामने समस्या आ रही है पीने के पानी की। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि यहां की बात अमृतसर न ले जाओ और अमृतसर की बात दिल्ली न ले जाओ। बात अंडरग्राउंड वाटर की हो रही थी और इसमें बंगलादेश कहां से आ गया ? (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अंडर ग्रांउड वाटर की बात कर रहा हूँ। अंडर ग्राउंड वाटर के लिए आप लोगों ने प्रयास भी तो नहीं किए। जहाँ से अंडर ग्रांउड पानी आता है वहाँ भी तो पानी होना चाहिए। अंडर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तभी तो अंडरग्राउंड वाटर बढ़ेगा। अब की बार थोड़ी सी बारिश हुई थी तो पानी का लेवल ऊपर आ गया था। सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास हुआ ही नहीं उल्टा नुकसान करने वाला काम किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप बी०एम०एल० हांसी बुटाना की बात कर रहे हैं यह एक कैरिंग चैनल भी है और रिचार्जिंग चैनल भी है। इनका यह कहना कि यह एक कैरिंग चैनल है ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप यह तो बतायें कि रिचार्जिंग के लिए आपने क्या किया है ? आप एक मिसाल तो दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : हमने उसमें साईड में बोर वैल बनाये हुए हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपने करनाल में बोर वैल किये थे वहां पर पानी और भी नीचे चला गया।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister wants to say something.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Speaker Sir, the Resolution was—

> "This House recommends to the State Government to take appropriate steps to introduce Underground Water Control and Regulation Bill so that exploitation of underground water can be stopped/regulated."

Sir, my reply is—

> The State of Haryana is facing twin problems of decline of water table in fresh water zones and rise of water table in the brackish water zones. Both these problems are increasing day by day. In the fresh water zones, the decline is said to be taking place because of the paddy - wheat cropping sequence and in the saline zones due to excessive use of surface water and very limited withdrawals due to unsuitability of under-lain waters for cultivation.

2. The latest assessment reveals that 55 Blocks of fresh water zones have become over-exploited, 11 critical, 5 semi-critical and only 43 are categorized to be safe. To say, these 43 Blocks to be safe is due to less withdrawal because of quality problems. It tantamounts to the whole of the ground water in the State being under stress.

3. The Department feels that this problem can be addressed by the enactment of Haryana State Ground Water Management & Regulation Act, for which the following steps/actions have been initiated :—

(a) Model Bill to Regulate and Control the development and management of ground water (2005) was received from Govt. of India. Accordingly, Haryana State Ground Water (Regulation & Control) Development & Management, Bill 2006 was drafted and submitted to Govt. by the Department on 14th August, 2006.

(b) A Committee has been constituted by the State Govt. on 22-5-2007 under the Chairmanship of Agriculture Minister with Public Health and Revenue & Disaster Management Ministers as its members to examine the issue of "depleting ground water resources in the State and suggest measures to contain the situation".

(c) The said Committee has met thrice on 19-6-2007, 20-8-2007 and 1-6-2009 for holding deliberations on the subject—

- In the 1st meeting, participants were requested to send their comments/suggestions on the concerned.
- In the 2nd meeting, the Committee was of the opinion that agriculture tube-wells and agriculture sector be kept out of preview of regulatory frame-work and public awareness for conserving water sources must be created and measures to augment groundwater resources be taken.
- In the 3rd meeting, it was decided to invite comments on the Model Bill from various departments/general public by putting the same in the public portal at Departmental website i.e. www.agriharyana.nic.in.

(d) Comments from various Departments on the Model Bill have been received. To decide the incorporation of these comments in the Model Bill, one more meeting will be convened very shortly.

The State Govt. will firm up the strategy immediately after the recommendations of the Committee.

4. The State Government has declared Year-2011 as "Water Conservation Year", further a number of steps are being taken for

[सरदार परमवीर सिंह]

saving water and arrest the depletion of under-ground water level by various departments.

A) **Agriculture Department** -

(a) The "Haryana State Preservation of Sub Soil Water Act, 2009" has been enacted which prohibits sowing and transplanting of paddy before 15th of May and 15th of June respectively. The ibid Act was notified on 18th March, 2009 and is being enforced strictly.

(b) The Department has introduced a State Plan Scheme from the year 2005-06, namely, "Accelerated Recharge to Ground Water" to recharge the ground water in water deficit areas of the State. Under this scheme, 418 Rain Water Harvesting structures have been constructed till March, 2010. A target of construction of 40 rain water harvesting structures has been fixed for the year 2010-11.

(c) The Department is also implementing National Watershed Development Project for Rain-fed Areas (NWDPRA), Flood Prone River (Ghaggar) and Sub Mountainous schemes under which activities like water harvesting structures, gully plugging, check dams, percolation embankments etc. are taken up. An amount of Rs.846 lakh has been spent under the above schemes to treat an area of 7,604 hectares during 2009-10 whereas a budgetary provision of Rs.747 lakh has been made for 2010-11 under these schemes out of which an amount of Rs. 354.50 lakh has been spent so far for treating an area of 3439 hectares.

(d) The Department is encouraging the farmers to adopt Drip and Sprinklers for irrigation to economize the use of irrigation water. For the promotion of Sprinkler System, subsidy @ 50% of the cost or Rs. 7,500 per hectare is being provided. So far, 1,04,758 sprinkler sets have been installed since the inception of the scheme in the State. An amount of Rs. 28.56 crore was given as subsidy during 2009-10 for promotion of sprinklers in the State. A total of 9,675 sprinklers were installed during the previous year whereas an amount of Rs. 50 crore has been earmarked for the current year 2010-11 for installation of 16,000 sprinkler sets. Drip irrigation system is also being promoted on pilot basis in cotton (350 hectares) and sugarcane (150 hectares) during the current financial year.

(e) In order to prevent seepage and evaporation losses, the Department is providing subsidy to the farmers @ 50% of the cost or a maximum of Rs. 60,000 per beneficiary for laying Underground Pipe Line System (UGPL). An amount of

Rs.3,815 lac has been spent for laying UGPL system in 39,581 hectares till 2009-10 since the inception of the scheme in 2002-03. An amount of Rs. 45 crore has been earmarked for UGPL during 2010-11 for covering 46,000 hectares in the State.

(f) Land leveling with Laser Levelers is being promoted which saves about 20% of irrigation water and improves crop production. Govt. has procured 120 Laser Levelers which are being run on custom hiring basis. A total of 14,282 hectares has already been levelled during 2010-11 upto February, 2011. A total of 60 Laser Levelers have been supplied on subsidy (@50% of the cost of machine or Rs. 50,000/- whichever is less) under RKVY scheme during 2010-11 upto February, 2011 whereas a total of 134 Laser Levelers have been supplied on subsidy from 2007-08, when the scheme was started, to 2009-10.

(g) Zero-tillage technology is being promoted which saves about 15% of irrigation water. A total of 1,290 Zero-tillage machines have been supplied on subsidy (@50% of the cost of machine or Rs. 15,000/-whichever is less) under RKVY scheme during 2010-11 upto February, 2011.

(h) Massive Awareness Campaign has been launched to educate the farmers regarding conservation of groundwater and judicious use of irrigation water. Farmers are being advised to grow less water intensive crops.

(B) Irrigation Department

(a) Irrigation Department is taking remedial measures for the recharge of ground-water. A total of 26 recharge schemes have been completed so far by the Department whereas 6 are in progress and 17 others are proposed to be taken up in near future.

(C) Haryana Urban Development Authority /Urban Local Bodies

(a) Urban Development Authority and Urban Local Bodies Department have made it mandatory for all Govt. buildings and private houses in HUDA Estates as well as Municipal Areas having roof top surface area of 100 square meters or more to have a Rain Water Harvesting Structure.

(b) HUDA has notified the Haryana Urban Development Authority (Erection of Buildings) Amendment-Regulations, 2001 on 31st October, 2001 whereas Urban Local Bodies Department has notified Haryana Municipal Building (Amendment) Bye-laws, 2002 on 13th December, 2002 for the purpose under reference.

[सरदार परमवीर सिंह]

(D) Rural Development Department

(a) Rural Development Department is implementing Centrally sponsored schemes namely Desert Development Programme (DDP), Integrated Wastelands Development Programme (IWDP) and MGNREGS, under which it has spent an amount of Rs. 111.32, Rs. 19.26 and Rs. 109.34 crore respectively, covering an area of 1,39,764 hectares, 25,778 hectares and 7,035 works (under MGNREGS) respectively during the period 2006-07 to 2010-11 (upto January, 2011).

सर, हमारी गवर्नमैंट यह ऐक्ट उनके लिए लाई जिसने पैडी की पौध और पैडी ट्रांसप्लांटेशन का काम किया। दूसरी बात यह है कि जो साथी हैं वह ज्यादा पानी पी रही थी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, पहले माजरा साहब कुछ बातें पूछना चाहते हैं उसके बाद आप रिप्लाई दे देना।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पानी पौल्यूट हो रहा है। चाहे वह यमुना का पानी है, चाहे मारकंडा का है, चाहे घग्गर का है उसमें विशेष रूप से दूसरे प्रदेशों से गंदा पानी आता है। एक तो सहारनपुर से मस्करा नाला आकर घग्गर में मिल जाता है। इसके अलावा कुछ यमुनानगर और पानीपत की फैक्ट्रियों का पानी इनमें आ कर मिल जाता है जिससे पानी बहुत ज्यादा पौल्यूट हो जाता है। जब यह पानी फरीदाबाद पहुंचता है तो पीने की तो बात दूर की है, देखने के योग्य भी यह पानी नहीं रहता। इसी तरह से ड्रेनों में भी गन्दा पानी छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से रिचार्ज होकर पीने वाला पानी ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, इसके बारे भी सरकार ध्यान रखे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कई जगह से निकलते हुए बदबू आती है, वह इसलिए आती है कि कारखानों का पानी उसमें चला जाता है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। अध्यक्ष महोदय, मारकंडा नदी की तो पूजा होती है लोग उसे धार्मिक भावना की दृष्टि से देखते हैं। इसमें भी कई तरफ से व काला अम्ब से फैक्ट्रीज का दूषित पानी आता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत सी नदियां विलुप्त हो रही हैं। सरस्वती नदी विलुप्त हो रही है और बहुत से लोगों ने तो नदियों की जमीन ही दबा ली। इसकी डिमारकेशन कराई जाए तो सरकार का ही फायदा है और वह नदी भी दोबारा आ सकती है।

Mr. Speaker : Majra ji, are you talking about under-ground water control ?

श्री राम पाल माजरा : जी हाँ सर, नदियों के माध्यम से पानी ग्राउंड में जा रहा है और पौल्यूटिड पानी ही ग्राउंड के नीचे जा रहा है। इसलिए पौल्यूटिड पानी पर ध्यान देकर इसको भी साफ किया जाए। सर, इसका कारण मैं जरूर बताना चाहूंगा। इसका मुख्य कारण बहुत ज्यादा अवैध खनन है। यमुनानगर से यमुना को देखें तो वहां 100 करोड़ रुपये की लागत से 600 से ज्यादा क्रशर लगे हुए हैं इसी प्रकार से घग्गर को भी पंचकुला के पास से देखेंगे तो लगभग 300-400 जे०सी०बी०, डोजर, ट्रैक्टर उसके अंदर तक जाते हैं और इनकी वजह से तटबंध टूटते हैं। जब तटबंध टूटते हैं तभी बाढ़ आती है। इन पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : यमुनानगर का क्वैरी जोन किसके पास है। जो ये वहां से खनन कर रहे हैं वह रेत का कर रहे हैं, रोड़ी का कर रहे हैं, यह कैसे कर रहे हैं ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, वर्ल्ड बैंक की भी चेतावनी है कि हमारी खाद्यान्न को खतरा है। यू.एस.ए. बेस्ड नासा ग्रेस मिसन ने भी एक स्टडी की है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को अत्यधिक दोहन क्षेत्र माना है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान ने भी इसको डैन्जर जोन कहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में एक वैबसाईट तैयार करे जिस पर सारे शहरों और बड़े गांवों या नजदीक के गांवों का डाटा आ जाए जिस पर पानी की उपलब्धता हो, जिस पर पानी की गुणवत्ता हो और पानी के दुरुपयोग के बारे में जानकारी हो। स्पीकर सर, जब सरकार की मेन थ्रस्ट थी तब सरकार ने हांसी बुटाना नहर बनानी शुरू की थी तो यह कहा था कि इसको नीचे से कच्ची रखेंगे ताकि इससे रिचार्जिंग हो सके लेकिन पता नहीं बाद में कैसे हालात बने कि इसका बैड लैवल पक्का कर दिया गया। इसके बारे में सी.ए.जी. की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वह रिपोर्ट आपने शायद पढ़ी होगी और टाईम्स ऑफ इण्डिया में भी यह खबर आई थी कि एक कम्पनी को छः करोड़ रुपये हांसी बुटाना नहर के लिए एडवान्स में पेमेंट कर दिया गया।

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Just a suggestion Sir, he has brought such a nice resolution on underground water control. Is it a political speech or is it a suggesion or recharging on underground water ?

Mr. Speaker : It is not.

Shri Randeep Singh Surjewala : Then how can the Hon'ble Member who had been the Chief Parliamentary Secretary and the incharge of the Parliamentary Affairs, make such a statement ?

Mr. Speaker : He may restrict his speech to his reference.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जब रिचार्जिंग की बात हुई थी तो इसका जो मेन प्रोजैक्ट बना था..... (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पानी रिचार्ज तो तब होगा जब बारिश ज्यादा होगी या नहर का बैड लैवल कच्चा रहेगा। इसी हांसी बुटाना लिंक नहर को 18 फिट तो खोद दिया गया उसके बाद बैंक्स पक्की कर दी गई और बैड पक्का कर दिया गया तो रिचार्जिंग कैसे होगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप हांसी बुटाना नहर के खिलाफ हो क्या ? आप हर बार इसके बारे में बोलते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, खिलाफ की बात नहीं है हम तो इसके पक्ष में हैं। हम तो रैजोल्यूशन के पक्ष में हैं। आप ही बतायें क्या रिचार्जिंग फ्लड और बारिश के पानी से होगी ? दादूपुर-नलवी नहर है। कभी नहरें भी क्या कोई पार्ट में चलती हैं। छः साल से ये यह बात कह रहे हैं कि इस नहर का इतना हिस्सा इस साल में चलेगा और इतना हिस्सा इस साल में चलेगा। नहरें तो टोटल बनने के बाद चला करती हैं। सरकार की नीति गलत है। सरकार की सोच ही गलत है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, दादुपुर नलवी नहर भी बनाना गलत है क्या ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गलत नहीं है। दादुपुर नलवी नहर रिचार्ज के लिए बनाई जानी थी लेकिन यह छः साल से बनाई नहीं गई। छः साल में उस नहर पर कुछ काम नहीं हुआ। आप सुनकर हैरान होंगे कि इसका एक पुल सारे का सारा बनते ही टूट गया और बाकी जो पुल हैं उनमें भी करैक आ गया है।

श्री अध्यक्ष : क्या ज्यादा पानी आ गया ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं, नहीं, ऐसे लोगों को ठेके दे दिए गए जिनके पास पैसा ही नहीं हैं। लोग इसमें पैसा खा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि जहां-जहां से भाखड़ा मेन लाईन गई थी पूरे पंजाब और हरियाणा से और आदरणीय चौटाला जी तो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने इस विभाग को भी बतौर मुख्यमंत्री जरूर देखा होगा। सर, नहर नीचे से पक्की हो, नहर नीचे से कच्ची हो जब इतना पानी फ्लो करता है तो ओटोमैटीकली दोनों तरफ किलोमीटरों तक कई टयूबवैलों का पानी ऊपर उठता है। पानी प्राकृतिक तौर से नीचे जाता ही रहता है, जब नहर में पानी आता है तो चारों तरफ का वह इलाका जहां से नहर जाती है वहां पानी मीठा भी होता है और पानी का स्तर भी ऊपर आ जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। चौटाला साहब जी दादूपुर नलवी नहर के बारे में कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि ऐसा किसने कहा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने ही कहा कि दादूपुर नलवी नहर बेकार है और उस पर फालतू में पैसा लगा दिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, दादुपुर नलवी नहर की शुरुआत हमारी सरकार में ही हुई थी। 2004 में उसकी आधारशिला मैंने ही रखी थी। इनके 6 साल के अर्से में इस पर कुछ काम नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान) यह नहर हमारी सरकार के वक्त में ही शुरू हुई थी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बजट में एक पैसा नहीं रखा। ये श्रीमान् पत्थर रखकर चले गए। हमने तो बजट में पैसा रखा है और बाकायदा इस नहर को शुरू करवाया। केवल घोषणा करने से बात नहीं बनती। 20 सालों तक यह बात चलती रही और यह बहुत पुरानी मांग थी। इतना बड़ा कार्य हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता को मालूम है कि जो आधारशिला इन्होंने रखी है। चौटाला जी तो तो एक ट्रक पत्थर का भरकर अपने साथ रखा करते थे और बगैर बजट में कोई पैसा पास किए कहीं भी आधारशिला रख दिया करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने क्या-क्या किया यह तो जग जाहिर है। हमने आधारशिलाएं भी रखी थी और उद्घाटन भी किये थे। पत्थर तो लोग इनको मारेंगे जब इनकी सरकार जाएगी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, शहजादपुर में 2006 में एक कालेज बनाने की घोषणा ये करके आए थे लेकिन आज तक उस पर ईंट नहीं लगाई गई।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि दादूपुर नलवी नहर की आधारशिला रखते ही आप की सरकार क्यों चली गई?

आवाजें : लोगों ने बदल दी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप चौटाला साहब से एक सवाल पूछ लें कि इन्होंने दादूपुर नलवी नहर के लिए कितना पैसा एलोकेट किया था। वित्त मंत्री ने भी इनसे पूछा है। May I ask Sir कि कितना पैसा एलोकेट किया था?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बिना पैसे के कोई काम शुरू होता है क्या? पैसा पहले सैंक्शन होता है तब काम शुरू किए जाते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बना दो। वह कमेटी चैक करके बता देगी कि इन्होंने कितना पैसा दादूपुर नलवी नहर के लिए रखा था।

Mr. Speaker : There is no need to constitute a Committee. The Minister concerned by tomorrow may place the record with regard to that canal on the Table of the House as to what funds were kept on the disposal and what has been done after this? Alright, no further discussion.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, 1987 में इस नहर के लिए जमीन एक्वायर हुई है। 1983 में भी जमीन एक्वायर हुई थी। एक दिन में नहर की शुरुआत नहीं हो जाती। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Your friends also are raising hands, should I allow them to speak?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो अभी बोलने ही नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : सुभाष चौधरी और नायर साहब हाथ उठा रहे हैं, क्या मैं इनको बोलने दूं या आपने बोलना है?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका प्रिवीलेज है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हांसी बुटाना लिंक कैनाल में से बुटाना ब्रांच का बैड 11 फुट और हांसी ब्रांच का बैड 9.20 फुट नीचा बना हुआ है। इसकी 18.37 फुट की गहराई है इसलिए इसका केवल 7.25 फुट हिस्सा ही पानी के प्रवाह में आएगा और वह भी तब जब प्राप्तकर्ता नहरें खाली होंगी। बैड नीचा होने की वजह से 11 फुट की एक ब्रांच को ठोकर लगेगी और 9.20 फुट की दूसरी ब्रांच को लगेगी। अध्यक्ष महोदय, यह मैं टैक्नीकल बात कर रहा हूं। इसके साथ-साथ अगर मैं इसकी लीगल बात करूं तो as per the Bhakra Nangal Agreement, 1959, extension or

[श्री रामपाल माजरा]

alternation in the dam, appurtenant works, river works and the channels cannot be done without the concurence of all the States और इसी बात के ऊपर सी०डब्ल्यू०सी० ने यह कहा कि हम अपना लीगल ओपीनियन देने से दूर रहेंगें। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा को पहले पंजाब और राजस्थान का पानी पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद ही हरियाणा इस पानी को यूज करेगा। इस बारे में ये कहते हैं कि मंजूरी मिल गई।

Shri Randeep Singh Surjewala : It is not a debate on distribution of water. It is a debate on recharge of underground water पता नहीं ये अपना स्वयं का रैजोल्यूशन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं?

सहकारिता मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे से ज्यादा हो गया शुरू में रिचार्जिंग की बात चल रही थी और बाद में चली गई इरीगेशन पर कि इस नहर में पानी कम आता है, दूसरी नहर में पानी कम आता है और तीसरी नहर में पानी कम आता है। रिचार्जिंग की बात ही नहीं की गई। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये जो हाउस को मिसलीड कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister is speaking. Marja ji please resume your seat.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि सी०डब्ल्यू०सी० ने कोई 13.00 बजे क्लैरीफिकेशन नहीं दी। हमने 2006 में रिपोर्ट सबमिट की और 23 मार्च, 2007 को सी०डब्ल्यू०सी० ने डिजाईन क्लीयर कर दिया। यह जो प्रोजेक्ट है it was cleared from hydrology-flood angle by the Director, Central Water Commission. ये लोग सदन के अंदर गलत बात क्यों करते हैं। He should not mislead the House.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय * * *

Mr. Speaker : Mr. Majra please listen to me. (Interruption) Mr. Majra you are not listening to me. Alright, this will not be recorded. (Interruption) Mr. Majra, you will confine your speech to recharge, anything outside it will not be recorded.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जब यमुना जल समझौते में हमारा पानी का शेयर कम हो गया तो हमारे रेणुका बांध, किशाऊ बांध और लखवार बांध बनने चाहिएं थे। यह ठीक है कि सरकार ने कहा कि रेणुका बांध के लिए 25 करोड़ रुपये जमा करवाये हैं लेकिन उसमें भी अभी तक - - -।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब इनकी सरकार थी उस समय क्या इन्होंने कभी रेणुका बांध और किशाऊ बांध के बारे में सैंटर गवर्नमैंट से बातचीत की। हमने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन बांधों को नैशनल प्रोजैक्ट मानकर भारत सरकार से बातचीत की है। इसमें

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

90 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार देगी और 10 प्रतिशत हिस्सा हम देंगे। उसके बाद भी ये इस तरह की बात करते हैं। यदि इन्होंने कभी इस बारे में बात की है तो ये सदन में प्रमाण देकर बतायें। इनका यह कहना कि हमने रेणुका डैम के लिए कुछ नहीं किया यह गलत बात है। इसको हमने अपने प्रयासों से नैशनल प्रोजैक्ट घोषित करवाया है और इसके लिए इनवायर्नमैंट विभाग से क्लीयरैंस भी मिल गया है और जमीन भी एक्वायर हो चुकी है। इसके अतिरिक्त लखवार डैम की डी०पी०आर० बन रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब यमुना एकोर्ड हुआ था तब इस शर्त के साथ हुआ था कि यह जो हरियाणा का पानी दिल्ली को जा रहा है उसके लिए लखवार डैम, किशाऊ डैम और रेणुका डैम बनेंगे जिनसे हरियाणा को पानी मिलेगा। 20 साल तक केन्द्र की सरकार ने और हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने इन डैमों को बनवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। हमारी सरकार आने पर हमने उनको जाकर मजबूर किया कि इन डैम्ज को बनाओ अन्यथा हमारा जो पानी दिल्ली को दिया है उसकी पूर्ति कहां से होगी। दिल्ली को जो हमारा पानी दिया था उसकी ऐवज में ये डैम बनाने का फैसला हुआ था। जिसके लिए इनकी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता रिकार्ड पर दिखा दें कि इन्होंने इन डैम्ज को बनवाने के लिए कब सैंटर गवर्नमैंट को एप्रोच किया था। हमारी सरकार आने के बाद हमने सैंटर गवर्नमैंट से एप्रोच किया है। जो 1994 का समझौता हुआ था उसमें किस प्रकार की गलती हुई थी कि वह मैंने सदन में बता दी थी। (विघ्न) मैं मान रहा हूं उस समय गलती हुई थी।

Mr. Speaker : Who was the Chief Minister at that time?

Capt. Ajay Singh Yadav : Ch. Bhajan Lal was the Chief Minister at that time.

Mr. Speaker : And who committeed this mistake?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्क्वायरी करने के लिए इन्होंने विधान सभा की एक कमेटी भी बनाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : वे कमेटी के सामने आये ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान) आज उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई प्रदेश में ट्रैक्टर रैली करता घूम रहा है और उनके फादर ने इतना बड़ा अन्याय प्रदेश की जनता के साथ किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट की मुस्तरका जिम्मेवारी होती है। जिस भजन लाल मुख्यमंत्री जी का कैप्टन साहब ने जिक्र किया है उस कैबिनेट में कैप्टन साहब भी मिनिस्टर होते थे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कब डिनाई कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) I am not denying it.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फिर उसको क्यों दोषी करार कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान) उसको क्यों दोषी करार दे रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

Capt. Ajay Singh Yadav : I am not denying it. मैंने तो सदन में सारी बात बताई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बार फिर से रैजोल्यूशन की तरफ दिलाना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब तो यह हुआ कि—

इतिहास के पन्नों ने वो दौर भी देखे हैं,

लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : तू इधर-उधर की न बात कर,

तू यह बता कि काफिला क्यों लुटा,

हमें राह जनों से गिला नहीं,

तेरी रहबरी का सवाल है।

यमुना जल समझौते में हरियाणा के साथ अन्याय हुआ था या नहीं हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रैजोल्यूशन से हटकर जो बातें कही है वे रिकार्ड न करवाई जायें। माननीय सदस्य डिबेट से भटक गये हैं। डिबेट यह है कि exploitation of under-ground water पर Under-Ground Water Control and Regulation Bill लाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जाना दिल्ली था और लोग जा रहे हैं बाम्बे और कोलकता।

Mr. Speaker : Mr. Majra, do you think that the Government of Haryana wants to construct Dadupur-Nalwi drain whatever size it is? Is it a good step of this Government?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ये स्टैप्स तो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने उठाये थे।

Mr. Speaker : No, No. When the construction of Drain was started? Is it good? Is it for recharge? (Interruption)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे कंसर्ड मंत्री जी ने भी यह कहा और विपक्ष के साथियों ने भी यह कहा है कि जो यमुना जल समझौता हुआ था उसमें हरियाणा के हितों के साथ न्याय नहीं हुआ था। जिसने भी यह समझौता किया वह ठीक नहीं किया। इस बात से हमारे मंत्री जी भी सहमत हैं लेकिन एक सवाल मैं इंडियन नैशनल लोकदल के साथियों और इनके मुखिया से पूछना चाहता हूं कि यह समझौता होने के बाद 6 साल तक इनकी सरकार सत्ता में रही उस समय इन्होंने क्या इस बारे में कोई कदम उठाये? ये एक बार भी विधान सभा में इस बारे में नहीं बोले। उसी समय पंजाब ने तो तीन राज्यों के साथ हुए समझौते को निरस्त कर दिया था लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने उस समय क्या किया?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये शायद भूल रहे हैं कि इस सम्बंध में इन्होंने भी हमारे साथ बैठकर प्रस्ताव पारित किया था।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I rquest them that they should give a separate notice on irrigaion issues.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, इन्होंने एस०वाई०एल० के बारे में प्रस्ताव पारित किया था जिसका हमने समर्थन किया था। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस समय यहां पर एस०वाई०एल० की बात नहीं हो रही है। इस समय यहां पर यमुना जल समझौते के बारे में बात हो रही है। हमारे माननीय मंत्री जी ने माना है कि उस समय के मुख्य मंत्री जी से यह ठीक नहीं हुआ इस बात को इन्होंने एडमिट किया है लेकिन उसके बाद 6 साल तक तो इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार रही उस दौरान इन्होंने इस बारे में क्या किया? श्री ओम प्रकाश चौटाला जी यह बता दें। उस समय केन्द्र में भी इनके समर्थन से माननीय श्री वाजपेयी जी की सरकार सत्तासीन थी। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आज वीरवार का दिन है जो कि प्राईवेट मैम्बर्ज़-डे है। एक घंटा निकल गया ये अण्डर ग्राऊंड वाटर पर कम से कम अपना रेजोल्यूशन तो पढ़े। उसमें लिखा है :- "appropriate steps to introduce Underground Water Control Bill so that exploitation of underground water can be stopped/regulated." इसमें लिखा है 'underground water' not 'surface water'. विपक्ष के साथी रेजोल्यूशन तो अण्डर ग्राऊंड वाटर के बारे में देते हैं और चर्चा करते हैं सरफेस वाटर के बारे में। इनको यह पता होना चाहिए कि सरफेस वाटर और अण्डर ग्राऊंड वाटर में डिफरैंस होता है। यह इनको पता ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) पता नहीं ये रेजोल्यूशन किससे लिखवाकर लाते हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Shri Ram Pal Majra ji, you may confine yourself to underground water only.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, पंजाबी में एक कहावत है "अग ला के, डूबू कंद ते" ये शुरू तो आप कर देते हैं और जब फंस जाते हैं तो फिर कहते हैं कि यहां पर सरफेस वाटर की बजाय अण्डर ग्राऊंड वाटर के बारे में बात की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Since this is a very important subject no reference outside the resolution should be mentioned in records. (Interruption) Majra Ji, you will confine yourself to undergound water. Now, kindly you may continue.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था मैं उसका रिप्लाई जरूर देना चाहता हूं। 16 नवम्बर, 2004 को अधोया गांव में दादूपुर-नलवी नहर का फांऊडेशन स्टोन रखा गया था। सितम्बर, 2000 में 10 करोड़ रुपये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस कार्य के लिए दिये। * * * * * (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में बोलना चाहते हैं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded outside this resolution. (Interruption) I will look into the record. Mr. Majra you may continue.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, 1999 के बाद हरियाणा प्रदेश में भू-जल स्तर 6.20 मीटर नीचे चला गया और प्रति वर्ष 6.37 सैंटी मीटर तक पानी नीचे जा रहा है। महेन्द्रगढ़ में भू-जल स्तर 45 मीटर नीचे चला गया है और प्रदेश की धान बैल्ट में भी यही हाल है। कुरूक्षेत्र में 30 मीटर, भिवानी में 21.25 मीटर, गुड़गांव में 23.15 मीटर और रेवाड़ी में भू-जल स्तर 21.50 मीटर नीचे चला गया यानी मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर यह स्थिति बहुत चिंतनीय है। सरकार को इसके ऊपर गम्भीरता से सोच-विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से सरकार को प्रदेश में पुराने तालाबों के ऊपर से भी अवैध कब्जों को हटवाना चाहिए और प्रदेश में बहुत से तालाब ऐसे भी हैं जो गांवों के अन्दर आ गये हैं और उनके आगे रिंग बांध बन गये उसके लिए कोई रिचार्जिंग योजना बनाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई जगह देखा है कि नरेगा स्कीम के तहत खोदे गये तालाबों में पानी नहीं है चाहे वे साल से खोदे गये या दो साल से खोद गये हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास उनकी लिस्ट भी है। वे तालाब खोद तो दिये गये लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंच पाया तो रिचार्जिंग कैसे होगी? उनको खोदने का मकसद तो अंडर ग्राउंड वाटर रिजार्जिंग का था लेकिन इस तरीके से अंडर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कैसे होगी? इस तरह के दर्जनों तालाब हैं जहाँ रिचार्जिंग का पैसा तो लग गया लेकिन रिचार्जिंग नहीं हुई। इसी तरह से कांडा द्वारा या सिंचाई विभाग द्वारा जो नाले बनाये जाते हैं उन पर भी अगर हो सके या आगे से कोई डिस्ट्रीब्यूट्रीज या माईनर बनाई जायें तो उनके बैड को कच्चा छोड़ दिया जाये तो उससे पानी नीचे जायेगा और रिचार्जिंग होने के चांस ज्यादा होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर नालों को कच्चा छोड़ दिया जायेगा तो उसमें पानी कैसे चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, कंकल्यूड करें।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिले में बराड़ा खण्ड बड़ा क्रिटिकल है। इसी प्रकार से इनके विभाग ने जो क्रिटिकल जोन चिह्नित किये हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ उनको विशेष तौर पर देखा जाये। फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद और हसनपुर, गुड़गाँव का नगीना, जीन्द का नरवाना और अलेवा भी इसी केटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार से झज्जर में बहादुरगढ़ है। इसी प्रकार से महेन्द्रगढ़ में महेन्द्रगढ़, अटेली और नारनौल तथा सिरसा का गूढा है। अध्यक्ष महोदय ये इस प्रकार के जोन हैं जो क्रिटिकल माने गये हैं। इसी प्रकार से कुछ सैमी-क्रिटिकल जोन भी हैं, इस पर ध्यान दिया जाये तथा पानी को पोल्यूट होने से बचाया जाये तथा जो पुराने कुएं हैं उनको भी रिचार्जिंग के काम में इस्तेमाल किया जाये। इसके प्रबन्धन पर कोई पॉलिसी बनाई जाये। धन्यवाद, स्पीकर सर।

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक ज्वलन्त विषय पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पृथ्वी पर जितना कुल पानी मौजूद है उसका कुछ प्रतिशत ही पीने का पानी है। लेकिन जितनी तेजी से हमारे अंडर ग्राउंड वाटर का एक्सप्लायटेशन किया जा रहा है उसकी वजह से लगता है कि अगला विश्व युद्ध पानी

पर ही होगा। मैं श्री रामपाल माजरा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे ज्वलन्त विषय को सदन में उठाया। अध्यक्ष महोदय, अंडर ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करने और एक्सप्लाइटेशन को रोकने के लिए मैं कुछ छोटे-छोटे उपाय सदन के सामने रखना चाहती हूँ। सुबह प्रश्न काल के दौरान भी मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया था जिसको कि सिंचाई मंत्री जी ने हवा में उड़ा दिया। स्पीकर सर, मुझे फिर से मौका मिला है कि मैं उन छोटे-छोटे उपाय जो हमारे अंडर ग्राउंड वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका एक्सप्लाइटेशन रोक सकते हैं, बताना चाहूँगी। स्पीकर सर, शहरों में जो लो लाईन एरिया होते हैं जहाँ पर बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है अगर वहाँ पर रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम बनाया जाये तो उस पानी को स्टोर किया जा सकता है तथा बाद में उसको रिचार्ज करके पीने के पानी में या किसी काम में लाया जा सकता है। इसी तरह से बारिश के दिनों में काफी मात्रा में जो पानी बेकार चला जाता है उसको बचाया जा सकेगा। जिस तरह से चण्डीगढ़ के अंदर वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम बनाया गया है उसी तरह से हरियाणा के शहरों में भी ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिनमें एक तरफ सीवरेज की लाईन डाली जाए और दूसरी तरफ बारिश का जो पानी है उसको रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम के हिसाब से बनाया जाए और सारा पानी एक अलग लाईन में डाला जाए और शहरों के बाहर एक स्पेस बनाकर यह पानी स्टोर किया जाए। फिर बाद में उसको ट्रीट करके काम में लाया जाए। इसी तरह से खेतों में सिंचाई के लिए खालों में जो पानी बहता रहता है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस तरह की कोशिश की जाए कि वह पानी बेकार न बह जाए। स्प्रिंकलर सिस्टम जो सिंचाई के लिए प्रयोग होता है उसके प्रोसीजर को बढ़ावा दिया जाए और किसानों को इसके बारे में नॉलेज दी जाए। बारिश के दिनों में नदियों में भी बहुत ज्यादा पानी आता है जैसा कि पिछले साल बारिश के दिनों में हरियाणा में यमुना नदी से बाढ़ आ गयी थी। कई-कई किलोमीटर तक लम्बी पानी की धारा बहकर फसलों को खराब करके इधर से उधर चली गयी थी। इसके लिए मैं सजैशन देना चाहूंगी कि उस पानी को बारिश के दिनों में स्टोर करने की कोई योजना बनायी जाए ताकि पानी का सदुपयोग हो जाए और यदि पानी को रिचार्ज करना पड़े तो वह भी हो जाए। धन्यवाद।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उस क्षेत्र के अंदर अंडर ग्राउंड वाटर नाम की कोई चीज नहीं है। लगभग 72 गांवों में से 80 प्रतिशत गांवों में पानी नहरों से आता है उसी नहरी पानी से पीने के पानी की वहां पर व्यवस्था है। जो नहरी व्यवस्था पिछले दिनों से बनी हुई है उसके अंदर पिछले कई सालों से टेल पर पानी नहीं जा रहा है। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जवाब दिया था कि उन टेलों पर पूरा पानी जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जे०डी० 3 जो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूट्री है उससे लगभग 22 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। सारे के सारे गांव जैसे आसन, खर्कराम जी, चावरी, डिगाणा, भेरूखेड़ा, निडाणा और पगाणी है जो टेल पर हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनका सुझाव ठीक है लेकिन ये विषय से हटकर है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। जब तक अंडर ग्राउंड वाटर नहर से गांवों में नहीं आएगा तो फिर जोहड़ कैसे भरेंगे और खेतों में पानी कैसे जाएगा और जब खेतों में पानी नहीं जाएगा तो फसलें कैसे मिलेंगी?

श्री अध्यक्ष : अब धन्तौड़ी साहब बोलेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, जब आपने मुझे बोलने के लिए समय दे दिया है तो आप मुझे अपनी बात पूरी तो कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष : आप अब सबजेक्ट पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, हमारे जुलाना हल्के में टोटल पीने के पानी की और खेत की व्यवस्था नहर के पानी से ही है। अगर नहर में पानी ही नहीं आएगा तो वाटर रिचार्ज कैसे होगा। मेरा सुझाव यह है कि जितने वहां पर माईनर्ज बने हैं उनमें पिछले 6 सालों से टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। वह हल्का टोटल टेल पर ही है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपकी बात अंडर ग्राउंड वाटर से रिलेटिड कैसे है?

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कई गांवों में तालाबों में पानी नहीं आ रहा है। डांगी साहब को भी पता है क्योंकि इनके हल्के में भी वही नहर जाती है। वहां पर पानी नहीं आ रहा है। यदि वहां पर उनमें पानी ही नहीं आएगा तो वाटर रिचार्ज कैसे होगा। पानी रिचार्ज तभी होगा जब पानी आएगा। वहां पर कई गांव ऐसे हैं जैसे बीबीपुर है, घिमाणा है, बैवलपुर है जिनमें लोगों ने वर्षों बीत जाने के बाद भी पानी नहीं देखा। नहर की डिग्गी तो बनी हुई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं रह सकता है। पिछले 6 साल तो ऐसे ही पूरे हो गए हैं लेकिन पानी नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि किला जफरगढ़ गांव है उसके अंदर पिछले 6 साल से पानी की घूंट नहीं गयी है। इस साल बरसात ज्यादा हुई है और कई इलाकों में पानी भर गया था तथा नहर भी हमारी इस बार थोड़ी फालतू चल गयी तो इसके बाद उस गांव में डेढ़ फुट पानी 6 साल बाद गया है। उस गांव वाले यह कहने लगे थे कि हमें इस गांव से उजाड़कर कहीं और बसा दो। इसी तरह से बीबीपुर गांव है, बैवलपुर गांव है, इगराह गांव है, ढिमाणा गांव है, सबमें यही हालत है। इसी तरह से एक गोहाना सब माईनर बनी हुई है। पिछले पांच साल से गोहाना सब माईनर में एक बूंद भी पानी की नहीं जा रही है फिर आप ही बताएं कि पानी कैसे रिचार्ज होगा क्योंकि तालाब भर नहीं रहे हैं, पानी जा नहीं रहा है? जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस समय मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस का जिला प्रधान था उस समय भी अकेले जफरगढ़ माइनर के अंदर पांच साल पूरा पानी आया और इनके सत्ता से जाते ही पानी आना कम हुआ है। यह रिकार्ड की बात है। यदि मेरी बात झूठी हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) पानी नहीं आ रहा है। यह हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? मेरे हल्के में सुंदर ब्रांच को लेकर सबसे बड़ी समस्या है वहां पानी नहीं आता है।

श्री राम किशन फौजी : सुंदर ब्रांच में पानी देने के लिए जब मैं चौटाला साहब से मिला था और उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे एम०एल०ए० होते हुए 400 किसानों के साथ जेल में ठोक दिया था। मैं खुद भी उन 400 लोगों के साथ जेल में गया था।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, सुन्दर ब्रांच से न केवल जींद और जुलाना को पानी जाता है बल्कि सुंदर ब्रांच हिसार के हल्के नारनौंद, बवानीखेड़ा और भिवानी जिले को भी पानी देती है। सुंदर ब्रांच की 2600 क्यूसिक की केपेसिटी है और इस साल वह दो दिन 2200

क्यूसिक कैपेसिटी पर चली है बाकी पिछले छह सालों में कभी भी 1100-1300 क्यूसिक से ज्यादा नहीं चली।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं आप चैक करवा लें, अगर किसी भी दिन इतने कम पानी से चली होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, यह विभाग की ही रिपोर्ट है कि यह ब्रांच दो दिन 2200 क्यूसिक चली है और बाकी दिन 1400-1600 क्यूसिक तक चली है। यह आपके विभाग ने दिखा रखी है। मैं गेज रीडर नहीं हूं। मेरे हल्के में भी कोई गेज रीडर नहीं है बल्कि वहां हैड्स लगे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, बेसिक इशू अंडरग्राउंड वाटर का था और वह इशू तो खत्म ही हो गया है, अन्य इशूज पर बात चलने लगी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी से अनुरोध है कि इसी विषय पर बात करें।

श्री अनिल धन्तौड़ी (शाहबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बहुत से सभासदों ने इस विषय पर अपने विचार रखे। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार दिन प्रति दिन जल का स्टोरेज करती जा रही है। हमसे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई और उन्होंने इसके ऊपर कोई काम किया या नहीं किया, ये वे खुद जानते होंगे। जब हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो बहुत अच्छी सोच से और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किए गए। अरावली क्षेत्र के अंदर भूमि जल भंडारण के सन्दर्भ में 50 करोड़ रुपये का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। महेन्द्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव, रिवाड़ी, फरीदाबाद, मेवात के अंदर वाटर हारवैस्टिंग चैक डैम बनाए जाएंगे और भविष्य के अंदर जैसा माननीय सदस्या कविता जैन ने कहा कि इससे विश्व युद्ध होने की संभावना है। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि जल की वजह से विश्व युद्ध न हो इसके लिए हरियाणा सरकार ने विभिन्न ड्रेनों के ऊपर ब्रिज का निर्माण किया है। झीलों और तालाबों को गहरा करने और रिचार्ज चैनलों का निर्माण करने का निर्णय लिया है, क्रॉस रैगुलेटरों का निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया है। छोटे चकबंदों, मिट्टी के बांधों तथा अन्य जल संरचनाओं का निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बरसाती पानी के संचय के लिए एवं अन्य प्रबंध करने के लिए बहुत सारे निर्णय लेगी। बरसाती पानी को संचय करने के लिए सरकार ने बहुत कार्य किया है। सरकार ने दादूपुर नलवी नहर और बी०एम०एल० हांसी बुटाना नहर के निर्माण की दशा में भी बहुत कार्य किया है। (विघ्न) मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री धर्मबीर सिंह (सोहना) : धन्यवाद स्पीकर सर। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है। इसके बारे में अलग-अलग सुझाव भी आए हैं। हरियाणा प्रदेश एक ऐसी जगह पर है जहां अपना

[श्री धर्मबीर सिंह]

कोई पानी नहीं है क्योंकि यमुना भी यू०पी० की तरफ है और पंजाब की बाकी नदियों का बहाव भी उन्हीं की तरफ है। हमें तो किराये का पानी मिलता है। फिर भी हमारी सरकार ने और हुड्डा साहब ने बहुत सोच समझ कर कई अच्छे स्टैप्स उठाये हैं। इनके बारे में मैं भी अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इस प्रदेश का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जहां ज्यादा पानी चलने की वजह से वाटर लौगिंग की समस्या हो गई है और वाटर लौगिंग की वजह से वह एरिया खराब हो चुका है। उसके कारण कुछ भी रहे हों। उदाहरण के तौर पर पुराना भाखड़ा मेन लाईन से जो पानी खासकर सिरसा की तरफ जाता रहा है उसकी वजह से पिछले 20-30 साल में जमीन खराब हो चुकी है। अब समय आ चुका है कि ज्यादा पानी उस इलाके में भेजा जाए जहां जमीन रिचार्ज भी हो जाये और वहां के लोगों को पानी भी मिल जाए। उदाहरण के तौर पर जो पुरानी नदियां हैं जिनसे अंग्रेजों के समय में नहर बनी थी चाहे वह सुन्दर नहर है या डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम है, अगर हम इनमें कई जगह पर जाकर देखें तो वहां वाटर लौगिंग ज्यादा होने की वजह से पानी का स्तर ऊपर आ चुका है। वहां से पानी निकाल कर उस पानी को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, इस बारे में आज सोचने की जरूरत है। (विघ्न) इस हाउस में सवा दो करोड़ जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं। एक तरफ तो ये यूनानीमसली प्रस्ताव पास करने की बात करते हैं चाहे एस०वाई०एल० के बारे में हो, या हांसी बुटाना लिंक नहर के बारे में हो हमें एक होकर इसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी तरफ इसी हाउस में अपना पक्ष कमजोर करने के लिए माजरा साहब पंजाब की भाषा बोलते हैं और इनकी वह भाषा बड़ी स्पष्ट है। जो टैक्नीकल बातें हैं या जो टैक्नीकल रिपोर्ट है उसको उल्टा सीधा कह कर हरियाणा का इस बारे में ये केस कमजोर कर रहे हैं। ये सी०डब्ल्यू०सी० द्वारा दी गयी रिपोर्ट को एक साजिश का हिस्सा बता रहे हैं ताकि पंजाब अपना पक्ष मजबूत कर ले और वह रिपोर्ट हमारे खिलाफ चली जाए। यह इस तरह की बातें करके उस क्षेत्र के लोगों की जहाँ हांसी बुटाना लिंक नहर के पानी की जरूरत है उनकी बातों को भी कमजोर कर रहे हैं। प्रदेश के काफी बड़े हिस्से को इस नहर के पानी की जरूरत है लेकिन ये उनके पक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। स्पीकर सर, आज वाटर लौगिंग की जरूरत है। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded whatever is spoken without my permission.

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो काम आज से 20-30 साल पहले हो जाना चाहिए था, शुक्र है भगवान का कि माननीय हुड्डा साहब ने पिछले चार-पांच साल में वह काम करवाया । इसी प्रकार से मैंने बजट में डब्ल्यू०जे०सी० वाटर के बारे में पढ़कर देखा था। जो वैस्टर्न जमुना कैनाल अंग्रेजों ने बनाई होगी उसके लिए लगभग 170 करोड़ रुपये का इस बात के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है कि इस वैस्टर्न जमुना कैनाल की हम कैपेसिटी बढ़ायेंगे ताकि वह पानी उस एरिया में जा सके जहां पीने का पानी नहीं है। नांगल चौधरी तक भी पीने का पानी नहीं है। दूसरी तरफ आपने और हमने सब ने और बहन कविता जी ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से उठाया कि हमें पानी को बचाने के लिए एग्रीकल्चर सैक्टर के माध्यम से किसानों को समझाना

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चाहिए कि वे ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर्स सैट के माध्यम से कम पानी से खेती करें जिससे पैदावार ज्यादा हो हमें ऐसे साधन अपनाने चाहिएं। इसके लिए कृषि मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस बार बजट में अच्छा प्रावधान किया है, जिससे हमें फायदा मिलेगा। पिछले दिनों विपक्ष की सरकार के दौरान हारवैस्टिंग स्कीम के कुछ ट्यूबवैल्ज लगे थे, शायद माजरा जी के पास यह महकमा था। हम हैरान इस बात के लिए हैं कि इस बार जब बाढ़ आई तो वे ट्यूबवैल्ज जो हारवैस्टिंग सिस्टम के लिए बने थे उनमें से किसी एक ने भी काम नहीं किया जबकि उसके पड़ौस में प्राईवेट लोगों ने अपने पैसे से जो कुएं बना रखे थे उनका प्रोजैक्ट बड़ा अच्छा रहा। इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनायें ताकि पानी का ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके। इसलिए मैं तो इस प्रस्ताव पर अपनी तरफ से यही बात कहना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है कि हमें पानी के बचाव की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि इस वर्ष को जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने का अभियान भी चलाया जा रहा है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस जल संरक्षण पर हम सब जरूर ध्यान दें।

श्री राजपाल मुखड़ी (सढ़ौरा, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण की बात यहां चल रही है। हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दादूपुर नलवी नहर बनवाई। हमारे जहां दादूपुर हैड, हथनीकुंड बैराज पर हजारों क्यूसिक पानी वेस्ट चला जाता था। जब पीछे से पानी ज्यादा आता था तो वह पानी यू०पी० में बह जाता था। दादूपुर नलवी नहर को बनाकर जल संरक्षण का बहुत बड़ा काम किया गया है। हमारे साथ लगते यमुनानगर, शाहबाद और आगे के जो भी एरियाज हैं जहां से यह नहर गुजरी है, इसके बनने से इन सारे क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। इस नहर पर हजारों-करोड़ों रुपये हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारी सरकार ने खर्च किए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हथनीकुंड बैराज से साढौरा, नारायणगढ़, मुलाना की तरफ से होती हुई एक और नहर निर्माण की परियोजना हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारी सरकार की है। दादूपुर हैड और हथनीकुंड बैराज में पीछे हिमाचल से जब पानी ज्यादा आता है तो उससे कई बार हमारे पूरे यमुनानगर को खतरा बन जाता है। इस नहर के बनने से उस खतरे से बचाव तो होगा ही और साथ ही इस नहर के बनने से जल संरक्षण का कार्य भी होने जा रहा है। जहां तक पानी के बचाव की बात कर रहे हैं तो मुझे याद है कि आज से दो प्लान पहले जब मैं लोक समिति का मैम्बर हुआ करता था, उस समय हमारे वहां एक स्कीम आई थी कि जो घरों का पानी है यानी जो घरों में यूज करते हैं उसमें बोरिंग करके उस पानी को अंडरग्राउंड ले जाया जाए और उस पानी को बचाया जाए ताकि हमारे भूमिगत जल स्तर का बचाव हो सके और उसको मेंटेन किया जा सके। ऐसे ऐसे काफी कार्य हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं। मैं इस बारे में यह भी कहूंगा कि पिछली ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में ऐसे कोई कार्य नहीं हुए, उनकी सरकार में न ऐसी कोई सोच बनाई गई और न ही कोई ऐसी नीति बनाई गई जिससे पानी का संरक्षण किया जा सके और फ्यूचर के लिए उसको मेंटेन किया जाए। आज बात की जाती है कि यह सरकार क्या कर रही है मेरा तो यह मानना है कि हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। आज से 40 वर्ष पहले तक का जो समय है यानी जब से हरियाणा बना है तब से किसी भी सरकार ने ऐसे कोई कार्य नहीं किये जैसे भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने किए हैं। जल संरक्षण के बारे में और नहरों के निर्माण के बारे में मैं यही सब कहना चाहूंगा और इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर।

मुख्य संसदीय सचिव (राव दान सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का समय दिया। यह सत्य है कि जल ही जीवन है और यह बात हर व्यक्ति जानता है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने जैसे ही सत्ता हासिल की थी उन्होंने पानी के महत्व को समझते हुए फ्लोर आफ दि हाउस कहा था कि मैं आज से पानी के समान बंटवारे का पक्षधर हूं। यहां पर इस बारे एक प्रस्ताव भी लाया गया था। अपनी उस मंशा को पूरी करने के लिए उन्होंने हांसी बुटाना लिंक नहर को बनाने का केवल प्रावधान ही नहीं किया बल्कि इसके लिए बजट एलोकेट करके काफी हद तक उसको पूरा भी कराने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं जहां 1400 फुट गहराई तक गीली मिट्टी भी नहीं निकलती। इस बजट के अंदर सहायक नदियों के तटबंधों को सुदृढ़ करने हेतु बाढ़ प्रबन्ध योजनाओं के लिए लगभग 175 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जबकि माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी सरकार के समय में सेम की समस्या से निपटने के लिए भी बहुत कम पैसे का प्रावधान किया था। एक तरफ सूखा है, एक तरफ गीला है तो मैं तो यह चाहूंगा हूं कि पूरा सदन इस पानी की समस्या के समाधान के लिए एक जुट होकर एक बात करे कि जहां पानी की कमी है वहां पानी पहुंचाया जाए और जहां पानी की बहुतायत है वहां पानी को कम करने का प्रसास किया जाए। इसके साथ साथ सरकार ने बहुत से और प्रावधान भी किए हैं जैसे कि जितने भी नये हाउसिज बन रहे हैं उनके अंदर वाटर हारवैस्टिंग के लिए प्रोविजन करना मंडेटरी कर दिया गया है और बिजली बचाने के लिए सोलर सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहता हूं कि हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझे। सरकार और मुख्यमंत्री जी की यह जिम्मेवारी नहीं है बल्कि यह सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जहां भी पानी बेकार जाता है उसको रोका जाये। कई जगहों पर मात्र दो-चार रुपये की टूटी न लगने के कारण सारे दिन पानी बेकार बह रहा होता है और जरूरतमंद लोग पानी से वंचित रह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ ऐसी लोक महत्व की चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस मंशा के साथ यह प्रस्ताव लाया गया है सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस पर गौर फरमायेंगे। धन्यवाद।

श्री जगदीश नैय्यर (होडल, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बड़ा सीरियस मैटर है और नदियों से जुड़ा हुआ अंडर ग्राउंड वाटर का मामला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश को आजाद हुए 62 साल और हरियाणा प्रदेश को बने हुए 44 साल हो गये। जबसे हमारा प्रदेश बना है तब से नेता लोग जनता को बड़ी-बड़ी दुहाई देते रहे हैं कि एस०वाई०एल० नहर बनेगी, यह नहर बनायेंगे, वह नहर बनायेंगे लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं है। मैं बड़े दु:ख के साथ इस विषय पर आ रहा हूं कि हमारे जिले मे आगरा कैनाल होकर गुजरती है उसका प्रबन्धन यू०पी० सरकार से हरियाणा सरकार के पास आज तक नहीं आया है। हमारे एरिया के सारे रजबाहे आगरा नहर से छटते हैं। जब से पिछले 6 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तबसे हमारी नदियों में पानी नहीं आया। उनमें बड़ी-बड़ी झाड़ियां खड़ी हैं और रजबाहे सूखे पड़े हैं। कई रजबाहों में तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। लोगों ने दूसरे कामों में उनको यूज करना शुरू कर दिया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उजीना ड्रेन में चलकर देख लें, झूठी बात कहने से बात नहीं बनती है। हमें यहां पब्लिक चुनकर भेजती है। आप लोग मेरे साथ चलकर उजीना ड्रेन को देखिये, वह बहुत चौड़ी बनाई गई थी.

आज उसमें पानी नाम की चीज नहीं है। ताऊ देवी लाल जी के टाईम में (विघ्न) उसको बहुत चौड़ा खोदा गया था। अध्यक्ष महोदय, हम पलवल और फरीदाबाद के बारे में कोई बात करते हैं तो ये लोग मजाक समझते हैं। (विघ्न) मेटर को सीरियसली नहीं लिया जाता।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, उजीना ड्रेन मेरे गांव से 100 मीटर से गुजरती है। मैं ईमानदारी के साथ हाउस में कहता हूं कि उजीना ड्रेन में बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए मैंने भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को दावत देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि इन्क्वायरी करवा लें अगर वहां बच्चे क्रिकेट खेलते हुए न मिल जायें तो मुझे जो सजा दी जायेगी वह मंजूर है।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी बड़ी बदनसीबी है कि जब हमारे एरिया की बात आती है (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात दोनों साथियों से कहना चाहूंगा कि शायद इनको मालूम नहीं है कि ड्रेन अलग चीज होती है और नहर अलग चीज होती है। ये लोग ड्रेन को नहर मान रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रिचार्जिंग आफ ग्राउंड अंडर वाटर के बारे में जो काम इनकी सरकार के समय में किए गये और जो काम हमारी सरकार के समय में किए गए उसके बारे में मैं सदन में जानकारी देना चाहूंगा। स्पीकर सर, इन्होंने अपने 6 सालों के शासन के दौरान केवल 6 स्कीमें ही अण्डर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए चलाई जिन पर कुल खर्च आया 1.92 करोड़ रुपये और वर्ष 2005 के बाद हमारी सरकार आने के बाद से अब तक हमने 457 करोड़ रुपये रिचार्जिंग स्कीमों के ऊपर खर्च किये। स्पीकर सर, हमने अपनी 20 स्कीमों को 176.54 करोड़ रुपये की लागत से कम्पलीट कर दिया है और लकरीबन 163.41 करोड़ रुपये की हमारी स्कीम्ज़ अण्डर प्रोग्रेस हैं। इसके अलावा हम 117 करोड़ रुपये की लागत से 17 ऐसी ही स्कीम्ज़ और प्रपोज़ कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं इनकी और अपनी स्कीम्ज़ को पढ़कर सुना सकता हूं। I can put it on record. (interrruption)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, **********

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, **********

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, **********

Mr. Speaker : Anything said without my permission should not be recorded. Hon'ble Members, we cannot record running commentaries. (Interruption) आप कहो मत। पहले मेरे से पूछो कि कहूं या नहीं कहूं। (Interruption) Anything said without my permission should not be recorded.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इन्होंने अपने शासनकाल में जो 6 स्कीम्ज़ रखी उनमें से पहली 10 लाख रुपये की लागत से करनाल में स्कीम बनाई गई इसी प्रकार से 40 लाख रुपये की लागत से पलवल में एक स्कीम बनाई, (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आश्चर्य की बात है कि ये अपनी स्कीमों के बारे में भी नहीं सुनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, **********

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, **********

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, **********

Mr. Speaker : Anything said without my prior permission not to be recorded. We cannot record running commentaries. (Interruption) माननीय सदस्यों, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि आप मेरी परमीशन के बगैर मत बोलो। आप पहले मुझसे पूछो कि मैं कुछ कहूं या न कहूं और अगर मैं परमीशन दूं तब ही बोलो। Anything said without my permission will not be recorded. Capt. Ajay Singh Yadav, you may please continue.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इसी प्रकार से क्रमश: 23 लाख, 29 लाख और 35 लाख रुपये की तीन स्कीमें महेन्द्रगढ़ में बनाई गई जिनकी टोटल कॉस्ट 98 लाख रुपये थी। इस प्रकार से इन्होंने ये 6 स्कीमें बनाई जिनके बारे में ये कंसर्न थे। इसके विपरीत हमने करनाल के अन्दर 80 लाख रुपये की स्कीम बनाई। इसी प्रकार की टोटल 20 मेजर स्कीम्ज़ हमने बनाई हैं। विपक्ष के साथी क्षेत्रीय भेदभाव का आरोप भी हमारी जनप्रिय सरकार के ऊपर लगाते हैं इसलिए मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि हमने सिरसा के अन्दर भी अनेकों स्कीमें बनाई हैं जिनमें से एक आर्टिफिशियल रिचार्जिंग स्कीम हनौरी ड्रेन की बनाई है जिस पर 80 लाख रुपये की लागत आई है। हमने यमुनानगर और करनाल में 50 लाख रुपये की लागत से एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल्ज़ से आर्टिफिशियल रिचार्जिंग स्कीम बनाई है। इसी प्रकार से हमने पानीपत में 50 रिचार्जिंग स्टॉक्स 16 लाख रुपये की लागत से बनाये हैं। इसी प्रकार से जो दादुपुर-नलवी प्रोजैक्ट है इस पर हम 112 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और इस स्कीम की टोटल कॉस्ट 266 करोड़ रुपये है। पिछले 20 साल से इस स्कीम के बारे में सिर्फ चर्चा ही की जा रही थी। इस बारे में मैं कल हाउस में डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा Scheme for custody humps के तहत हमने नूंह और उजीना ड्रेन में 36 लाख रुपये की लागत से अप्रैल, 2010 में हम्प्स बनाये हैं। इसके साथ-साथ सोनीपत के अन्दर डाईवर्शन ड्रेन के ऊपर 5.54 लाख रुपये की लागत से एक रेगुलेटर लगाया गया है। इसके अलावा सिरसा जिले में 13.35 करोड़ रुपये की लागत से मंगला डायरेक्ट माईनर का निर्माण किया गया है। स्पीकर सर, मैं ये सारी स्कीमें सिरसा जिला की गिनवा रहा हूं। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन ऑफ घग्गर ड्रेन वह भी सिरसा के अन्दर है। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन ऑफ भागसर माईनर यह भी सिरसा जिले के अन्दर है और कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल सिरसा चैनल सिरसा के अन्दर हैं। ये दोनों स्कीमें 14 करोड़ और 9 करोड़ रुपये की हैं जो कि कुल मिलाकर 23 करोड़ रुपये की बनती हैं। इसके अलावा संतनगर माईनर है जो कि सिरसा के अन्दर है और इस पर 64 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह भी हमने कम्पलीट की है। इसी प्रकार से पोखरण माईनर है जो कि सिरसा जिले में है जिसे हमने ही कम्पलीट किया है जिस पर लागत 256 लाख रुपये आई है। ऐसे ही न्यू कैथल माईनर भी सिरसा में है जिसका निर्माण हमारी सरकार द्वारा किया गया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सिरसा के अन्दर ही हमने कैथल ड्रेन के अन्दर 20.23 लाख रुपये की लागत से तीन हम्प्स

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

बनाये हैं। इस प्रकार से हम अभी तक टोटल 176 करोड़ रुपये का काम कर चुके हैं। इसी प्रकार से ओटू झील की हमारी स्कीम 67 करोड़ रुपये की है। (विघ्न)

Mr. Speaker : As Hon'ble Minister is speaking, no interruption please.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इसके अलावा हमने मसानी बैराज की स्कीम भी 11 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की है। इन सबके अलावा भी हमारी बहुत सारी स्कीम्ज़ ऐसी हैं जो कि अण्डर प्रोग्रेस हैं जिनकी कुल लागत लगभग 163 करोड़ रुपये है जिनमें भिण्डावास लेक की डीपनिंग का काम है, जिस पर 47 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार से जिला झज्जर में खापरवास लेक की डीपनिंग की स्कीम है जिस पर 46 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार से एस.के. ब्रदर, लोहारु की स्कीम है। हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री के रिचार्जिंग चैनल के कंस्ट्रक्शन की भी स्कीम है जिस पर लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार से ओटू वियर की डीपनिंग की स्कीम है जोकि 59 करोड़ 68 लाख रुपये की है। इसी प्रकार से जो स्कीमें हम प्रपोज कर रहे हैं वे हैं पानीपत में सरदाना कैनाल जो कि 46 लाख रुपये की स्कीम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन हारवैस्टिंग पौंड बिहोली, जिला पानीपत की स्कीम 32 लाख रुपये की है। पानीपत में ही एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल पर 1.30 करोड़ रुपये की स्कीम है। इसी प्रकार से पलवल में एक जगह है ड्रेन नीयर पंगाल्लू यह 26 लाख रुपये की है।

श्री जगदीश नैय्यर : सर, यह क्या स्कीम है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : इस स्कीम का नाम कंस्ट्रक्टिंग ऑफ हम्प्स है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्जिंग पौंड सोनीपत में गन्नौर डिस्ट्रीब्यूट्री पर 71 लाख की स्कीम है। सिरसा में कस्बा माईनर 3 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से बन रहा है। इसी प्रकार से रतिया खरीफ चैनल है जो 71 लाख रुपये की लागत से हमने प्रपोज किया है जिसमें खरीफ चैनल है जो कि आर.डी. 11800 से टेक ऑफ करके घग्गर में मिलेगा। इसकी बहुत पुरानी माँग थी। इस बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री ने भी हमारे मुख्य मंत्री से बात की थी। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलाना खरीफ चैनल सिरसा में 20 करोड़ रुपये की लागत से हम प्रपोज कर रहे हैं। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन ऑफ धोतर माईनर सिरसा में है जिस पर 4.40 लाख रुपये की लागत आयेगी। डीपनिंग ऑफ शेरांवाली पैदल चैनल 3 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से बनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यों में से जब कोई डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करता है तो आप कहते हैं कि यह विषय नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये सभी रिचार्जिंग चैनल हैं। इसी प्रकार से जिला महेन्द्रगढ़ में 1.64 लाख रुपये की कादमा माईनर है। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्जिंग रिजरवायर महेन्द्रगढ़ कैनाल में 2 करोड़ 39 लाख रुपये की है। बजीन में सतनाली फीडर पर एक रिचार्जिंग चैनल 94 लाख रुपये का बन रहा है। इसी प्रकार से एक लैट्रल सॉफ्ट टर्न्ज आर्टीफिशियल 117 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कुल 457 करोड़ रुपये हमने इन कामों पर खर्च किये हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके समय में जो मेजर प्रोजैक्टस थे उन पर 524 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

हमारी सरकार के समय में 2325 करोड़ रुपये मेजर प्रोजैक्टस पर खर्च किये गए हैं। इसी प्रकार से वाटर कोर्सिज इनके समय में 540 किलोमीटर बने और हमारे समय में 4947 किलोमीटर बने। उसी प्रकार से इनके समय में माईनरों पर 240 करोड़ रुपये खर्च किये गये और हमारे समय में 797 करोड़ रुपये खर्च किये गये। अध्यक्ष महोदय, 1966 से 2005 तक सिंचाई विभाग का जो खर्च हुआ है वह 7380 करोड़ रुपये है जबकि हमारे समय में 2005 से लेकर अब तक 8087 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, very serious issue has been raised by Shri Rampal Majra and very healthy discussion is taking place. Good suggestions are coming. Instead of leveling allegations, we should talk of facts. It is a very serious issue. The Hon'ble Leader of the House has declared this year as 'Jal Sanrakshan Year'. That means the Government takes this issue very seriously and anybody who is talking here should not talk outside this issue and should not laugh rather give good suggestions. Good suggestions are coming in but sometimes issues are disgraced, which is not good, which is not healthy also. Shri Ajay Singh Chautala wanted to say something. (Interruption) You still want to say something..

Shri Jagbir Singh Malik (Gohana) : Speaker Sir, in this Bill it is mentioned that "to introduce underground water control and Regulation Bill so that exploitation of underground water can be stopped/regulated." यह बिल अण्डर ग्राउंड वाटर जो एक्सिस्ट करता है उसकी एक्सप्लायटेशन न हो सिर्फ इस बात के लिये है इसलिए इसमें रिचार्ज शब्द और जोड़ा जाये कि - 'Recharge Under Ground Water and its control'.

Mr. Speaker : Yes, this is a very important and significant suggestion.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सरफेस वाटर के बारे में माजरा जी ने इतना लम्बा भाषण दे दिया कि इन नदियों का जल यह हो गया, वह हो गया, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इस तरह से उनके द्वारा हाउस का टाईम खराब करने वाली बात है। इसमें इस लिमिट तक यह इंट्रोडयूज किया जाए।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, that is a very good suggestion.

विधायकों को सुविधाएं देने सम्बन्धी मामला

डॉ. अजय सिंह चौटाला (डबवाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने और सदन ने इस बात को महसूस किया है कि लोक महत्व के मुद्दों पर हमें सीरियस बात करनी चाहिए और जो यह सदन है वह इसीलिए है कि हम जनता की तकलीफों को यहां पर उठाएं। बार-बार हम अपने इशु से भटककर दूसरी बातें करते हैं जिससे जहां सदन का समय जाया होता है वहीं कहीं न कहीं हम लोग भी मजाक का पात्र बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे सदस्य नये हैं उनको हाउस के तौर तरीकों का ज्ञान नहीं है। पहले भी इस सम्मानित सदन में इस बात की

चर्चा हुई थी कि नये सदस्यों के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए कि वह किस तरह के इशुज किस तरीके से उठाएं और सरकार को भी यह हिदायत दी जाए कि वह गैर जरूरी बातें न करे। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से बात ठीक से चलती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी इस भावना को समझेंगे। अगर आप इस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे तो उसमें हमारे सदस्य भी आएंगे और आप उधर के सदस्यों को भी उसमें बुला लें। आप इस तरह का माहौल यहां पर तैयार करें ताकि वह पुरानी कड़वाहट- कि तूने क्या किया हमने क्या किया और हम क्या करने जा रहे हैं, वह न हो। हम प्रदेश के हित की बात करें ताकि प्रदेश के लोगों को भी कोई सुविधा मिले। जहां तक बार बार गाली निकालने वाली बात है यह तो हम बहुत से मंचों से करते हैं, हमारे पास बड़े बड़े प्लेटफार्म है जहां पर हम इन बातों पर चर्चा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसकी तरफ ध्यान देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अजय सिंह चौटाला जी ने एक सुझाव ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में दिया है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी जब गवर्नर एड्रेस पर चर्चा हुई थी तो उस समय भारत भूषण बत्तरा जी ने तथा दूसरे और सदस्यों ने भी यही सुझाव दिया था, अब मैं भी इससे अपने आपको जोड़ता हूं। सर, सरकार यह समझती है कि आपके दिशा निर्देश के अनुसार विधान सभा सैक्रेटेरिएट इस प्रकार का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला लें क्योंकि यह बहुत अच्छा सुझाव है। इससे मैं भी सहमत हूं। जो नये सदस्य हैं उनके लिए भी और यदि कोई पुराना सदस्य भी यह प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहे तो उनका भी इसमें स्वागत है, इसमें क्या दिक्कत है।

Mr. Speaker : Very well said by both the sides.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सुझाव को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अन्दर दो तीन तरह के लोग शामिल हो जाएं। आप इसके लिए पार्लियामैंट्री प्रैक्टिसिज के सब्जैक्ट आईडैन्टीफाईड कर दें, विषय आईडैन्टीफाईड कर दें।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें राजनीति न हो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट आईडैन्टीफाईड करके इस प्रोग्राम में कुछ केन्द्रीय सरकार के अन्दर से भी और कुछ संसद से भी जो बड़े बड़े मशहूर पार्लियामैंटेरियन रहे हैं, उनको बुला लिया जाए तथा कुछ कांस्टीच्यूशनल लॉ के नोन प्रोफेसर और कुछ दूसरे संसदीय कार्य प्रणाली की सोच रखने वाले शिक्षाविदों को भी बुला लिया जाए। इनके अलावा इस प्रोग्राम में कुछ राजनैतिक दलों के लोगों को भी जिनको आप उचित समझें उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक बुला लें। विषय आईडैंटीफाईड हो जाएं तो यह ट्रेनिंग प्रोग्राम बाकायदा विधान सभा सैक्रेटेरिएट के अन्दर या जहां पर आप उचित समझें हो सकता है। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है इसलिए मुझे लगता है कि इसका क्रियान्वयन करना वाजिब रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अजय सिंह जी की एक और बात से सहमत हूं कि यह सदन एक गंभीर सदन है और आपने भी जिस दिन यह कुर्सी सम्भाली थी तथा जब इस सदन ने संयुक्त तरीके से आपको निर्वाचित किया था तो आपने भी कहा था कि हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव सुझाव आएं। मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आलोचना अगर आलोचना के लिए न हो तो ठीक रहता है क्योंकि we can also be wrong some time.

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

Sir, we cannot right all the times. कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमेशा ठीक हो, कभी न कभी, कहीं न कहीं हर व्यक्ति गलत हो सकता है। सरकार की नीतियों के अंदर कहीं कमी है तो मुख्यमंत्री जी बार बार कह चुके हैं, मैं भी कई बार कह चुका हूं कि हम उसको दुरुस्त करेंगे। सुझाव चाहे कंस्ट्रक्टिव आएं चाहे क्रीटिकल सुझाव भी आएं तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हम उनको फौलो करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं सरकार की तरफ से आपको और इस सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती अनीता यादव) : स्पीकर सर, जो बात चल रही है उसमें मैं भी एक बात की चर्चा करना चाहूंगी कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जब वर्ष 2000-2005 में चीफ मिनिस्टर थे तब इन्होंने मैम्बर्स के लिए कम्प्यूटर ट्रेनिंग सैक्रेटेरियट में शुरू की थी, उस समय हमारे जैसे नये मैम्बर सदन में चुनकर आये थे, उनको उस ट्रेनिंग से काफी बल मिला था और हमें कम्प्यूटर भी दिये गये थे। मेरा सुझाव है कि अब की बार जो नये साथी विधान सभा में चुनकर आए हैं उनके लिए भी उसी तरह से कम्प्यूटर ट्रेनिंग चलाएं।

Mr. Speaker : Some more suggestions I would expect from the Members. After the suggestions have come, the reply will be given. जो बात सदन में चल रही है ऐसी बातें पहली बार यहां सुनी जा रही हैं।

श्री भारत भूषण बत्तरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल पहले 35 विधायकों ने लैपटॉप प्रदान करने बारे अपने हस्ताक्षर करके तत्कालीन अध्यक्ष महोदय श्री चट्ठा साहब को पत्र लिखा था। वे इस समय यहां बैठे नहीं हैं। बैठे होते तो मैं उनको कहना चाहता था कि उनको अब तक लैपटॉप नहीं दिये गये हैं। रूल्ज़ में इनके लिए प्रोविजन है और बजट भी आने वाला है वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं इसलिए कृपया सभी को जल्द से जल्द लैपटॉप दिलवाएं।

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सब्जेक्ट पर दो शब्द कहना चाहूंगा । जैसे अभी श्री अजय चौटाला जी ने सुझाव दिया, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर साहब ने सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादातर सदस्य यहां लेजिस्लेशन के लिए ही आते हैं। मैंने इस बारे में एक चिट्ठी चीफ सैक्रेटरी को भी लिखी थी और उसमें सुझाव दिया था कि जो बिल विधान सभा के अन्दर आते हैं वह विधायकों के पास कम से कम एक हफ्ते पहले आना चाहिए ताकि सभी उसको ठीक तरीके से पढ़ सकें। जो अमैंडमैंट आती हैं उनके साथ मैंबर एक्ट और छोटा एक्ट भेजा जाए। अदरवाइज अभी तक तो एक लाइन की अमैंडमैंट आ जाती है और सदस्यों को उसकी बैकग्राउंड तक का पता नहीं होता कि क्या अमैंडमैंट आ रही है और उस अमैंडमैंट पर क्या बोलना है। जब स्पीकर साहब का चुनाव हुआ तो सभी थैंक्स कर रहे थे। आज हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री संपत सिंह जी गैर हाजिर हैं, उन्होंने इस बारे में सदन में सुझाव दिया था और कैप्टन अजय सिंह ने भी सुझाव दिया था कि नये सदस्यों को कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि नये सदस्यों को तो सीखने की जरूरत है साथ ही पुराने सदस्य जिनको मर्यादाओं का ज्यादा ज्ञान है, वे भी समय समय पर मर्यादा तोड़ते हैं, मेरा निवेदन है कि जो कैम्प लगे उसमें इन बातों पर भी सुझाव दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Are you not happy in this way the House is being conducted ? I think the House is going well, Mr. Barshami.

श्री शेर सिंह बड़शामी : बिल्कुल ठीक चल रहा है सर। मैं कह रहा था कि उन वरिष्ठ साथियों पर भी लगाम लगनी चाहिए। एक सुझाव और है कि विधान सभा के अन्दर हमारे विधायकों में किसी ने पासपोर्ट बनवाना है, वीजा लगवाना है उसके लिए एजेंटों के धक्के खाने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे एक अनुरोध है कि विधानसभा के अन्दर एक विंग कायम की जाए जो विधायकों के पासपोर्ट बनवाये और जो विधायकों के वीजा लगवाने का प्रबन्ध भी करवा सके क्योंकि विधायक अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए और वीजा लगवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के लिए धक्के खाते रहते हैं।

Mr. Speaker : You mean to say that there should be a Protocol Officer in Haryana Vidhan Sabha. (Interruption) जो अजय चौटाला जी ने सुझाव दिया वैसा सुझाव किसी ने नहीं दिया। उन्होंने इस विषय पर बहुत अच्छी डिबेट और सुझाव दिया है।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जिस प्रकार क्वैश्चन आवर के लिए एक घण्टा फिक्स किया हुआ है उसी प्रकार से बिल पर विस्तार से डिस्कशन करने के लिए भी आधा या पौन घण्टा फिक्स करना चाहिए। बिल की इन्ट्रोडक्शन पहले हो जाये चर्चा और बिल पास चाहे आखिर में कर दिये जायें।

Mr. Speaker : Mr. Parliamentary Affairs Minister may please note down this point.

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सुझाव देना चाहती हूं जिससे सारा सदन लाभान्वित होगा। जैसे क्वैश्चन आवर के बाद जीरो आवर में माननीय सदस्य अपने हल्के की समस्याओं के बारे में नोटिस देते हैं उसी प्रकार से वह रिटन नोटिस दे दें so that they can be read out on the floor of the House and become part of the proceedings of the House. It is not upon Government, upon Minister to answer or not to answer because this is a healthy precedent and most of the Assemblies follow this precedent. Something like this should be done here. जो भी उसके इलाके की ज्वलन्त समस्याएं हैं उनके बारे में नोटिस दे दें so that it can come to the notice of the concerned Minister और उसको रिटन ओर्डर के माध्यम से उसका जवाब दे दिया जाए।

Mr. Speaker : Hon'ble Parlaimentary Affairs Minister may please note down this point regarding laptops.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री अजय चौटाला जी ने ओरियण्टेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए अपना सुझाव दिया है यह बिल्कुल सही बात है। जिस दिन स्पीकर का इलैक्शन हुआ था और अध्यक्ष महोदय आप सर्वसम्मति से स्पीकर के पद पर चुने गये थे तो आपके धन्यवाद प्रस्ताव में मैंने भी यही सुझाव दिया था। दूसरी बात यहां लैपटॉप के बारे में कही गई है। आपका आफिस वित्त विभाग को प्रोपोजल बनाकर भेज दे तो यह प्रोपोजल अवश्य पास कर दिया जायेगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Parlaimentary Affairs minister may please note down this point.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, the Hon'ble Finance Minister has already cleared this and Hon'ble Finance Minister has to sanction the money.

Mr. Speaker : Has he agreed to sanction the money ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, he has agreed to sanction.

Mr. Speaker : O.K. Capt. Sahib, when these laptops will be provided to the Members ?

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, the moment the case comes to me. अध्यक्ष महोदय, जो नये एम.एल.एज. हैं उनके लिये ओरियण्टेशन प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह ओरियण्टेशन प्रोग्राम चले ताकि नये एम.एल.एज. को हाउस के बारे में नया ज्ञान हो। पिछली बार जब यह सरकार पहली बार चुनकर आई थी उस समय भी यह प्रोग्राम चलाया गया था।

Mr. Speaker : I will send a proposal to you and you in consultation with the Parliamentary Affairs Minister, may kindly do it at the earliest and at the same time the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will in his reply suggest, if you give laptops, how they will be used ?

श्री आनन्द कौशिक (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि श्री अजय चौटाला जी ने यहां अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन जिस दिन आप सर्वसम्मति से स्पीकर के पद के लिए चुने गये थे उस दिन हमें यह लगा था कि आप कुछ अच्छी परम्पराएं यहां रखेंगे और उसी का ही नतीजा है कि आज यहां सुधार ज्यादा दिखा है। जिस साइड से शोर शराबे की उम्मीद की जा सकती थी ..... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : As it is a very serious discussion, no insinuation, please.

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जल संरक्षण के बारे में भी अपनी बात कर सकता हूं।

Mr. Speaker : No insinuations, please.

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि सब को लैपटॉप मिले, ट्रेनिंग सैंटर चलाए जाएं ताकि सभी मैम्बर्ज यहां अच्छी और सभ्य बात करें और रचनात्मक कार्यों के लिए ही यहां पर बोलें। हरियाणा के लोगों को इन मैम्बर्ज से जो उम्मीदें होती हैं उन उम्मीदों पर हम सभी मैम्बर्ज खरे उतर सकें।

Mr. Speaker : Next Mr. Bishan Lal Saini Ji. Saini Ji, speak only on this issue please.

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, अब तो रैजोल्यूशन पास करवा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री विशनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी एक बात सुन लें। (Interruption) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिस है कि आप एक बार एम.एल.ए. होस्टल का दौरा करें और वहां जाकर हमारी दुर्व्यवस्था देखें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It is for the information of this House that I visited the MLAs Hostel yesterday and today also and I will continue to do so, so that we can improve the living conditions of the Hon'ble Members of this House. It is under the consideration of the Government of Haryana. I have already spoken to them to take steps regarding furnishing, making it a little comfortable for Members. Saini Sahib, tomorrow I am coming to your room also.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से यहीं पर ही इस बारे में हां भरवा लें।

Mr. Speaker : The Hon'ble Minister will examine it. So many Members have spoken. Mr. Dangi suggests let there be no further discussion. Now, Hon'ble Minister please.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि जिस मान मर्यादा के साथ हमारा सदन चलना चाहिये और बहुत अच्छी परम्परा यहां शुरू हुई है इसका हम स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : किसने शुरू कि यह परम्परा ? Who suggested it ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है।

Mr. Speaker : Give it to Dr. Ajay Singh Chautala today. He has come with this suggestion.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए सारा क्रेडिट आपको जाता है। अजय चौटाला जी ने भी ये बातें कहकर बहुत अच्छी परम्परा की शुरुआत की है।

श्री अध्यक्ष : आप इसके लिए अजय चौटाला जी को भी एप्रीसिएट करो।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अजय चौटाला जी ने अच्छी परम्परा की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से यहां जो भी चर्चा हो उस बारे हैल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। जब भी विधान सभा का सत्र शुरू होता है सभी की निगाहें इस ओर लगी होती हैं। हर व्यक्ति चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वोटर हो या स्पोर्टर हो या न हो उसकी निगाह बजट सत्र पर होती है। वह सोचता है कि जब इस तरह के सत्र होंगे तो क्या चीज अल्टीमेटली निकलकर आएगी। अध्यक्ष महोदय, यहां हर विभाग की हर विषय की, आम जुड़े हुए नागरिक की चिन्ता के बारे में चर्चा होती है इसलिये यहां से एक अच्छा मैसेज बाहर जाना चाहिए। यहां की हर चर्चा का इम्पैक्ट बाहर जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो यहां लैप टॉप देने का डिसीजन लिया गया है इस बात के लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। हम इस विधान सभा में 2005 में नए सदस्य के रूप में चुनकर आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की थी। हम नए सदस्यों ने वह ट्रेनिंग प्रोग्राम अटैंड किया था। बहन अनीता जी हमसे एक प्लान पहले चुनकर आई हुई हैं। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री जी ने यह भी बताया कि पहले भी लैपटॉप दिये गये थे और कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई थी। हमारे सभी सम्मानित सदस्य चण्डीगढ़ में कमेटी की मीटिंग्ज अटैंड करने आते हैं। ये मीटिंग्ज अक्सर मंगलवार, बुधवार या किसी भी दिन होती हैं तो उन्हीं दिनों के दौरान आई. टी. विभाग ये

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि गवर्नमैंट की जो पॉलिसी और प्रोग्राम हैं वे बनने के बाद अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सभी को इनके बारे में पता चल जाता है। हमारे सभी सम्मानित सदस्य जो प्रश्न पूछना चाह रहे होते हैं अगर वे खुद भी उसकी तैयारी करके आएं कि हमारा प्रश्न क्या है और उनकी क्या सप्लीमैंट्रीज हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट सजैशन यह है कि जो प्रश्न लिस्ट प्रश्न काल के लिए होती है वह हमारे सभी सम्मानित सदस्य एक समय सीमा में दे दें ताकि वे टाइम पर सभी विभागों को भेजे जा सकें और समय पर उनकी रिप्लाई आ सके। अध्यक्ष महोदय, यह भी डिसीजन हो जाना चाहिये कि कौन से प्रश्न तारांकित हैं और कौन से प्रश्न अतारांकित हैं क्योंकि कई बार लास्ट मोमैंट पर इस तरह के प्रश्नों को लेकर कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। भाई अजय सिंह चौटाला जी ने एक अच्छी शुरूआत की है हम उसका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। मंत्री जी ने यहां लैपटॉप देने की बात कही तो मैं कहना चाहूंगी कि ये सभी सम्मानित सदस्यों को समय पर मिल जाएं। अभी सुमिता सिंह जी पीछे से कह रही थी कि जो लैपटॉप दिए जाएं वे नई टैक्नोलोजी के हों तो मैं चाहूंगी कि मैम्बर्ज को मिलने वाले कम्प्यूटर नई टैक्नोलोजी के हों। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक मिनट बोलने का समय दिया। * * *

Mr. Speaker : This is not a relating issue. Please not to be recorded outside the issue.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम किशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय, भाई अजय चौटाला जी ने बहुत अच्छी बात की है। इससे हरियाणा प्रदेश की जनता में अच्छा संदेश जायेगा। इस पर लोग भी अमल करें और हमें भी अमल करना चाहिए। शुरुआत करने पर ही अमल होता है। अध्यक्ष महोदय, सैशन के पहले दिन मैंने कहा था कि आपने सबकी कुण्डली देख ली और सदन में सही काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने सबकी देख ली थी लेकिन अपनी नहीं देखी।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, आपकी हमने देख ली। मेरा सुझाव यह है कि लैपटॉप के साथ प्रिंटर भी दिए जायें। कहीं ऐसा न हो कि केवल लैपटॉप ही पकड़ा दिया जाए।

श्री अनिल धनतौड़ी (शाहबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मैंबर बड़शामी जी ने पासपोर्ट के बारे में बात की है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मिनिस्टर्ज के पासपोर्ट डिप्लोमैटिक होते हैं उसी तरह से विधायकों के पासपोर्ट भी डिप्लोमैटिक होने चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले अमेरिका टूर पर गया था वहां जो दूसरे देशों के विधायक और लैजीस्लेटर थे उनके पासपोर्ट डिप्लोमैटिक बने हुए थे।

श्री राम किशन गुर्जर (नारायणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, भाई अजय जी ने जो शुरूआत की है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने उसको

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

बढ़ावा देकर सभी सदस्यों से राय मांगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे एक मुस्लिम भाई जो इस सदन के सदस्य हैं वे लॉबी में नमाज अदा कर रहे थे लेकिन वे जिस स्थान पर नमाज अदा कर रहे थे वह स्थान मुझे नमाज के लिए ठीक नहीं लगा इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहां पर विधान सभा के सदस्यों व कर्मचारियों के लिए नमाज के लिए उचित जगह की व्यवस्था की जाये.

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी, आपका सुझाव अच्छा है। पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर इसको नोट कर लें।

मुख्य संसदीय सचिव (राव दान सिंह) : अध्यक्ष महादय, आज भाई अजय चौटाला जी ने एक अच्छी पहल करके अच्छी शुरूआत की है क्योंकि यह सदन ही है जहां पर स्वस्थ परम्पराओं की अपेक्षा जनता हमसे करती है। वरना इसी सदन में मैंने देखा है कि विपक्ष के सदस्यों को दो-तीन मिनट से ज्यादा समय अपनी बात कहने के लिए नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, आपने और सदन के नेता ने बड़ी दरियादिली से विपक्ष के साथियों को सुना भी है और पूरा समय भी दिया है। हमने यहां यह भी देखा है कि जब विपक्ष के साथी कहते थे कि हमें बोलने के लिए समय क्यों नहीं दिया जाता तो जवाब मिलता था कि आपके समय में से 5 मिनट का समय दिया जाता है, हमने तो फिर भी 10 मिनट का समय दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, यानि स्वस्थ परम्पराएं कहीं से तो शुरू होंगी things cannot make one right. अगर एक पांच मिनट देता है तो दूसरा 10 मिनट दे देता है तो उसने बहुत बड़ी बात की है। मेरा सुझाव यह है कि सदन की समय सीमा को भी लम्बा किया जाये ताकि सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिले और यहां की जो परम्पराएं हैं उनके लिए ओरिएण्टेशन प्रोग्राम लगाया जाए ताकि सदन में नई शुरुआत हो। धन्यवाद।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष जी, एम.एल.एज. होस्टल, हरियाणा में एम.एल.ए. कम और एम.एल.एज. का स्टाफ ज्यादा रहता है। अगर आप एम.एल.ए. हॉस्टल को रैनोवेट करने जा रहे हैं तो जो एम.एल.एज. फ्लैट्स में रहते हैं और जिन एम.एल.एज. के पास फ्लैट्स नहीं है उनके स्टाफ के ठहरने का भी कोई न कोई अरेजमैंट जरूर करें। धन्यवाद।

Mr. Speaker : This is a very good suggestion. Hon'ble Parliamentary Minister may please note. Please let me make an observation. (Interruption) You are not allowing me to make an observation. Please let me do it. (Interruption) Hon'ble Members, not only this that a suggestion has come from Smt. Sumita Singh regarding the residence and residential problems of Hon'ble Members because they have also their secretarial staff with them, they have their security officials, they have other supporters coming in. Hon'ble Parliamentary Affairs Minister may kindly initiate steps so that we can have more flats for our MLAs. Secondly it is also a matter of concern that where the staff accompanying with a Hon'ble Legislator should stay? So, we should also look into this aspect. If, we cannot give a positive assurance today let it be examined at least and before the end of this Session, some concrete suggestions should come. Now, Shri Anil Vij, may please speak.

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : स्पीकर सर, यहां पर विधायकों की तकलीफों के बारे में चर्चा हो रही है और एम.एल.एज. हॉस्टल में सुविधाओं के बारे में भी चर्चा हो रही है मैं इन बातों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि ये सुविधायें अगर कम भी मिल जायें तो भी गुजारा चल सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता हमें बड़ी उम्मीदों के साथ चुनकर भेजती है और जनता हमसे काम चाहती है। हमारे पास रोज़ाना अनेकों लोग अपनी ग्रिवैंसिज लेकर आते हैं। हमारे पास लोगों की समस्याओं से सम्बन्धित अनेकों पत्र आते हैं। जब लोग अपनी अनेकों प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आते हैं और जब हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में अधिकारियों को लिखते हैं तो आप यकीन मानिए हमारे किसी भी पत्र का जवाब हमारे पास नहीं आता। एक एम.एल.ए. को चीफ सैक्रेटरी से ऊपर का प्रोटोकोल दिया गया है लेकिन एक क्लर्क भी एम.एल.ए. के पत्र का जवाब नहीं देता। इस बारे में मेरा यह कहना है कि एम.एल.ए. की डिग्निटी को देखते हुए, जनता के प्रति उनके दायित्व और जिम्मेदारियों को देखते हुए डिसिप्लनरी एक्शन का एक कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी एक एम.एल.ए. की चिट्ठी का सात दिन, 10 दिन या 15 दिन के लिमिटिड पीरियड के अन्दर जवाब नहीं देता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

Mr. Speaker : Hon'ble Parliamentary Affairs Minister kindly note that in Parliament there is a settled Government arrangement. If an Hon'ble Member of Parliament writes even to the Minister and which is not replied to, then it becomes a matter of privilege. If a Member of Parliament writes to an officer or for that matter to a Minister and it is not replied to, then he can send it to the Privileges Committee. This procedure is adopted in Parliament and I don't know what the procedure here is? Mr. Anil Vij, has given a very good suggestion and if a Member of Legislative Assembly who has been elected, he writes to an officer and he does not get a reply, this is a very serious issue. Hon'ble Parliamentary Affairs Minister may kindly note it.

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : स्पीकर सर, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगी कि जब डिस्ट्रिक्ट लैवल पर किसी सरकारी या गैर सरकारी मीटिंग का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है तो उसमें लोकल एम.एल.ए. को भी आमंत्रित किया जाता है लेकिन अगर किन्हीं कारणों से वह मीटिंग कैंसिल या पोस्टपोन हो जाती है तो उसकी सूचना सम्बन्धित एम.एल.ए. को नहीं दी जाती जिससे बहुत भारी असुविधा होती है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस प्रकार की मीटिंग की कैंसलेशन और पोस्टपोनमैंट की सूचना सम्बन्धित एम.एल.ए. को समय पर दी जाये ताकि उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। धन्यवाद।

लोक निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. (बी एण्ड आर) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस में विशेष तौर से दो विषयों पर एक सकारात्मक डिबेट हुई। किस प्रकार से हम प्रजातंत्र में स्वस्थ संसदीय प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं और अपने कर्त्तव्यों और अपनी जिम्मेवारियों दोनों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे एक माननीय सदस्य ने श्री अजय सिंह जी के बाद पहला सुझाव कम्प्यूटर के बारे में दिया और श्री रामकिशन फौजी ने प्रिंटर के बारे में अपना सुझाव दिया है और आपने भी दिया है। इसी प्रकार से ट्रेनिंग के बारे में भी कई सदस्यों ने कहा है। यह सच है कि 21वीं सदी में और जब से स्वर्गीय राजीव जी

ने इस देश में कम्प्यूटर युग की शुरूआत की थी, आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गये हैं कि 21वीं सदी में जो 2020 तक एक नई तरह के इल्लीट्रेटस पूरी दुनिया में पैदा होंगे they will be computer illiterates. हमें कम से कम अपने विधायकों और विधायकों के साथ साथ हरियाणा के सब लोगों को और खास तौर से अगली पीढ़ी को इसके लिए लैस करना है। अध्यक्ष महोदय, जो विषय चर्चा में था उस पर 8-9 सुझाव आये हैं मैं उनकी बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। इसमें पहला सुझाव ट्रेनिंग का है। उस बारे में मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि हम भी इस बात से सहमत हैं। उसका एक मोडयूंल आप तैयार कर लें, आपकी अध्यक्षता में वह तैयार हो जाए। उसमें नये सदस्य भी आयें और सभी सदस्यों को नोटिस भेज दिया जाये। कोई पुराना सदस्य भी आना चाहता है तो no harm. Sir, there is always a scope to learn. One learns till one dies. One continues to learn. Every day he learns something new. It is not the people, who have been elected two, three, four or five times, they are repository of all wisdom-No Sir. Parliamentary practices and/or conventions is something that you continue to learn day after day, minute after minute and second after second. So, somebody new can adhere to better parliamentary conventions sometimes rather than someone who may be two, three, four or five times senior to him. So, Sir, on that issue we are all in agreement.

Second issue was on computers and printers. I had immediately gone to discuss it with the Leader of the House, Ch. Bhupinder Singh Hooda, Hon'ble Chief Minister had also called the Hon'ble Finance Minister and he has instructed me to say on behaf of the Government that the Government would provide the same at the earliest opportunity.

Mr. Speaker : Do you have some time frame, please ?

Shri Randeep Singh Surejewala : We will try to do it in 60 days because this matter has to go to the High Power Purchase Committee. We will try to do it early. Sir, I am putting an outer limit of 60 days that we will provide computers and printers to the Members just like it has been done in the last Government and last to last Government also. We will also direct the HARTRON like we had done last time that they shall provide the necessary training at the IT Centre on the 9th Floor of the Secretariat and we will give due notice to you and you can then send a letter to the Legislators to go there on the fixed days. We can also shift the venue from there to Vidhan Sabha, if you may so like. You can delve over the issue Sir.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, is it comfortable in Vidhan Sabha or in Secretariat ?

Voices : Haryana Vidhan Sabha.

Mr. Speaker : But no established infrastructure is here.

Shri Randeep Singh Surejewala : Why I have suggested IT Centre? Mr. Ajay Singh also knows that. There is an established infrastructure. So, we do not have to take more rooms from Vidhan Sabha as no spare room is available in the Vidhan Sabha. But in Secretariat, there are more rooms available and we will

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
be able to accommodate everybody. Sir, you can fix the dates on every week and we will make sure that by those particular hours every week, our instructors will be available, HARTRON officials will be available to provide necessary training of all basic programmes, operations, internet, intranet, State Wide Area Network. We have already set up the State Level Data etc., whatever the new IT avenues that we are creating for the people of Haryana. For the first time, this Government has set up a State Wide Area Network. We have already tendered the State Level Data Centre so that it is never lost. For generations to come, it should remain. Although, we will provide inputs to the Legislators so that they can train their own constituents as also their party people in the process. Sir, the third thing that was raised by Shri Barshami ji was regarding Visas and Passports and by Shri Dhantori regarding issuing of diplomatic passports. Sir, let me first come to Dhantori's suggestion. Diplomatic passports - they are governed by the regulations of Government of India. Sir, we will request if this suggestion is acceptable. Members of Parliament and Union Ministers are issued diplomatic passports. Your goodself may write to the External Affairs Ministry on behalf of this House requesting them to consider issuing diplomatic passports to the Legislators. Government is in agreement on this issue.

Mr. Speaker : A letter may be drafted on this issue.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I will assist the Vidhan Sabha in drafting the necessary letter.

Mr. Speaker : Before you do that, I want to know something. Do other Assemblies, Members have this diplomatic passport ?

Shri Randeep Singh Surjewala : No, Sir. It is not given anywhere across the country. That is a fact.

Mr. Speaker : Then why they will give you?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, that's why a suggestion has come. A reference can be made. Ultimately, it is for the Government of India to decide that. They will not give diplomtic passports to the Legislators of Haryana alone, they will have to give across the nation. So, that is a policy issue. Government of India will have to decide it.

Mr. Speaker : Another suggestion was that if a Member of Vidhan Sabha wants to have a passport made for him, do you have any Protocol Officer who can help him so that the Member of the Vidhan Sabha does not stand in the queue of Regional Passport Office and some protocol arrangements be made by him.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I am coming to that. Barshami Ji's suggestion was regarding granting of visas to Legislators and the second was regarding issuing of passports. Your goodself has also pointed out, the suggestion whether we can have a Protocol Officer to assist the Members? Sir, I would request your goodself to look into this issue. I am sure you can designate one or two members of your staff for specifically for this purpose that when a Legislator

comes, they will help him in filling up the forms. They can go and submit the forms and they can go to pursue the same personally etc. etc. The process of applying a passport and all information with regard to this is available now online. A small cell of one or two people can be created by the Vidhan Sabha. They can pursue regarding visas. Sir, I want to respectfully say that grant or non-grant of visa is a perogative of a particular Government of a country. We have no say in the matter. If a Legislator comes to your goodself, you can send a recommendatory letter in this regard.

Mr. Speaker : They do not accept it.

Shri Randeep Singh Surjewala : Normally, they do not accept letters. Although, the Hon'ble Chief Minister has pointed out that when recommendations go in certain countries, they are treated as interference by political people and the visa is rejected on that ground. So, I will say that is something, that is not within the domain of either Government of India or of this House because it is another country which decides.

Mr. Speaker : However, if any Member requires a letter which can facilitate him a visa then he can come to me.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रॉब्लम आती है। जब आप वीजा के लिये जाते हैं तो वहां पर कई बार आपसे विधान सभा की एन.ओ.सी. मांगते हैं। वीजा देना या न देना तो एम्बैसी की जिम्मेवारी है लेकिन अगर हम यहीं विधान सभा से इनीशिएट करके यहां से ही पेपर पूरे करके वहां पर जाएं तो यह ज्यादा ठीक रहेगा।

Mr. Speaker : I will have to see whether one is going to official visit or private visit.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, प्राईवेटली जाएं या ऑफिशिएली जाएं वह अलग बात है।

Shri Randeep Singh Surjewala : I can safely tell you. I have travelled abroad on government and private visits many times.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कई बार विदेश में गया हूं।

Shri Randeep Singh Surjewala : So, I do not think so that ever NOC is required. Some countries insist upon one information i.e. whether any criminal case is pending against you in the country to a citizenship which you hold. Some visa applications do have that column. So, on that point of time, some NOCs are concerned. I would request that as it is a healthy discussion, let's not get into that debate.

Mr. Speaker : Sir, if anytime, anybody comes for help, we will extend help to him.

Shri Randeep Singh Surjewala : Another suggestion that has come is regarding adequate notice of Bills should be given.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the time of the Sitting of the House be extended by 10 minutes more?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for another 10 minutes.

विधायकों को सुविधाएं देने सम्बन्धी मामला (पुनरारम्भण)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, Vidhan Sabha Secretariat will ensure and I can assure that reasonable notice, as has been suggested, shall be given to the Members and will be circulated well-in-advance so that Members can be well-aware of the contents etc. of the Bills. As far as amendments go, sometimes in course of discussion, an amendment is suggested by a Member, I remember last to last time, Shri Ajay Singh Ji had suggested some thing, and a small amendment was admitted by the Government. So, sometimes they are made on the floor of the House on the suggestion of one or the other Hon'ble Member. So, qua amendment, there cannot be an advance notice which comes out of discussion. But Bills or any amending Bills will be circulated well-in-time. Another suggestion that came was regarding MLAs' Hostel facilities. In this regard, Hon'ble Chief Minister has already directed me as a Minister of PWD (B&R) and your goodself has also spoken to me that we need to create the amenities better and we are looking at. The difficulty is that the building relates to the Union Territory of India. They do not permit us any structural alteration whatsoever is. We have gone to them twice and thrice, they have rejected. Even in this Vidhan Sabha, Mr. Arora as a Speaker, Mr. Kadian as a Speaker and Mr. Chattha as a Speaker, they all tried, but the structural alteration is not permissible.

Mr. Speaker : What about inside the rooms?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, we cannot touch the structure of exterior but inside the rooms we can. We cannot touch the exterior structure. MLAs' Hostel was constructed in a fashion that it requires structural alterations now because the time has changed and about 30-40 years have passed. Now, there are many amendments required to be done. We are pursuing that matter. As far as whatever interior are concerned, I am talking one is structural alteration and other is interior. About interiors, we will try and do as per the suggestions you will give. A committee can be constituted under your leadership for that purpose and necessary alterations we will do. One suggestion, however, I will give as Smt. Sumita Singh has pointed out, if we are going to make staff stay in the rooms then Members who are staying in adjoining rooms are inconvenienced many times. Sir, we received complaints many times. We overlook them. There are sometimes brawls of various nature that takes place there and one MLA or the other has been inconvenienced there. कई बार विधायकों की चाहे वे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों

शिकायत आई है कि अमुक पड़ौसी के कमरे में कुछ अवांछित व्यक्ति रह रहे थे और वह कमरा किसी माननीय विधायक के नाम से बुक था। इसलिये सैल्फ डिसिप्लिन हमें भी सबको रखना पड़ेगा। हम या तो कमरा ही ना लें और अगर लें तो उसमें स्वयं रहें otherwise, during the Vidhan Sabha Session, if I am staying in one room alongwith with my wife, with my daughter, with my son and children and in another room someone else is staying, if they are quietly staying, it is one issue, but if they are interfering with my privacy, perhaps it is not a fair thing. Members have also to see to it. It will come to the staff arrangement also. Their staff should not stay in their rooms because then every other Member feels inconvenienced.

श्री अभय सिंह चौटाला : उसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि आपसे जैसा कहा कि था तो कमरा ना लें और अगर ले तों खुद रहें। ऐक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारे हल्के का कोई आदमी बीमार हो गया और उसे चण्डीगढ़ में पी.जी.आई. में इलाज के लिए लेकर आएं तो साथ में जो लोग आते हैं उनकी कोशिश रहती है कि उनके लिए ठहरने की व्यवस्था हो जाए ताकि वे साथ आए व्यक्ति का ठीक ढंग से इलाज करा सकें तो उन लोगों को इस बात से भी दिक्कत होगी। यह बात ठीक है कि किसी एम.एल.ए. को आब्जैक्शन हो सकता है लेकिन एम.एल.ए. की भी मजबूरी है। उसके हल्के के आदमी आएंगे तो वह उन्हें कहां ठहराएगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई साथी नहीं होगा जिसके पास इलाके का और इलाके से बाहर का कोई बीमार व्यक्ति नहीं आता होगा। हमसे सब उम्मीद करते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। What I was referring was something else. I did not want to use those words. Abhay Singh Ji, sometimes there are various other kinds of elements who come and stay there. एक दो बार हमारे पास परिवारों की शिकायतें आई। किसी विधायक की पत्नी वहां थी और उस की शिकायत आई, किसी विधायक की बेटियां वहां थी उन्होंने मुझे फोन किया। हमने ये कोशिश की कि इस प्रकार की कोई बात ना हो। क्योंकि हम सदन में है इसीलिए I only told you very very broadly and in general terms that there was a complaint in this regard.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अगर स्टाफ वाला भी हो जाये तो काफी हद तक समस्या हल हो जायेगी।

Shri Randeep Singh Surjewala : Regarding arrangement of staying of staff, I request you, Sir, we have added some MLA flats. This Government, Hon'ble Chief Minister personally intervened and went to the Administrator of Union Territory in this regard. कुछ नये एम.एल.एज. फ्लैट्स का कॉम्पलैक्स बनना था वह तो हमने बना लिया है। इसके अलावा और जगह भी वहां पर है। हम इसको भी परश्यू कर रहे हैं। Sir, a letter from you to the Administrator of Union Territory will also help us in this regard. कार्बूजिए के प्लान की वजह से यहां वर्टीकल्ज में भी जाने की समस्या है। अगर ऐसा ना हो तो एक ऊंची बिल्डिंग बना दी जाए, उसमें सारे एम.एल.एज. एडजैस्ट हो जायेंगे।

Mr. Speaker : In that case, is it Governor of Punjab ?

Shri Randeep Singh Surjewala : That is correct, Sir. एक से अधिक बार हमने तो रिक्वेस्ट भेज रखी है और हम परश्यू भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यू.टी. के एडमिनिस्ट्रेटर से मिल कर आये हैं। मैं भी उनसे दो बार इस प्रार्थना के साथ मिलकर आया हूं कि आप हमें सैक्टर 3 में ही जमीन न देकर किसी दूसरे सैक्टर में दे दें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि इसी सैक्टर 3 में जगह दें चाहे आप हमें सैक्टर 44 में जगह दे दें। हम तो वहां पर नये एम.एल.एज. फ्लैट्स बना लेगें.

Mr. Speaker : Why not in Haryana somewhere in Panchkula or in MDC ?

Shri Randeep Singh Surjewala : On that the opinion of the Members has been consistent. I have told to each and every Member in this regard and they always refused it. If the House is agreed on this, we can do this. But they always refuse and they always say that नहीं पंचकूला में नहीं यहीं बनाईये। कई बार एम.एल.एज. से चर्चा हुई। अगर हाउस एग्रीड है तो हम पंचकूला में बना देंगे।

श्री अशोर कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, पंचकूला में मिनिस्टर ही नहीं जाते एम.एल.एज. कहां जायेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मैं यही बात कह रहा हूँ। हमारे जो साथी विधायकगण हैं वे इस बात के लिए मानसिक तौर से तैयार नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि हमें चण्डीगढ़ में ही एम.एल.एज. फ्लैट्स चाहिएं। हमने इस बारे में परश्यू किया है। स्पीकर सर, विधानसभा की फीलिंग्ज को कन्वे करते हुए आपकी तरफ से भी यू.टी. एडमिनिस्ट्रेटर को एक पत्र जायेगा उसके बाद मुझे विश्वास है कि एडमिनिस्ट्रेटर, यू.टी. चण्डीगढ़ उसको कन्सीडर करेंगे। पैसे की तंगी नहीं है। एम.एल.एज. फ्लैट्स नये बनाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दे रखा है ताकि हर एक एम.एल.ए. को फ्लैट मिल सके जोकि विधायकों को नहीं मिल पाता। हम इसके लिये तैयार हैं। सर, एक सुझाव यह भी आया था जोकि श्री रामकिशन जी ने दिया था कि नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा में जगह नहीं है। मैं सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपने आपको इस बात के लिए जोड़ता हूं। सर, नमाज पढ़ने के लिये बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटी सी जगह की आवश्यकता है। सर, एक छोटा सा एरिया आप एलोकेट कर दें जहां पर जो भी साथी विधायकगण नमाज पढ़ना चाहें पढ़ लें इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है।

Mr. Speaker : We will identify such a place.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, स्टाफ का जो एरेंजमैंट है वह भी इस पर निर्भर है कि एम.एल.एज. फ्लैट्स की भी जगह मिले और स्टाफ के लिये भी हमें जगह मिले। विधान सभा सैक्रीटेरिएट जो है इसमें विधानसभा स्टाफ को बैठने की जगह भी तंग है। हमने पंजाब से बार-बार रिक्वैस्ट की है कि उनके चार कमरे जो नीचे खाली हैं वे हमें दे दें लेकिन वे हमें नहीं देते। सर, मैं और चट्ठा साहब और मैं और कादियान साहब जब ये दोनों विधान सभा के स्पीकर रहे थे तब तीन बार पर्सनली पंजाब के स्पीकर साहब से मिलकर आये थे उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आये। हमने उनसे अनुरोध किया है कि जिन कमरों को आपने ताला लगा रखा है और वहां कबाड़ पड़ा हुआ है, वे हमें दे दें तो हम अपने कुछ मिनिस्टर्ज और कुछ स्टाफ के लिए और जगह क्रिएट कर सकेंगे। परन्तु वह रिक्वैस्ट हमारी अभी वहां पर विचाराधीन है। उन्होंने हमारी रिक्वैस्ट न तो रिजैक्ट की और न ही असैप्ट की। स्पीकर सर,

स्टाफ के लिए भी मैं यही कह सकता हूं कि आप भी पत्र लिखें और हम भी पर्सनली जाकर परश्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं पत्र लिखवाऊंगा और मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर, यू.टी. से मिलूंगा कि हमें एक बिल्डिंग एम.एल.एज. फ्लैट्स के नजदीक स्टाफ के लिए और पार्किंग के लिए दोनों के लिए ही परमिट करें। सर, आखिरी सुझाव जब आया था तो आपने उस सुझाव को विशेष तौर से नोट करने के लिए कहा था कि जो आफिसर्ज हैं उनको जब विधायकगण पत्र लिखें तो उसका जवाब आफिसर्ज को देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इस बारे में चीफ सैक्रेटरी के माध्यम से लिखकर निर्देश इश्यू किए थे। We will again issue the instructions in this regard. I can assure you on behalf of the Government that the Chief Secretary will write to all the Officers that whenever an MLA writes a letter then a proper reply must be given as expeditiously as possible and as quickly as possible to the learned Legislator. On that there is no issue.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, is it the pleasure of the House that the time of the Sitting of the House be extended by 10 minutes.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for another 10 minutes.

गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Agriculture Minister will give reply to the non-official resolution moved by Shri Ram Pal Majra, MLA.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Sir, I have already spoken about the measures which have been taken by the Government in this regard. Some issues were also raised on irrigation for which the Irrigation Minister has replied to them.

Mr. Speaker : Alright.

Sardar Parmvir Singh : Thank you, Sir.

Mr. Speaker : Question is—

> That the House recommends to the State Government to take appropriate steps to introduce Underground Water Control and Regulation Bill so that exploitation of underground water can be stopped/regulated.

The motion was carried unanimously.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House stands adjourned till 10.30 A.M. tomorrow.

*14.41 hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.30 A.M. on Friday, the 11th March, 2011.)

48779—H.V.S.—H.G.P., Chd.